द्वितीय माला, खण्ड २३—अंक १

४ दिसम्बर, १९५८ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(6th Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

278 (AI) L.S.D.

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ५६० से ५६३ और ५६५ से ५७४ .	१४४१—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ और ५७५ से ६०३ . . .	१४६४—७४
अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ६६५ और ६६७ . .	१४७४—१५०६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	१५०६—११
राज्य-सभा से संदेश	१५११-१२
राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक—	
सभा-पटल पर रखा गया . . .	१५१२
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली के बारे में याचिका.	१५१२
निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव	१५१२—४६
श्री रामजी वर्मा .	१५१२—१६
श्री श्री अ० डांगे . .	१५१७—१६
श्री सोमानी . . .	१५१६—२१
श्री अ० चं० गुह . . .	१५२१—२२
श्री महन्ती	१५२२-२३
श्री रंगा	१५२३-२४
श्री बिमल घोष	१५२४-२५
श्री मनुभाई शाह	१५२५—३०
श्री च० द० पाण्डे	१५३०—३२
श्री पु० र० पटेल	१५३२-३३
श्री ओझा	१५३३—३५
कुमारी मो० वेदकुमारी . . .	१५३५-३६
श्री ब्रजराज सिंह	१५३६-४०
श्री रामेश्वर टांटिया	१५४०-४१
श्री अजित सिंह सरहदी . . .	१५४१-४२
श्री तंगामणि	१५४२-४३
श्री रघुनाथ सिंह . . .	१५४४—४६
श्री लाल बहादुर शास्त्री	१५४६
दैनिक संक्षेपिका	१५४७—५४

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ४ दिसम्बर १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मुक्त व्यापार क्षेत्र[1]

+

†*५६०. श्री राम कृष्ण :
श्री वि० च० शुक्ल :
श्री दामानी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री खीनजी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन पर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की योजना की जांच और उस पर विचार अब पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री राम कृष्ण : कांडला के विकास आयुक्त ने जो योजना दी है उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†श्री राज बहादुर : मुख्य बात यह है कि आध वर्गमील का एक क्षेत्र इस प्रयोजन के लिये पृथक कर दिया जाय। इसकी लागत ५२.२२ लाख रुपये कूती गयी है और इसकी देख रेख आदि पर ५.६१ लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें रक्षा और प्रहरी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिये सीमा-शुल्क विभाग को दिये जाने वाले १.५ लाख रुपये भी शामिल हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

1Free Trade Zone

†श्री राम कृष्ण : यदि इस योजना को क्रियान्वित किया गया तो उसका सीमा-शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†श्री राज बहादुर: मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के पीछे मुख्य प्रयोजन यह है कि उस क्षेत्र में किसी भी माल या व्यापारिक-वस्तु पर सीमा-शुल्क नहीं लगेगा । इस कारण इसे सीमा-शुल्क के क्षेत्राधिकार से बाहर का क्षेत्र माना जायेगा ।

†अध्यक्ष महोदय: कितना घाटा होगा ?

†श्री राज बहादुर: घाटा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ।

†श्री दामानी: क्या भारतीय वैदेशिक व्यापार परिषद् ने बम्बई पत्तन को भी मुक्त क्षेत्र बनाने की मांग की है ?

†श्री राज बहादुर : मुझे तो उसका पता नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों की राय यही रही है कि ऐसा मुक्त-व्यापार क्षेत्र ऐसे पत्तन पर होना चाहिये जहां काफी बड़ी जगह उपलब्ध हो और घनी बसी बस्तियों से दूर हो ।

†श्री रघुनाथ सिंह : इस योजना के बारे में स्थानीय जनता का भाव क्या है ?

†श्री राज बहादुर: निश्चय ही जनता को इसके सम्बन्ध में खासा उत्साह दिखाना चाहिये क्योंकि इससे निश्चय ही उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और बेरोजगारी में भी कुछ हद तक कमी होगी ।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या सिंध-निगम इस योजना का विरोध कर रहा है ?

†श्री राज बहादुर: मुझे पता नहीं है । पर मेरे ख्याल से उन्हें विरोध नहीं करना चाहिये ।

†श्री जगन्नाथ राव : एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि सीमा-शुल्क लगाया जायेगा ।

†श्री राज बहादुर : यह उस हालत में लगाया जा सकता है जब मुक्त व्यापार क्षेत्र में लाया गया माल वहां से देश के भीतर लाया जाये । उससे पहले उस पर नहीं लगेगा ।

†श्री जगन्नाथ राव: अन्यथा इससे जनता का क्या लाभ होगा ?

†श्री राज बहादुर : कच्चे माल को जमा करने, श्रेणी भाजित करने, छांटने, तैयार करने, निर्माण और प्रदर्शन—इन सभी कार्यों से स्थानीय औद्योगिक गतिविधि को बल मिलता है ।

†श्री दामानी: क्या सरकार को पता है कि हाल ही में भारतीय वैदेशिक-व्यापार परिषद् ने बम्बई पत्तन के निकट इस प्रयोजन के लिये भूमि लेने के लिये विज्ञापन किया है । यदि हां, तो इसके पीछे क्या बात है ?

†श्री राज बहादुर : यह जानकारी मुझे अभी माननीय सदस्य से मिल रही है । लेकिन माननीय सदस्य जिस प्रस्ताव का जिक्र कर रहे हैं उससे इसका बहुत थोड़ा सम्बन्ध है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस समय कांडला पत्तन का कितना उपयोग किया जाता है ? क्या इस कार्यवाही के फलस्वरूप पत्तन की अवस्था में काफी सुधार नहीं हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†श्री राज बहादुर : १२ लाख से कुछ अधिक की अधिष्ठापित क्षमता में से पिछले वर्ष मेरे ख्याल से यह ८ लाख टन था। स्पष्ट है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने पर हम पत्तन की सुविधाओं का अधिक अच्छा उपयोग कर सकेंगे।

अमरीकी लिबर्टी पोत

†*५६१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २५ अगस्त १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करें कि अमरीकी लिबर्टी पोतों की खरीद के बारे में और कितनी प्रगति हुई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : इन पोतों की खरीद के बारे में और आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। जिस पिछले प्रश्न का जिक्र किया गया है उसके उत्तर में मैं बता चुका हूं कि लिबर्टी पोतों की मुक्त बाजार-मूल्य इस समय इतना मन्दा है कि मॉथ-बॉल लिबर्टी पोतों को प्राप्त करने का प्रयास करने में कुछ भी लाभ नहीं है। यदि, इन पोतों को देने के लिये अधिकार देने वाला विधान, जो अमरीका सरकार के विचाराधीन है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें आकर्षक शर्तों पर बेचा जायगा पास हुआ तो वह जब भी पास होगा इस संबंध में आगे कार्यवाही की जायेगी।

†श्री दी० चं० शर्मा : यदि इन पोतों की खरीद से संबंधित वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो माल ढोने के प्रयोजन के लिये जहाज प्राप्त करने के लिये मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है।

†श्री राज बहादुर: इस संबंध में कुछ मुख्य-मुख्य बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये। पहली बात तो यह है कि अमरीका सरकार को आवश्यक विधान बनाना चाहिये, जो अभी नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि खुले बाजार में लिबर्टी पोतों की कीमत काफी गिर गयी है। इसलिये यह उस कीमत से कहीं कम कीमत पर प्राप्त किये जा सकते हैं जिसका अमरीकी सरकार ने इस प्रस्ताविक विधान में उल्लेख किया है। तीसरे, अमरीका सरकार की मार्फत खरीदे गये लिबर्टी पोतों पर यह प्रतिबंध है कि वह केवल तटवर्ती क्षेत्र में चलाये जा सकते हैं, जबकि खुले बाजार से खरीदे गये पोतों के बारे में यह प्रतिबंध नहीं रहेगा।

†श्री तंगामणि : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लिबर्टी पोत बहुत धीरे चलते हैं, और मौजूदा बाजार का रुख खरीददार के पक्ष में है, क्या सरकार लिबर्टी पोतों की खरीद का इरादा छोड़ने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†श्री राज बहादुर: मैं 'इरादा छोड़ने' की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें विधान बनने के बाद की स्थिति का ध्यान रखते हुए इस प्रश्न पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या यह सच है कि इन पोतों का संचालन-व्यय इतना अधिक है कि ये भारत के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभ-प्रद नहीं सिद्ध होंगे और अब उन्हें खरीदना बेकार है ?

†श्री राज बहादुर: मैं समझता हूं कि नौवहन प्रतिष्ठानों का भी यही अनुमान है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

+

*†५६२. { श्री राम कृष्ण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल को कैंसर विंग के निर्माण के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) सफदरजंग अस्पताल में एक कैंसर विंग के निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। ब्यौरेवार योजनायें और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। निर्माण कार्य मार्च, १९५९ तक आरम्भ हो जाने की आशा है ।

(ख) इस कार्य की लागत ८.३९ लाख रुपये कूतीं गयीं है ।

†श्री रामकृष्ण : क्या यह अस्पताल द्वितीय योजना के भीतर चालू हो जायगा।

†श्री करमरकर: अस्पताल तो है ही। कैन्सर वार्ड १९५९ की मार्च से कार्य आरम्भ कर देगा ।

†श्री राम कृष्ण : इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि व्यय की गयी है ?

†श्री करमरकर : मेरे पास कैन्सर वार्ड के संबंध में अलग आंकड़े नहीं हैं। इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या किये गये खर्च में आधुनिकतम उपकरणों का खर्च भीं शामिल है।

†श्री करमरकर: जी हां, मेरे ख्याल से इस में शामिल हीं होना चाहिये —बशर्ते कि रुपया उपलब्ध हो ।

†श्री जगन्नाथ राव : क्या सरकार की नीति देश भर के अस्पतालों के कैन्सर विंग में सुधार करने कीं है ?

†श्री करमरकर : जी हां। यह "नहीं" तो हो ही नहीं सकती।

†श्री बर्मन : इसका शिलान्यास कब हुआ था ? निर्माण में विलम्ब क्यों हुआ ?

†श्री करमरकर : कैन्सर ब्लाक का शिलान्यास श्रीं सी० डी० देशमुख ने ५ मई, १९५६ को किया था। १९५७-५८ के लिये बजट-उपबन्ध न होने के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। अब बजट उपबन्ध है ।

†श्री प्रभात कार : क्या निर्माण का ठेका किसी गैर-सरकारी फर्म को दिया गया है या केन्द्रींय लोक-निर्माण विभाग ने कार्य आरम्भ किया है ?

†श्री करमरकर : यह बात मंजूरी के बाद उठेगी ?

†श्री जाधव : दिल्ली में कितने व्यक्ति कैन्सर से पीड़ित होते हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री करमरकर : मुझे यह संख्या जमा करनी पड़ेगी क्योंकि इसके विभिन्न अस्पताल हैं ।

†श्री दासप्पा : मंजूरी प्राप्त करने से पहले ही शिलान्यास क्यों कर लिया गया ? क्या जबर्दस्ती मजूरी लेने के लिये यह तरीका अपनाया गया था ?

†श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र को इस संबंध में अधिक तजुर्बा है ।

†श्री रंगा : मैं आपत्ति उठाना चाहता हूं । प्रश्न मेरे माननीय मित्र श्री दासप्पा ने पूछा है और मंत्री महोदय केवल व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र कर बात खत्म कर देते हैं । क्या किसी प्रश्न के उत्तर देने का यही ढंग है ?

†श्री करमरकर: : मेरे माननीय मित्र को श्री दासप्पा से भी अधिक अनुभव है ।

†श्री रंगा: प्रश्न काल में इस प्रकार की मखौल पर मुझे आपत्ति है । मैंने अपना प्रश्न मंत्री महोदय से नहीं पूछा था । वह आपको संबोधन न कर सीधे मुझे उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं ।

†श्री करमरकर : मैं बात को और स्पष्ट कर दूं । आप इस बात को शायद हम से भी अच्छी तरह जानते हैं कि कभी-कभी शिलान्यास वादा कराने के ख्याल से भी करा लिया जाता है । संभवत: श्री देशमुख के वित्त मंत्री होने की वजह से इससे लाभ हो गया होता । जिन लोगों ने उन से शिलान्यास कराया हो सकता है यह बात उनके मन में हो । कुछ भी हो, मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इरादा नेक ही था ।

†अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि इरादा मखौल का था । वास्तव में, थोड़ा हंसी मजाक अच्छा हीं रहता है ।

पाकिस्तान पर बकाया राशि

+

†*५६३. { श्री सुबोध हंसदा:
श्री स० च० सामन्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के लिये पाकिस्तान को अंशदान के अंश के रूप में भारत ने जो बहुत बड़ी राशि दी थी वह पाकिस्तान पर बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या अब तक कुछ राशि वसूल हुई है, और यदि हां, तो कितनी ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन: (क) पाकिस्तान से १५,६३५ डालर की राशि मिलने वाली है ।

(ख) और (ग). अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के महा मंत्री की मार्फत कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा**: हमने पाकिस्तान का अंश क्यों दिया ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं कह चुका हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के महा मंत्री की मार्फत इस मामले में कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : पाकिस्तान के इस अंश का भुगतान भारत ने कब किया और क्या उसके बाद से पाकिस्तान से कुछ लिखा-पढ़ी हो रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : अविभक्त भारत के अंश का भुगतान जुलाई, १९४७ में किया गया था और उसके फौरन बाद ही भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के लिये अगस्त, १९४७ से जून, १९४८ के अन्त तक की अवधि के लिये पाकिस्तान के सानुपातिक अंश का दावा कर दिया था। तब से ही लिखा पढ़ी चल रही है और कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : आरम्भ में ही भारत ने पाकिस्तान के इस अंश का भुगतान किया था। इतना समय कैसे निकल गया और पाकिस्तान से अब तक कोई बात तय क्यों नहीं हुई ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं बता चुका हूं कि यह रुपया जुलाई में दिया गया था और इसका हिसाब अगस्त में पाकिस्तान का जन्म होने के बाद होना था। उसके बाद से, मैं बता चुका हूं, कि पाकिस्तान १५,६३५ डालर का अपना अंश देने के लिये राजी हो गया है।

†**श्री प्रभात कार** : ग्यारह वर्ष।

†**श्री मुहीउद्दीन** : प्रश्न सिर्फ यही रह जाता है कि इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये कौनसा तरीका अपनाया जाना है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : स्पष्ट है कि लिखा-पढ़ी का कुछ फल नहीं निकला है क्योंकि लिखा पढ़ी तो पिछले बारह वर्षों से चल रही है। इस मसले को तय करने के लिये मंत्रालय दूसरे कौन से तरीके अपनाने वाली है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं नहीं जानता कि कोई दूसरा तरीका भी है। अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संघ तो है ही और सीधे भी बातचीत की जा सकती है।

†**श्री आसर** : क्या सरकार इस राशि को वसूल करने के लिये कोई अवधि निर्धारित करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके पश्चात् क्या होगा ? अगला प्रश्न।

खाद्यान्नों का आयात

†*५६५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के आयात के लिये सितम्बर, १९५८ के बाद से कौन-से नये करार हुये हैं ; और

(ख) क्या इन्हें रखने के लिये पर्याप्त संग्रह व्यवस्था हो गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) (१) गेहूं की खरीद के लिये कनाडा सरकार से २४ सितम्बर, १९५८ को हुआ करार।

(२) गेहूं, मक्का और चरी के सम्भरण के लिये अमरीका सरकार से २६ सितम्बर, १९५८ को हुआ करार।

(ख) जी हां।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : रबी की फसल कैसी होने की सम्भावना है और क्या रबी की फसल अच्छी होने की सम्भावना का आयात सम्बन्धी वादों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : रबी की फसल के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। हां, बुवाई सफल ढंग से हो गई है।

†**श्री आसर** : कनाडा ने जो अनाज भेंट के रूप में दिया है क्या वह पूरा का पूरा आ गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह प्रश्न अस्थगित भुगतान के आधार पर खाद्यान्नों की खरीद के करारों के विषय में है। जहां तक इस दूसरी बात का प्रश्न है, कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा ने १९५८ में हमें लगभग १२७,००० टन गेहूं उपलब्ध कर दिया है।

†**श्री महन्ती** : कनाडा और अमरीका से कुल कितने गेहूं का आयात किया जायेगा ? उसे रखने के लिये कितने भांडारों का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जहां तक उसे रखने का सवाल है, मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। हमने करीब १५ लाख टन अनाज रखने का प्रबन्ध कर लिया है। यह ठीक है कि इस सारी क्षमता का उपयोग अभी नहीं हो पायेगा और इसमें से कुछ को वापस दे देना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में अब आगे और कुछ कठिनाई होने की हमें कोई आशा नहीं है।

†**श्री तिरुमल राव** : अमरीका और कनाडा से कितना-कितना अनाज तय हुआ है ?

†**श्री अ० म० थामस** : कुल २३८० लाख डालर के अनाज में से हमें २८ लाख टन गेहूं, एक लाख टन मक्का और दो लाख टन चरी मिलेगी।

†**श्री त्यागी** : इस वर्ष कितने मूल्य के आयात किये गये या किये जाने वाले हैं और विदेशों से दान और भिक्षा के रूप में कितने मूल्य के अनाज आये हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय सदस्य का इसे दान या भिक्षा कहना ठीक नहीं है। हम कोलम्बो योजना और पी० एल० ४८० के अधीन आयात करते हैं और सामान्य रूप से खरीदारी भी करते हैं। कुछ देशों ने कोलम्बो योजना के अधीन हमारी सहायता की है पर इसे दान या भिक्षा नहीं कहा जा सकता।

†**श्री त्यागी** : इस वर्ष कुल कितने मूल्य के अनाज का आयात किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कभी-कभी अपने परिहास भाव की लहर में ही बह जाते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम इसका असर किस पर पड़ता है। यह ठीक है कि यह माननीय सदस्य, जो पहले मंत्री थें, जानते हैं कि क्या कठिनाइयां होती हैं। यदि हम विदेशों से सहायता

---

†मूल अंग्रेजी में

मांगें और बाद में इस ढंग से कहें तो हम स्वयं अपने को दोषी सिद्ध करते हैं। यह कह कर कि हम भीख मांग रहे हैं हम और किसी को दोषी नहीं सिद्ध करते। मुझे पता नहीं कि इससे क्या लाभ होता है। माननीय सदस्यों को जल्दीबाजी में वैसी बात नहीं कहनी चाहिये जो हमारे आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाये।

†**श्री त्यागी** : भिखारियों के मन में आत्मसम्मान का भाव नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य के मन में आत्मसम्मान का भाव न हो तो कम से कम सारे देश और लोक-सभा के विषय में उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

†**श्री त्यागी** : कम से कम उसकी कीमत तो बता दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसकी कीमत की बात माननीय सदस्य की दूसरी बात के पीछे छिप गई है। उन्होंने उसके साथ अपनी कुछ बातें भी जोड़ दी हैं।

†**श्री त्यागी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल कितने मूल्य का अनाज खरीदा जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अपनी बात उसमें जोड़ने के स्थान पर सीधा प्रश्न पूछना चाहिये था। मैं नहीं कह सकता कि यह हमारे देश के हित में अच्छा होगा भी या नहीं। चाहे कोई भी क्यों न हो, किसी को भी प्रश्न-काल का उपयोग आरोप लगाने के लिये नहीं करना चाहिये। वह जो कुछ भी कह चुके हैं, उसे उन्हें वापस ले लेना चाहिये।

†**श्री त्यागी** : मैं अपनी बात वापस लेता हूं। कुल कितनी कीमत के अनाज खरीदे गये हैं और कितना धन दिया गया है ? कुल कितने मूल्य के अनाज भेंट स्वरूप प्राप्त हुये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: कनाडा के गेहूं की कीमत ८८ लाख डालर है और अमरीका के गेहूं, मक्का और चरी की कीमत २३८८ लाख डालर होगी।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या किसी अन्य देश से चावल के आयात के लिये कोई करार हुआ है और १९५८–५९ में कुल कितना आयात हुआ है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : बर्मा से चावल की खरीद का करार चल रहा है। इस करार के अधीन हम १९५९ में ३.५ लाख टन चावल का आयात कर सकते हैं।

†**श्री महन्ती** : प्रश्न का भाग (ख) इस बात से सम्बन्धित है कि क्या ये अनाज रखने के लिये उचित संख्या में भांडारों का प्रबन्ध किया गया है। मंत्री महोदय ने इसके उत्तर में 'हां' कहा है। लेकिन वह इस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाये है कि सभी प्रकार के अनाजों के लिये कितने भांडारों का प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : १३ लाख टन का। इसके अलावा हाल ही में हमने कुछ भांडार छोड़ दिये हैं, हम उन्हें फिर से ले सकते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : राज्य-सरकारों और केन्द्रीय सरकार के पास इस समय कितना स्टाक है ? इस वर्ष में कितना आयात होने की सम्भावना है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं यह आंकड़े नहीं बता सकता। यह बताना लोकहित में नहीं है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†श्री वासुदेवन् नायर : मंत्री महोदय ने कहा है कि हम बर्मा से ३ लाख टन चावल मंगा सकते हैं। क्या इस वर्ष बर्मा से चावल का आयात करने के सम्बन्ध में कुछ ठोस प्रस्ताव है ?

†श्री अ० प्र० जैन : ३½ लाख टन मंगा सकते हैं। मैंने कहा था कि करार चल रहा है।

†श्री वासुदेवन् नायर : क्या हम आयात करेंगे ?

†श्री अ० प्र० जैन : बातचीत चल रही है।

ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल

*५६६. { **श्री पद्म देव :**
श्री राम कृष्ण : }

क्या रेलवे मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाने की योजना के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह योजना कब पूरी होगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी): (क) पायों की बुनियाद[1] डालने के सम्बन्ध में सहायक काम शुरू किये जा चुके हैं, खान से पत्थर लाने के लिये साईडिंग बना दी गई है, बेस कैम्प और कंस्ट्रक्शन वर्कशाप तैयार हैं। बुनियाद के कुएं गलाने[2] का काम शुरू किया जा रहा है।

गर्डर बनाने और उनकी सप्लाई के लिये संसार के विभिन्न देशों से टेंडर मांगे गये हैं।

(ख) आशा है कि यह पुल १९६२–६३ तक बन कर तैयार हो जायेगा।

†श्री रामकृष्ण : इस पुल पर कुल कितना व्यय होगा ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : लगभग १० करोड़ रुपये।

†श्री बसुमतारी : क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर इस पुल के निर्माण के लिये आसाम सरकार शिलान्यास करने के लिये प्रधान मंत्री को आमंत्रित किया है, और यदि हां, तो क्या तारीख निश्चित की गई है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मुझे पता नहीं।

†श्री रामकृष्ण : इस पुल की कुल लम्बाई कितनी है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : लगभग ४२०० फुट।

†श्रीमती मफीदा अहमद : इस विषय पर एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में रेलवे मंत्री ने पहली दिसम्बर को यह बताया था कि ब्रह्मपुत्र के पुल की बुनियाद और सब-स्ट्रक्चर के निर्माण का ठेका मेसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया है। क्या डिजायन बनाने और उपकरणों के सम्भरण का काम भी इस ठेके में शामिल है, और यदि नहीं, तो डिजायन बनाने और सामान के सम्भरण का काम किसे सौंपा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Well foundations.

[2]Sinking.

†श्री सें० वें० रामस्वामी: बुनियाद के कुएं लगाने का और अन्य काम हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी करेगी। शहतीरें बनाने और उनका सम्भरण करने के ठेके के लिये हमने विश्व भर के देशों से टेंडर मांगे हैं।

†श्रीमती मफीदा अहमद: डिजायन ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी: डिजायन हमारा होगा। यह काम रेलवे इंजीनियर करते हैं।

†श्री जीनचन्द्रन्: क्या यह भारत का सब से लम्बा पुल है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी: जी नहीं। यह सब से लम्बा नहीं है।

†श्रीमती मफीदा अहमद: जहां तक कुशल और अकुशल श्रमिकों का प्रश्न है, क्या इस करार में स्थानीय लोगों का उपयोग करने का कोई विशेष उपबन्ध है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी: सरकार की नीति ही यह है। हम यथासम्भव स्थानीय श्रमिकों और देशी सामान का ही उपयोग करते हैं।

†श्रीमती मफीदा अहमद: यह ठेका मेसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को किस विचार से दिया गया और यह ठेका कुल कितने का था ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): एकमात्र विचार यही था कि देश में यही एकमात्र ऐसी कम्पनी है जिसे इस प्रकार के कार्य का अनुभव है। कोई और कम्पनी नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय: यह ठेका कितने का था ?

†श्री जगजीवन राम: मैं एकाएक नहीं बता सकता। आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं। मैं इसे स्पष्ट कर दूं। हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने गंगा के पुल के लिये हमारा कार्य किया था। गंगा के पुल के निर्माण के समय विश्व भर के देशों से टेंडर मांगे गये थे और यह देखा गया कि हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी के, जो एक देशी कम्पनी है, टेंडर सब से अच्छे थे। इसीलिये ब्रह्मपुत्र के पुल का काम हमने उनको दे दिया ताकि उनके उपकरणों और मशीनों का उपयोग हो जायेगा और काम जल्दी हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजनायें

\+

†*५६७. { श्री तंगामणि:
श्री स० म० बनर्जी:

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटी सिंचाई के लिये उत्तर प्रदेश को ११ करोड़ रुपयों की अतिरिक्त सहायता देने के बारे में तब से कोई निश्चय हुआ है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये ११.२७ करोड़ रुपये की जो अतिरिक्त सहायता मांगी है वह १९५८-५९ से १९६०-६१ तक के तीन वर्षों के सम्बन्ध में है। १९५८-५९ के लिये ११० लाख रुपयों की अतिरिक्त रकम दी गई है,—७० लाख इस मंत्रालय से और ४० लाख सामुदायिक विकास मंत्रालय से। १९५९-६०

---

†मूल अंग्रेजी में

और १९६०-६१ के लिये दी जाने वाली राशियों का निश्चय इन वर्षों की वार्षिक योजनाओं पर चर्चा के समय किया जायेगा ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह राशि मिलने के फलस्वरूप १७१,००० एकड़ अधिक भूमि की सिंचाई करने का लक्ष्य पूरा हो गया है, और यदि नहीं, तो इसके फलस्वरूप कितन एकड़ अधिक भूमि में खेती होने लगी है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** अभी से यह कहना संभव नहीं है कि इस वर्ष का लक्ष्य पूरा हो सकेगा या नहीं। हम समझते हैं कि वे आवंटित से अधिक राशि व्यय कर रहे हैं और इसीलिये हमें आशा है कि वह लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त करेंगे।

†**श्री तंगामणि :** उत्तर प्रदेश ने छोटी सिंचाई योजनाओं और जल-मग्न क्षेत्रों, दोनों के संबंध में ११.२५ करोड़ रुपये मांगे हैं। क्या उनकी कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए इन तीन वर्षों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को ११.२५ करोड़ रुपयों का आवंटन किया जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** अतिरिक्त रुपया तीन मुख्य बातों के लिये मांगा गया था : जलमग्न भूमि और पानी निकालने की व्यवस्था में सुधार की योजनाओं के लिये ; १,००० नलकूपों के चारों ओर पक्के कुओं का विस्तार करने ; और साधारण कुओं और रहट लगाने के लिये।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** इस वर्ष जो सहायता दी गयी है उसका उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार मुख्य सिंचाई योजनाओं में से किस के लिये करेगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** उन्होंने अतिरिक्त रुपया मांगा है और यह पहला ही वर्ष है। हम ने उन्हें छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये १.९६ करोड़ रुपये दिये हैं। उन्होंने अतिरिक्त मांगें की हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वह वार्षिक योजना में दी गयी राशि और अतिरिक्त राशि दोनों का उपयोग कर लेगी।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो छोटी छोटी सिंचाई योजनाएं रक्खी हैं उनका मुख्य स्वरूप क्या है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : अभी जिन ६ आइटम्स के वास्ते १ करोड़ और १० लाख रुपये दिये हैं वे यह हैं :

†नालियां बनाना ; सहकारी नलकूपों को अपने हाथ में ले लेना ; नलकूपों की लाइनिंग ; दक्षिण उत्तर प्रदेश में बंदियां ; पर्वतीय जिलों में कुहुल ; ईंटों के कुएं।

श्री जगदीश अवस्थी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो छोटे छोटे कुएं खुदवाये जायेंगे, उन कुओं के खुदवाने में राज्य सरकार क्या किसानों से भी अनुदान के रूप में कुछ रुपया लेगी, उनका भी कुछ हिस्सा होगा या सरकार उनको खुद खुदवायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : एक कुएं के बनाने के लिए २००० रुपये दिये जायेंगे। २००० रुपये में २५ परसेंट सबसिडी होगी और उस सबसिडी में आधा हमारा हिस्सा है और आधा राज्य सरकार का हिस्सा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसमें कितना निर्माण मज़दूर करेंगे ; क्या श्रमदान या किसानों द्वारा कुछ व्यय पूरा किया जायगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** यह सब ऋण है। हम २००० रुपये ऋण देते हैं।

†**श्री तंगामणि :** उत्तर प्रदेश की सिंचाई क्षमता के कितने अंश का दूसरी योजना में उपयोग किया जा चुका है, और यदि यह लक्ष्य के बराबर न हो तो उसका क्या कारण है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिये ....पहली पंचवर्षीय योजना के पहिले साल में........

†**एक सदस्य :** आप या हिन्दी में उत्तर दें या अंग्रेज़ी में।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्रियों तथा सदस्यों को अवश्य हिन्दी सीखनी चाहिये।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** पहले दो वर्षों में २४ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई है।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** क्या सरकार ने सिंचाई के उद्देश्य के लिये गांवों के पुराने तालाबों की मुरम्मत कराने के लिये कोई आदेश जारी किये हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जी हां। लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत यह योजना भी शामिल है।

सहकारी चीनी कारखाने, आन्ध्र प्रदेश

+

†*५६८. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में चीनी कारखाने बनाने के लिये योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ;

(ख) इसमें से अब तक कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है ; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा के लिये अभी प्रार्थना पत्र लम्बित पड़े हैं ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) यह निश्चय किया गया है कि पूरी मशीनरी बाहर से मंगवाने की बजाये यहां पर तैयार उपकरणों से कारखाना तैयार किया जाये और बाहर से कम से कम मशीनें मंगवाई जायें। यदि हम पूरी मशीनें बाहर से मंगवायें तो चार कारखानों के लिये ३०० करोड़ की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती किन्तु अब केवल १०० करोड़ रुपये की मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तथा (ग). अभी तक कोई राशि नहीं स्वीकृत की गई है। इसलिये ३०० करोड़ अथवा १०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के लिये, जैसा भी कि तय होगा, ही प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जायेगा।

†**श्री नागी रेड्डी** : हमारे देश में मशीनें बनाने में बहुत समय लग जायेगा। चितूर, अमदालाबाल्डी, पुल्लाकोटू और चोदावरम की चारों सोसाइटियों ने आवश्यक पूंजी एकत्रित कर ली है और उधर राज्य सरकार ने भी अपना हिस्सा दे दिया है। इन सब बातों को देखते हुए क्या सरकार इन चारों कारखानों के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रदान करने की कृपा करेगी?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हमने योजना आयोग को शीघ्रता करने के लिये कहा है। किन्तु बदकिस्मती से आजकल विदेशी मुद्रा की तंगी के कारण कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो गई हैं। हम इसके लिये शीघ्रता करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री नागी रेड्डी** : राज्य सरकार ने "१९५८-५९ के लिये प्लान प्रावीजन" नामक एक प्रकाशन निकाला है उसमें यह बताया गया है कि तीन कारखानों के लिये रुपयों में तथा भविष्य में भुगतान चुकाने के आधार पर मशीनरी खरीदने का एक प्रस्ताव हुआ है? क्या सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार है?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी हां। इस प्रकार का एक प्रस्ताव आया है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। मंत्रालय ने कहा है यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे शेष व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का भय हो सकता है।

†**श्री नागी रेड्डी** : जब विदेशी मुद्रा की अनुमति नहीं दी जा रही है तब क्या हम यह समझें कि किसानों ने जो धन जुटाया है वह उनको वापस लौटा दिया जायेगा?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हम यह प्रबन्ध करेंगे कि आवश्यक हिस्से जल्दी से जल्दी मंगवाये जा सकें। इस मशीनरी के निर्माण के लिये हमने एक निर्माता संघ की स्थापना की है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : इन चार कारखानों को आयात लाइसेंस दिये जा चुके हैं क्या इनको मशीनों के लिये आवश्यक पुर्जे व सामान मंगवाने के लिये कोई प्राथमिकता दी जायगी?

†**श्री अ० प्र० जैन** : अभी आयात लाइसेंस नहीं दिये गये हैं।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : दिये गये हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : अभी तक उनको कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इनको आयात लाइसेंस दिये जायेंगे?

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मुझे यह सूचना मिली है कि लाइसेंस दिये जा चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नागी रेड्डी: केवल तीन को लाइसेंस दिये गये हैं मगर किसी को भी विदेशी मुद्रा नही ी गई है।

†अध्यक्ष महोदय : अगर इन कारखानों को विदेशी मुद्रा मिल जाये तो क्या इन्हें सामान मंगवाने के लिये कोई प्राथमिकता ीं जायेगी ?

†श्री अ० प्र० जैन : ग्यारह कारखाने हैं। इनमें से जो प्राथमिकता के अधिकारी होंगे उनको प्राथमिकता दी जायेगी ?

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या सरकार बता सकती है कि यह निर्माता संघ कब तक मशीनरी दे पायेगा ?

†श्री अ० प्र० जैन : यह संघ वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की देख रेख में बनाया जा रहा है। इसलिये मैं इसका ठीक उत्तर तो नहीं दे सकता किन्तु मुझे आशा है दो वर्ष में यह मशीनरी मिल जायेगी।

†श्री तिरूमल राव : उत्तर से यह मालूम होता है कि विदेशी मुद्रा को १ करोड़ रुपये तक घटाया जा सकता है। ऐसी अवस्था में क्या सरकार इन चार कारखानों को प्राथमिकता देने को तैयार है ?

†श्री अ० प्र० जैन : मैंने अभी बताया है कि हमने योजना आयोग को आवश्यक मशीनरी मंगवाने के लिये तत्काल विदेशी मुद्रा देने के लिये कहा है ताकि उनकी सहायता से यहां पर शेष मशीनरी जल्दी से तैयार की जा सके। ग्यारह कारखानों को रुपया दिया जाना है। इसमें आन्ध्र के चार कारखाने भी हैं अगर इन को प्राथमिकता देनी उचित समझी गई तो जरूर दी जायेगी। किन्तु इस समय कुछ कहना कठिन है।

†श्री रंगा : मंत्री महोदय का उत्तर बड़ा भ्रमजनक है। एक ओर तो उन्होंने यह कहा है कि इन चार कारखानों को एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई है किन्तु पिछले उत्तर से यह दिखाई देता है कि यह कोई अन्तिम अथवा दृढ़ निश्चय नहीं। क्या सरकार इन्हीं चार कारखानों को यह राशि देगी जिससे कि यह ठीक समय पर स्थापित हो सकें ?

†श्री अ० प्र० जैन : मेरे उत्तरों में कोई विरोधाभास नहीं है। यह तय हो चुका है कि ये कारखाने बनाये जायें और इनके लिये आवश्यक मशीनरी ही विदेशों से मंगाई जाये। जहां तक मुद्रा देने का प्रश्न है यह उपलब्धि पर निर्भर करता है।

†अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा यह जानना चाहते थे कि क्या यह तीन करोड़ या एक करोड़ रुपया इन चार कारखानों को मिलेगा अथवा ग्यारह को ?

†श्री अ० प्र० जैन : यह केवल इन चार कारखानों के लिये है।

†श्री हेडा: क्या यह सच है कि कुछ अन्य चीनी निर्माण के लिये निजी योजना कर्त्ताओं को आयात लाइसेंस दिये जा चुके हैं जब कि इन कारखानों को अभी तक लटकाया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० प्र० जैन : यदि कोई ऐसी चीज हुई है तो इसके लिये योजना आयोग उत्तरदायी है।

†श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या ये ग्यारह कारखाने आन्ध्र के चार कारखानों के इलावा हैं या उनमें यह चार भी सम्मिलित हैं?

†अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को आन्ध्र के कारखानों के बारे में ही सूचना मांगनी चाहिये।

†श्री अ० प्र० जैन : दो बम्बई में, एक मैसूर में, चार आन्ध्र में, दो पंजाब में, एक उत्तर प्रदेश में और एक उड़ीसा में।

†श्री जाधव : क्या बम्बई राज्य ने कोई शिकायत की है कि यहां की निर्मित मशीनरी ठीक नहीं है और उसके कारण काफी हानि सहन करनी पड़ रही है?

†श्री अ० प्र० जैन : मैंने कभी यह नहीं कहा कि मशीनरी बन चुकी है। अभी तो संघ बना है। उसे मशीनरी बनाने में समय लगेगा। कदाचित् माननीय सदस्य पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं कि यहां पर जो मशीनरी बनेगी वह बुरी होगी।

पश्चिम जर्मनी का कृषि प्रतिनिधि मंडल

+

†*५६९. { श्री रा० च० माझी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी के कृषि प्रतिनिधिमंडल ने, जो कि हाल ही में भारत के कृषि कार्यक्रम के विकास में सहायता करने के लिये भारत आया था, कोई रिपोर्ट दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री रा० च० माझी : वे लोग हमारे देश में कितनी देर रहे तथा किन-किन राज्यों में गये?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : वे लोग १४ सितम्बर को आये और ११ नवम्बर को गये। वे किन-किन राज्यों में गये इसका मेरे पास पूरा वर्णन नहीं है। वैसे उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय, योजना आयोग तथा हमारे मंत्रालय के साथ बातचीत की है और वे लोग देश की अधिकांश कृषि संस्थाओं में भी गये हैं।

†श्री पु० र० पटेल : हमें उससे क्या लाभ हुआ है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जर्मनी में विभिन्न कृषि क्षेत्रों के पांच काफी अनुभवी विशेषज्ञ थे। और भारत-जर्मन कृषि सहकारिता के आधार पर वे यहां की स्थिति का अध्ययन करना चाहते थे ताकि उसी के अनुरूप सहायता कर सकें।

†**श्री पु० र० पटेल :** लेकिन, इससे हमें क्या लाभ हुआ है?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रतिनिधिमण्डल परस्पर लाभ के लिये आया था।

†**श्री रा० च० माझी :** क्या वे किसी सहकारी फार्म में गये थे और यदि हां, तो उन्होंने सहकारी फार्मों के विकास के लिये क्या सुझाव दिये हैं?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** उनमें से एक सदस्य ने हमारे देश की सहकारी संस्थाओं का अध्ययन भी किया है। किन्तु अभी उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री आचार :** क्या इनसे कोई किसान भी मिला है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** उन्होंने देश की कृषि संस्थाओं का भ्रमण किया है। मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि इस दौरान में वह किसी किसान से मिले हैं अथवा नहीं।

श्री जगदीश अवस्थी : मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रतिनिधिमंडल आया था उसे सरकार ने आमंत्रण दिया था या वह स्वयं आया था?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह स्वयं आये थे या हमारे आमन्त्रण पर?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वह स्वयं आये थे।

सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म

\+

†*५७०. { **श्री दामानी :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ के केन्द्रीय यन्त्रीकृत फार्म में जोत की भूमि तैयार करने व कृषि भूमि का विकास करने के बारे में क्या नवीनतम प्रगति हुई है ; और

(ख) इस समय फार्म कितने उपलब्ध उपकरणों का लाभ उठा रहा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) २९२३ एकड़ भूमि इसकी खरीफ में बुवाई हुई थीं और अब इसमें फसल खड़ी है। वर्तमान रब्बी के मौसम में अभी तक १०६५२ एकड़ भूमि में बुवाई की जा चुकी है तथा और काम जारी है।

(ख) ७५ प्रतिशत।

†**श्री दामानी :** क्या यह सच है कि रूस से हमें १९५६ में पूरा उपकरण मिल गया था किन्तु यह अब तक व्यर्थ पड़ा था, यदि हां, तो इसका कारण तथा क्या इस उपकरण का इसके आस पास किसी अन्य फार्म में भी प्रयोग किया गया है?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : नहीं यह ठीक नहीं है। हमें १६५६ में पूरे उपकरण नहीं मिले थे। रूस ने १६५६ में इनको एक मुश्त पांच जहाजों में वहां से रवाना कर दिया था, किन्तु यह हमें नहीं मिले। हम इस सारी मशीनरी का, केवल कुछ वस्तुओं जैसे टेलीफोन सेट्स वगैरह को छोड़ कर पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं।

†श्री दामानी : क्या समीपवर्ती पानी के तालाबों से इस फार्म को पानी मिल सकेगा ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह आशा की जाती है कि १६६०–६१ तक ३००० एकड़ की सारी भूमि भाखड़ा सिंचाई योजना के अन्तर्गत आ जायेगी।

†श्री नागी रेड्डी : क्या यह सच है कि मशीनरी की टूट फूट का कारण इसका इस्तेमाल नहीं है जितना कि इसका धूप और छांह में खुले में पड़ा रहना है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : प्रारम्भ से ही इस फार्म में रूसी इंजीनियर कार्य कर रहे हैं। सब कार्य उनकी सलाह के अनुसार हो रहा है। हमें खुले से नहीं डरना चाहिये क्योंकि उस इलाके में बहुत कम, केवल ४" सालाना, वर्षा होती है।

†श्री नागी रेड्डी : किन्तु वहां धूप, आंधी तथा मिट्टी तो होती है।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : वहां बहुत कम वर्षा होती है। दूसरे वहां पर कोई इमारत नहीं है। हमने हर वस्तु को सुरक्षित तरीके से रखा है।

†श्री दामानी : जब पूरा फार्म चालू हो जायेगा तब इसमें कितने लोगों को नौकरी मिल जायेगी तथा कितने लोगों को प्रशिक्षण मिल सकेगा तथा क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : अभी हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। हम इसको एशिया में सब से बड़ा फार्म बनाना चाहते हैं।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सूरतगढ़ फार्म में जो अपने विशेषज्ञ हैं वे प्रति एकड़ कितना उत्पादन करते हैं और पहले के जो किसान हैं वे उस जमीन में प्रति एकड़ कितना उत्पादन करते थे ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इस साल हमने वहां पर धान बोया था और वह प्रति एकड़ ३० मन हुआ है जबकि ऐवरेज ११ मन प्रति एकड़ का है। इस प्रकार यह एक सर्वोत्तम फार्म सिद्ध होगा।

†श्री पु० र० पटेल : अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण की अपनी नीति को देखते हुये क्या हमारे देश में यंत्रीकृत फार्मों का परीक्षण करना ठीक होगा, यदि नहीं, तो फिर इस पर रुपया क्यों अपव्यय किया जा रहा है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : हमारे लिये सौभाग्य की बात है कि हमारे रूसी मित्र भारत में आये हैं। यह फार्म अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखता है और हम देखना चाहते हैं कि यह पूर्णतया सफल फार्म सिद्ध हो ताकि यहां पर ऐशिया में सब से अच्छी नसल के बीज, बैल तथा रंभे आदि पैदा किये जा सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दासप्पा :** क्या यहां के अनुभव का हम सहकारी फार्मों में भी लाभ उठाना चाहेंगे ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** हम इस अनुभव का कहीं भी लाभ उठा सकते हैं। सहकारी प्रकार के फार्म इससे सर्वथा भिन्न प्रकार के होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं मंत्री महोदय का पहला उत्तर ठीक से नहीं सुन सका। क्या उन्होंने "पिडिग्री लैंड्स" कहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जी नहीं। मैंने "पिडिग्री रेम्ब्स" शब्द कहे हैं। उस क्षेत्र में बहुत बढ़िया प्रकार की भेड़ें पाई जाती हैं। हम चाहते हैं कि हम इस फार्म में उनसे बहुत उत्तम प्रकार के रम्मे उत्पन्न कर सकें।

क्षेत्रीय लघु सिंचाई सम्मेलन

†*५७१. **श्री पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की लघु सिंचाई योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाने की समस्या पर पूर्वी क्षेत्रों और क्षेत्रीय लघु सिंचाई सम्मेलन की कलकत्ता में ८ व ९ अगस्त, १९५८ को हुई बैठकों में विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने अपने संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये कोई सुझाव रखे हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने नई योजनाओं को प्रारम्भ करने से पूर्व पुरानी चालू योजनाओं को पूरा करने का निश्चय किया है। वह एक लघु सिंचाई निदेशालय की स्थापना कर रही है। खेतों में नालियों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार एक सिंचाई अधिनियम भी बनाने जा रही है।

†**श्री पाणिग्रही :** उड़ीसा में कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई करने की व्यवस्था थी। सरकार को सारी भूमि की सिंचाई में क्या कठिनाइयां प्रतीत हुई हैं तथा उसने इस सम्मेलन के सामने क्या समस्यायें रखी हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जहां तक लघु सिंचाई योजनाओं का संबंध है मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इनका पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है। जैसे ही कोई कूप या तालाब खोदा जाता है उसी समय उसके पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है।

उड़ीसा में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये कोई पृथक विभाग नहीं है। इसलिये इसके लिये वह एक निदेशालय बना रहे हैं तथा एक अधिनियम भी पास कर रहे हैं।

†**श्री पाणिग्रही :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा को लघु सिंचाई योजनाओं के लिये कितना रुपया दिया गया है और उड़ीसा में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : १.३८ करोड़ रुपये पांच वर्ष के लिये पहले साल में सरकार ने १६ लाख रुपये व्यय किये, द्वितीय वर्ष में २५ लाख रुपये और इस साल के लिये ४१ लाख रुपये दिये गये हैं ।

†श्री महन्ती : प्रश्न यह था कि क्या उड़ीसा में लघु सिंचाई योजनाओं का पूरा पूरा लाभ उठाया जा रहा है । इस संबंध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार का ध्यान उड़ीसा राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में प्रगति नामक पुस्तिका की ओर दिलाया गया है जो कि योजना आयोग द्वारा बांटी गई थी और जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि प्रविधिक व्यक्तियों की कमी के कारण राज्य की योजनाओं का पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है । हम इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहते हैं कि क्या यह बात सच है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : यह प्रश्न लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में है । इसके अन्तर्गत छोटे छोटे तालाब, कूप, व छोटी नहरें आदि आती हैं । इनके उपयोगय करने का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता । केवल नल-कूपों के बारे में कहा जा सकता है कि इनके पूरे पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है मगर उड़ीसा में कोई नलकूप नहीं है । कदाचित, माननीय सदस्य के मन में वृहत् सिंचाई योजनाओं का विचार घूम रहा है जिनका कभी कभी पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता है । क्योंकि उनके आसपास के खेतों में नालियां इत्यादि बनी होती हैं ।

†श्री बसुमतारी : क्या आसाम सरकार ने इस सम्मेलन में अपने यहां की नदियों आदि से कोई लघु सिंचाई योजना बनाने का सुझाव दिया है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इसके लिये पृथक प्रश्न पूछा जाना चाहिये

†श्री सूपकार : अभी तक मूल प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है कि कितने प्रतिशत कामों का लाभ उठाया जा है रहा और कितने का नहीं ।

†श्री अ० प्र० जैन : लघु सिंचाई योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ उठाया जा रहा है ।

†श्री पाणिग्रही : क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में अगले दो वर्षों के लिये लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य करने के लिये और सहायता देने के लिये कहा है ?

†श्री मो०वें० कृष्णप्पा : हमने कलकत्ता सम्मेलन में सभी व्यय पर विचार किया था । उड़ीसा सरकार प्रविधिक कर्मचारियों की कमी के कारण पहले दिये गये सारे रुपये का व्यय नहीं कर पाई है इसलिये उसको अतिरिक्त रुपया देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री महन्ती : नालियां और नहरें खोदने के लिये कौन से प्रविधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है ? यदि कर्मचारियों की कमी का ही प्रश्न है तो क्या सरकार इस काम के लिये विदेशों से कर्मचारी मंगाना चाहती है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये कि उड़ीसा में भी एक सरकार व विधान सभा है । ऐसी बातें वहां के सदस्य पूछ सकते हैं ।

†श्री पाणिग्रही : यदि वे लोग न पूछें ?

†अध्यक्ष महोदय : तब मैं क्या करूं ? हमारे पास बहुत कम समय है । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सड़क विकास योजना

+

*५७२. { श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ५ सितम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य इंजीनियरों के सामान्य निकाय ने इस बीच सड़कों की योजना के प्रारूप की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुनरीक्षित योजना का विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारामक हो, तो योजना को अन्तिम रूप देने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). चीफ इंजीनियरज़ की जनरल बाडी ने योजना के मसौदे की जंच कर ली है और इनके सुझावों के आधार पर योजना तय की जा रही है। आशा है इसे जल्दी ही सरकार के सामने पेश करने के लिये तैयार कर दिया जायेगा। [इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी दिया गया]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि नागपुर प्लान जिन सिद्धांतों पर आधारित था उन सिद्धांतों में और जो यह नई २० वर्ष की योजना बनाई जा रही है, उनके सिद्धांतों में क्या अन्तर है ?

श्री राज बहादुर : नागपुर प्लान में यह लक्ष्य रक्खा गया था कि प्रत्येक गांव जो कि एक विकसित कृषि क्षेत्र है वह किसी भी मुख्य सड़क से ५ मील से अधिक दूरी पर न हो और अविकसित क्षेत्र में २० मील से अधिक दूरी पर न हो।

जहां तक नई योजना का संबंध है और जो लक्ष्य उसमें रक्खा गया है वह यह है कि विकसित कृषि क्षेत्र में कोई गांव पक्की सड़क से ४ मील से अधिक दूर न हो और अन्य किसी सड़क से डेढ़ मील से अधिक दूरी पर न हो। अर्ध कृषि क्षेत्र में कोई गांव पक्की सड़क से ८ मील से अधिक दूर न हो और अन्य किसी सड़क से तीन मील से अधिक दूर न हो। गैर कृषि क्षेत्र में कोई गांव १२ मील से अधिक पक्की सड़क से दूर न हो और ३५ से अधिक मील किसी अन्य सड़क से दूरी पर न हो।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अनुमान लगाया गया है कि जो नई योजना तैयार की जा रही है उसमें कुल कितना खर्चा पड़ेगा और क्या योजना आयोग ने इस संबंध में कोई आश्वासन दिया है कि इतना रुपया उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री राज बहादुर : अनुमानतः लगभग ५ हजार रुपया खर्च आयेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री नवल प्रभाकर : क्या मंत्री महोदय यह बतला सकेंगे कि चीफ इंजीनियर्स ने जो एक योजना तैयार की है क्या उसको सद्न के सभा-पटल पर रक्खा जा सकेगा ?

श्री राज बहादुर : यह जो योजना तैयार की है वह चीफ इंजीनियर्स की मीटिंग में, तैयार की गई है। उसको पहले गवर्नमेंट के सामने रक्खा जायगा और प्लानिंग कमिशन द्वारा भी उसकी जांच होगी और तदुपरांत वह हाउस के सामने किसी रूप में आयेगी।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या विभिन्न क्षेत्रों की दूरी के अनुसार सड़कें बनाने का पैमाना पहाड़ी क्षेत्रों में भी लागू किया जायेगा जोकि परिवहन की दृष्टि से पहले ही बहुत पिछड़ हुये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक मंभव होगा हम पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं का भी ध्यान रखेंगे।

†**श्री राम कृष्ण :** योजना के मसौदे में और कौन कौन से [illegible] सम्मिलित किये गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं इनके नाम नहीं बता सकता क्योंकि अभी यह योजना ही स्वीकार नहीं हुई है। किन्तु उस नई योजना के अन्तर्गत ३२,००० मील की सड़कें बनाने का प्रस्ताव है जबकि वर्तमान सड़कों की लम्बाई १३,८०० मील है और नागपुर योजना में २०,००० मील थी।

†**श्री दासप्पा :** क्या सरकार इस कार्य को तेजी से करने का प्रयास करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता-पूर्वक गौर कर रही है।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह विकास योजना केवल राष्ट्रीय राजपथों के बारे में ही है अथवा इसमें राज्यों के वर्तमान राजपथों को मिलाने की योजना भी है। यदि यह केवल राष्ट्रीय राज-पथों के बारे में ही है तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या उसमें वर्तमान राष्ट्रीय राजपथों को बढ़ाने तथा कुछ राजकीय राजपथों को राष्ट्रीय राजपथों में बदलने की भी कोई योजना है ?

†**श्री राज बहादुर :** यह एक विस्तृत योजना है जिसमें न केवल राष्ट्रीय राजपथ बल्कि राज्य राजपथ, जिलों और गांवों की प्रमुख सड़कें भी शामिल हैं। स्पष्ट है कि जब हम इस योजना को आरम्भ करेंगे तब कुछ राज्य राजपथों को राष्ट्रीय राजपथ और जिला सड़कों को राज्य राजपथ बना दिया जायेगा अथवा घोषित कर दिया जायेगा।

†**श्री भक्त दर्शन :** मैं यह जाना चाहता हूं कि नागपुर प्लान में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे पक्की और कच्ची सड़कों के, उनकी अब तक कितनी पूर्ति हो चुकी है और नई योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य पूरे होंगे उनके बाद हमारे देश का नक्शा क्या होगा ?

श्री राज बहादुर : नागपुर प्लान में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह करीब करीब ३ लाख ३१ हजार का था जिनमें कि [illegible] हाइवेज और स्टेट हाइवेज़ सब सम्मिलित हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त [illegible] लाख ७९ हजार तक पूरा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** : योजना पर अभी विचार किया जा रहा है इसलिय क्या सीमा क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : जब योजना सरकार के सामने रखी जायेगी तब सीमा क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर उचित रूप में विचार किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस गति से इस पर विचार किया जा रहा है क्या उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कब तक इस बारे में अन्तिम निर्णय हो सकेगा ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि इस योजना के अन्त तक या तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों के संबंध में यह हो सकेगा। यह गति जो है विचार करने की वह काफी महत्वपूण है लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कितनी गति से हम इसके लिये पैसे इकठ्ठ कर सकेंगे और उनको बना सकेंगे।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री की प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत राजस्थान के कितने गांव आयेंगे ?

श्री राज बहादुर : गांवों की संख्या तो मैं नहीं बता सकता लेकिन बीकानेर डिवीजन में पड़ने वाले करीब करीब सब गांवों का ध्यान रक्खा जायेगा।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत के लिये गेहूं

†*५७३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत किन देशों ने भारत को उपहार के रूप म गेहूं भेजा और उसका कितना मूल्य था ;

(ख) क्या इस प्रकार प्राप्त किया गया गेहूं उचित मूल्य पर बेचा जायेगा ; और

(ग) इस गेहूं के विक्रय से उपलब्ध धन को किस परियोजना पर खर्च किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) **कनाडा** : लगभग ३९२ लाख रुपये की। **आस्ट्रेलिया** : लगभग २१ लाख रुपये की ।

(ख) यह गेहूं उसी मूल्य पर बेचा जायेगा जिस पर अन्य आयात किया गया गेहूं बेचा जा रहा है।

(ग) विषय विचाराधीन है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी**: विक्रय से कितनी राशि प्राप्त होने की आशा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैंने गेहूं का क्रय मूल्य बताया है। क्रय और विक्रय मूल्यों में विशेष अन्तर नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या सस्ते भाव पर अनाज बेचने के प्रयोजन के लिये उस लाभ को, जो उपाहारस्वरूप प्राप्त गेहूं के विक्रय से प्राप्त होगा आयात किये गये और स्थानीय तौर पर एकत्र किये गये गेहूं के मूल्य में से घटा दिया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: सारा गेहूं एक ही दर से बेचा जा रहा है। उपहारस्वरूप प्राप्त गेहूं के विक्रय से उपलब्ध राशि का व्यय उसी प्रकार किया जायेगा जैसे कि सरकार निर्णय करेगी। अभी तो यह निश्चय किया गया है कि आस्ट्रेलिया से प्राप्त हुए गेहूं के विक्रय से उपलब्ध होने वाली राशि कलकत्ता में "शैल" आकार के गोदाम बनाने पर खर्च की जायेगी।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : भाग (ग) के उत्तर के संबंध में, कब तक निर्णय हो जायेगा ? राज्यों में कितना बांटा जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह बताया जा चुका है कि आस्ट्रेलिया से प्राप्त गेहूं के विक्रय से उपलब्ध होने वाली राशि कलकत्ता में "शैल" आकार के गोदाम बनाने पर खर्च की जायेगी।

†**श्री त्यागी** : असल मूल्य से कम दर पर गेहूं बेचने के कारण वर्ष भर में कितनी हानि होने की आशंका है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मूल प्रश्न उपहारस्वरूप प्राप्त हुये गेहूं के बारे में है न कि यहां से खरीदे जाने वाले गेहूं के बारे में। माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न की सूचना दें।

†**श्री त्यागी** : मैं यह जानना चाहता था कि यदि उपाहरस्वरूप प्राप्त गेहूं और वसूल किये गये गेहूं के मूल्यों की औसत निकाल ली जाये तो क्या वह प्रचलित मूल्य से अधिक रहेगी या कम ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम बचतपूर्ण मूल्य पर विक्रय करेंगे और हम इसे जमा कर देंगे ; वित्त मंत्रालय इस पहलू को देखेगा। जहां तक हमारा संबंध है हम तो यही समझेंगे कि हमने इसके लिये भुगतान किया था और तब हमें गेहूं मिला था।

रबी की फसल

+

५७४. { **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को रबी की फसल के आंदोलन के संबंध में क्या सहायता दी है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): रबी उत्पादन आंदोलन के संबंध में राज्यों को दी गई सहायता का एक विवरण सभा की टेबिल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]**

†**श्री मोहन स्वरूप** : क्या सरकार को ज्ञात है कि रबी फसल के लिये बहुत कम बीज बांटे गये और वे घटिया भी थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: दोनों धारणायें गलत हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हीराकुड बांध परियोजना

†*५६४. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड बांध परियोजना की तृतीय तथा चतुर्थ अवस्था के नक्शे तैयार किये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक अवस्था की लागत का अनुमान क्या है; और

(ग) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन दोनों अवस्थाओं का काम पुरा हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ग). जी नहीं हीराकुड बांध परियोजना के मुख्य इंजीनियर ने महानदी घाटी विकास (अवस्था ३ और ४) के बारे में प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार किया है और उड़ीसा सरकार को विस्तृत अनुसंधान करने का सुझाव दिया है। राज्य सरकार प्रतिवेदन का परीक्षण कर रही है ।

(ख) प्रारम्भिक तथा मोटे तौर पर तैयार किये गये प्राक्कलन के अनुसार अवस्था ३ और ४ पर लगभग क्रमवार २४ करोड़ रुपये और १६ करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुमान है कि विस्तृत अनुसंधान पर ८३,२०० रुपये खर्च होंगे ।

आंध्र में धान की उपज

†*५७५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में आंध्र प्रदेश में धान की कुल कितनी उपज हुई ;

(ख) सरकार ने चावल की वसूली करते समय प्रति मन अधिकतम कितना मूल्य दिया (गत छः मास की औसत) और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब के मूल्यों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ; और

(ग) ग्रीष्म ऋतु की तीसरी फसल से चावल की अनुमानतः कितनी उपज हुई।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में आंध्र प्रदेश में अनुमानतः क्रमवार ३१.४१ और ३४·६८ लाख टन चावल की उपज हुई।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें चार राज्यों में चावल की वसूली के भाव बताये गये हैं **[देखिये परिशिष्ट ३, अनबन्ध संख्या २६]**

(ग) १९५७–५८ में १.८६ लाख टन ।

ग्राम्य ऋण

†*५७६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में कृषकों के लिए कृषि कार्यों के लिए सस्ते ऋण की शीघ्र व्यवस्था करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या इस व्यवस्था से ग्राम्य ऋणिता पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७**]

(ख) जी हां ।

टोकियो में खाद्य तथा कृषि संगठन का सम्मेलन

† ५७७. { **श्री वाजपेयी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या हाल ही में टोकियो में हुये खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन मे भारत ने एक अन्तर्राष्ट्रीय उर्वरक संग्रह और एक अन्तर्राष्ट्रीय कृषि बैंक की स्थापना करने का प्रयत्न किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). चतुर्थ खाद्य तथा कृषि संघठन क्षेत्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिडमंल ने यह सुझाव दिया कि खाद्य तथा कृषि संघठन और सदस्य सरकारें एक अन्तर्राष्ट्रीय उर्वरक संग्रह और राष्ट्रीय प्रत्यय तथा विपणन सहकारी संस्थाओं का विकास करने में सहायता देने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय कृषक सहकारी बैंक की स्थापना की संभावना को देखें। क्षेत्रीय सम्मेलन ने ये सुझाव स्वीकार कर लिये। अब अन्तर्राष्ट्रीय उर्वरक संग्रह और ऐसे बैंक की स्थापना करने की संभावना का अनुसंधान खाद्य तथा कृषि संगठन को करना होगा ।

हिंडन से दिल्ली के लिये जल

†*५७८. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने भारत से यह प्रार्थना की है कि दिल्ली की जल संबंधी आवश्यकता पूर्ति के लिए हिडन नदी से पानी देने के लिए वह उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा को रेल से मिलाना

†*५७९. **श्री दशरथ देब** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का पथारकंडी से धर्मनगर तक विस्तार करने के संबंध में सरकार किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

पंजाब में चावल का समाहार

†*५८०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चावल तथा अन्य खाद्यान्नों को उपलब्ध करने के लिये पंजाब सरकार को कोई आदेश दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो मामला विस्तार से क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जी हां, पंजाब सरकार को भारत सरकार की ओर से उद्ग्रहण पद्धति द्वारा लाइसैंसदार व्यक्तियों तथा मिलों से चावल प्राप्त करने का अधिकार है । इस आदेश के आरम्भ से ही जो कुछ स्टाक उनके पास होगा, उसका ७५ प्रतिशत उन्हें राज्य सरकार को बेचना होगा। और इसके बाद अपने प्रतिदिन के उत्पादन की ७५ प्रतिशत मात्रा भी राज्य सरकार को देनी होगी। उद्ग्रहण पद्धति द्वारा जो भी चावल प्राप्त किया जायेगा उसके लिये वह कीमत अदा कर दी जायेगी जो कि नियत्रण के अन्तर्गत पंजाब राज्य के लिये निर्धारित है ।

मद्रास और केरल का अन्तर्राज्यिक जल विवाद

†*५८१. { **श्री सम्पत** :
श्री वाजपेयी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारअलीकुलम विद्युत सिंचाई परियोजना के संबंध में केरल और मद्रास की सरकारों में कोई अन्तिम निर्णय हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो वह विस्तार से क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दोनों सरकारों ने काफी अच्छी प्रस्थापनाओं को स्वीकार कर लिया है, और सविस्तार मामले की छानबीन करके अन्तिम समझौता शीघ्र ही हो जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खंड विकास समितियां

†*५८२. **श्री रघुवीर सहाय** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंड विकास समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) और (ख) योजना पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और अन्तिम रूप देने पर इसकी प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कचार रोड का निर्माण

†*५८३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की कचार रोड के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) पहले ८८ मीलों का सविस्तार सर्वेक्षण हो चुका है और बाकी ६२ मीलों का सर्वेक्षण भी प्रगति पर है। ९ और २४ मीलों के बीच की सड़क का निर्माण अभी हाल ही में लिया गया है;

(ख) तीसरे योजना काल में।

कोलाघाट के निकट रूप नारायण नदी पर पुल

†*५८४. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ अगस्त १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५७ के जोकि कोलाघाट के निकट रूप नारायण नदी पर पुल निर्माण करने के संबंध में था, उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल का निर्माण कब तक पूर्ण होने की आशा है।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : ठेका देने के तीन वर्ष बाद तक पुल के पूर्ण होने की आशा है।

अमृतकौरपुरी दिल्ली में मकानों का निर्माण

*५८५. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की गन्दी बस्ती अमृतकौरपुरी में मकानों का निर्माण बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) जिस जगह पर मकान बनाये जाने हैं उस पर अनधिकृत कब्जा हो जाने के कारण मकानों का निर्माण रोक दिया गया है । इन अनधिकारी लोगों से स्थान खाली कराते ही निर्माण-कार्य फिर शुरू कर दिया जायेगा ।

रंगापुर के पास कृष्णा नदी पर पुल

†*५८६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ फरवरी १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगापुर के पास कृष्णा नदी पर पुल निर्माण करने का टेंडर स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ होगा और कब तक इसके समाप्त होने की आशा है ; और

(ग) यदि (क) का उत्तर नहीं में है, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में कार्य आरम्भ हो जायेगा और इसके पूर्ण होने में तीन वर्ष लगेंगे ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

कुल्लू के भूंतर[1] पर हवाई पट्टी

†*५८७. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल्लू घाटी में बंटर के स्थान पर हवाई पट्टी बनाने के कार्य के सर्वेक्षण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) कार्य कब आरम्भ होगा और इस पर खर्चे का क्या अनुमान है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). इस क्षेत्र का सर्वेक्षण अभी हाल ही में किया गया है और असैनिक उड्डयन के महानिदेशक से प्राप्त होने वाली उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) रिपोर्ट के परीक्षण के बाद इस पर कोई कार्यवाही की जायेगी ।

असंघीय जहाजों[2] का चार दिन का बहिष्कार

†*५८८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन कर्मचारी संघ ने १४ सितम्बर १९५८ शुक्रवार को ४ दिन के लिये असंघीय जहाजों का वहिष्कार किया जो झंडे लहरा रहे थे ; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bhuntar, Kulu Valley.

[2]Non-Union Ships.

(ख) यदि हां, तो भारत इस संबंध में क्या रास्ता अपनायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). भारत सरकार को सरकारी तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे जहाजों का भारतीय पत्तनों पर कोई बहिष्कार नहीं किया गया।

गेहूं गवेषणा संस्था

†*५८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के निरीक्षण में कार्य करने वाली गेहूं गवेषणा संस्थाओं की संख्या कितनी है ; और

(ख) खेतों में उत्पादन करने वालों को इन गवेषणा के परिणामों से कैसे परिचित कराया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) गेहूं संबंधी गवेषणा का कार्य इस समय १६ केन्द्रों में हो रहा है। इनमें से छः भारतीय कृषि गवेषणा संस्था नई दिल्ली के निर्देशक के प्रशासनिक नियंत्रण में है। बाकी के दस केन्द्र भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् सम्बद्ध राज्य सरकारों की सलाह से चलाती है।

(ख) राज्यों के कृषि विभाग इस गवेषणा के परिणामों को उत्पादकों तक पहुंचाते हैं। भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के महत्वपूर्ण परिणामों को 'इंडियन फार्मिंग', खेती और धरती के लाल नामक लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित कर दिया जाता है।

परिवहन सहकारी संस्थायें

†*५६०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री रामेश्वरटांटिया :
श्री कोडियान :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ सितम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेकारों को काम पर लगाने के लिये निर्माण की जाने वाली परिवहन सहकारी संस्थाओं की योजना के संबंध में सविस्तार विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर अनुमानित व्यय क्या होगा ; और

(ग) इसके लिये कितनी धनराशि उपलब्ध है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) हां, योजना को सविस्तार अन्तिम रूप दिया जा चुका है, और जिन पांच राज्यों में सहकारी संस्थाओं को स्थापित किया जाना है, उनकी राज्य सरकारों को इसे कार्यान्वित करने के लिये कहा जा रहा है। सम्बद्ध सरकारों से प्राप्त टिप्पणों के फलस्वरूप योजना के विस्तार में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) योजना पर लगभग २० लाख व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) जब ही राज्य योजना को चलाना स्वीकार करेंगे धन की व्यवस्था हो जायेगी ।

चित्तरंजन में इस्पात का ढलाई घर

***५९१. श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन के लोकोमोटिव कारखाने में इस्पात के ढलाई घर बनाने की प्रस्थापना किस अवस्था में है ; और

(ख) इस पर अनुमानित कितना व्यय होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) टेंडरों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और इसके लिये ब्रिटेन की सार्थ मैसर्ज़ एफ० एच० लोयडज एंड कम्पनी के साथ करार कर लिया गया है ।

(ख) परियोजना का कुल व्यय लगभग २.५ करोड़ होने की आशा है ।

'डीलक्स' गाड़ियां

***५९२. श्री राम कृष्ण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सभी वातावस्थापित डीलक्स गाड़ियां, जब से चली हैं, अच्छा नफा निकाल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन गाड़ियों की संख्या को बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) किन्ही विशेष गाड़ियों के चलाने के व्यय का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । इसलिये इन वातावस्थापित डीलक्स गाड़ियों के नफे का पता करना संभव नहीं । यह कहना भी संभव नहीं कि इनसे काफी नफा हो रहा है ।

(ख) नहीं ।

भारत और भूटान को मिलाने वाली सड़कें

†*५९३. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री पाणिग्रही :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री भगवती : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत और भूटान के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिये दो सड़कें निर्माण करने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) दो सड़कों का निर्माण, अर्थात् आसाम में ग भाषा—हतिसार सड़क और पश्चिमी बंगाल में जैंती—बुक्षापुर—संयूल सड़क, जो कि भारत और भूटान को मिलायेगी, किया जा रहा है । इस कार्य को तीसरी पंच वर्षीय योजना में समाप्त कर लेने की पूरी आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुकामा पुल से दरभंगा तक बड़ी लाइन

***५६४. श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुकामा पुल से, जो इस समय बनाया जा रहा है, एक बड़ी लाइन दरभंगा और नरकटियागंज तक बनाई जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब आरम्भ होगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) इस सुझाव पर विचार हो रहा है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

दूध के चूर्ण का कारखाना

†***५६५. श्री नागी रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करें कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थान पर दूध के चूर्ण का कारखाना स्थापित करने के संबंध में निश्चय किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धन राशि खर्च की जायेगी ; और

(ग) कारखाना कितने उत्पादन का लक्ष्य अपने समक्ष रखेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) दूध के चूर्ण का कारखाना स्थापित करने का प्रयत्न आंध्र सरकार के विचाराधीन है और उसके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

अगरतला का रेलवे आउट एजेन्सी

†***५६६. श्री दशरथ देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला तथा अन्य क्षेत्रीय मुख्यालय स्थानों पर रेलवे आउट एजेंसी को चालू करने की मांग वाले अभिवेदन सरकार को प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सामान के परिवहन के लिये इस प्रकार की आउट एजेंसी चालू करने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, धर्मनगर और अगरतला में बाह्य अभिकरण चालू करने के अभिवेदन प्राप्त हुये थे ।

(ख) अगरतला में आउट एजेंसी को चालू करने का निर्णय कर दिया गया है और इस निर्णय को कार्यान्वित करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है । धर्म नगर के बारे में उत्तर पूर्वी सीमा रेलवे जांच कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीकानेर और लालगढ़ के बीच की रेल लाइनों का रुख बदलना

†*५९७. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने बीकानेर और लालगढ़ के बीच की रेल लाइनों का रुख बदलने की प्रस्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) प्रस्थापना का परीक्षण किया जा रहा है।

खंड विकास समितियां

†*५९८. **श्री पाणिग्रही** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में हुये विकास आयुक्तों के सम्मेलन में यह प्रस्थापना स्वीकार कर ली गयी थी कि खंड विकास समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों को स्व सेवक संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षित किया जाए ;

(ख) क्या खंडों में कर्मचारियों की कमी के मामले पर भी सम्मेलन में चर्चा हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के संबंध में क्या निर्णय किया गया ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) इस संबंध में जानकारी दिल्ली में ६ और ७ नवम्बर १९५८ को हुई। विकास आयुक्त कर्मचारी सम्मेलन के संक्षेप रिकार्ड से उपलब्ध हो सकता है। उसकी प्रतिलिपियां संसदीय पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

मुरादाबाद के निकट राम गंगा नदी पर पुल

*५९९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद के निकट रामगंगा नदी पर सड़क का पुल बनाने में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : प्रारम्भिक सर्वेक्षण का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन चालू योजना की अवधि में फंड न होने कारण पुल बनाने का काम शुरू करना सम्भव न हो सकेगा।

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण समिति

†६००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पशु हिंसा निवारण समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के संबंध में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विवरण

पता चला है कि बिहार सरकार जहां तक संभव है समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही कर रही है। मद्रास सरकार भी इस पर विचार कर रही है। यह बात तो इससे पूर्व भी एक प्रश्न के उत्तर में कही गयी है कि मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मैसूर, उत्तर प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा की सरकारें भी कार्यवाही कर रही हैं। अन्य राज्यों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय विधान से संबंधित समिति की सिफारिशों के संबंध में समिति द्वारा बनाये हुये विधेयक के प्रारूप पर विधि मंत्रालय से परामर्श किया जा रहा है। इसे शीघ्र ही मंत्रि मंडल के समक्ष उनके आदेशानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

सड़क परिवहन

†*६०१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०० के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन का विकास करने के लिये सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह विस्तार से क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). नहीं. सड़क परिवहन तथा परिवहन के अन्य अंगों के विकास संबंध में राष्ट्रीय नीति निर्माण का कार्य भारत सरकार के विचाराधीन है।

वायु परिवहन परिषद्

*६०२. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वायु परिवहन परिषद् के भावी स्वरूप के प्रश्न के बारे में, जिस पर विचार किया जा रहा था, क्या निर्णय हुआ है ?

असनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : एयर कारपोरेशन एक्ट के दफा ३० को तरमीम करने पर गौर किया जा रहा है जिससे केन्द्रीय सरकार को यह अख्तियार होगा कि कौंसिल को बरखास्त कर दिया जाय और जब भी जरूरत हो दूसरी कौंसिल कायम की जाय। कौंसिल पर जो खर्च हो रहा था उसका ऐसा इन्तजाम किया है कि इस वक्त कोई खर्चा नहीं है।

तेल द्वारा समुद्र को गंदा किया जाना

†*६०३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ के तेल द्वारा समुद्र को गन्दा किया जाने पर रोक लगाने वाले सम्मेलन को भारत ने मान्यता प्रदान कर दी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं।

(ख) सम्बद्ध हितों से परामर्श करके मामले पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

भारत में बच्चों के नेत्र रोग

†८८५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय बच्चों में नेत्र रोगों की वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के कारण क्या हैं ; और

(ग) इनको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** :(क) अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा कोई सामयिक सर्वेक्षण किया नहीं गया जिससे यह पता चल सके कि बच्चों के नेत्र रोगों की वृद्धि हो रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलों में भीड़-भाड़

†८८६. { **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री राम कृष्ण** : **श्री दलजीत सिंह** : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में (अब तक) उत्तरी रेलवे पर रेलों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) इसके परिणाम क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १-४-५८ से लेकर १५-११-५८ तक के काल में उत्तरी रेलवे पर, समुचित लाइनों की क्षमता की उपलब्धी को देखते हुये और आवश्यक माल के यातायात के लिये जितनी आवश्यकता का अनुमान लगाया गया उसकी व्यवस्था करते हुये और अतिरिक्त गाड़ियों और लोकोमोटिवों का ध्यान रखते हुये, रेलों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिये निम्न लिखित पग उठाये गये हैं :—

	बड़ी लाइन	छोटी लाइन
नयी चालू की गयी गाड़ियां . .	१८	२
वर्तमान गाड़ियां जिनकी दूरी का विस्तार किया गया .	२	२
उन गाड़ियों की संख्या जिनके भार में वृद्धि कर दी गई .	९४	४४

†मूल अंग्रेजी में

बड़ी लाइन की जो १८ गाड़ियां हैं, इनमें से १० सामयिक यात्रियों के लिये जिनका विस्तार से विवरण यह है :—

गाड़ी संख्या	जहां चलती है	चलने का काल
१ ए० पी०/२ ए० पी०	अमृतसर–पट्टी	१–४–५८ से १–१०–५८
१ बी० क्यू०/२ बी० क्य०	बटाला–कादिया	,, ,,
१ जे० एन०/२ जे० एन०	जालन्धर–नाकोदर	,, ,,
दोहरी ३३ अप/३४ डोऊन काश्मीर मेल	नयी दिल्ली–पठानकोट	यह १५-४-५८ को चालू की गयी और जब तक काश्मीर यातायात का जोर कम नहीं होता जारी रहेगी।
९ए० ए०/१० ए० ए०	अमृतसर–अटारी	१८–७–५८ से १–१०–५८

(ख) जो कि (क) भाग में पग उठाने की बात की गयी है, उससे उत्तर रेलवे की भीड़ भाड़ काफी कम हो गयी है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव

†८८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक कितनी संख्या में चितरंजन में लोकोमोटिव तैयार हुये ; और

(ख) क्या १९५७–५८ के मुकाबले में उत्पादन व्यय कुछ कम हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) प्रथम जनवरी से ३१ अक्तूबर १९५८ तक १३५ लोको तैयार हुए।

(ख) १९५७–५८ में उत्पादित १६४ लोकोमोटिवों पर औसतन खर्च ४१६ हजार हैं। १९५८–५९ में यह खर्च ४२४ हज़ार है। यह ९२ से ४१ लोकोमोटिवों की वास्तविक औसतन व्यय के आधार पर था जो कि १९५८–५९ से अक्तूबर १९५८ तक के काल में निर्माण किये गये थे। ९वें संग्रह के १८ लोको जो १९५८–५९ में अन्तिम रूप में बनाये जा रहे हैं, उसमें खर्चा कुछ कम होने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गेहूं का स्टाक

†८८८. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में केन्द्रीय सरकार के पास कितना गेहूं का स्टाक है ; और

(ख) यह कौन से साधनों से उपलब्ध किया गया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) यह जानकारी देना जन हित में नहीं होगा ।

(ख) अमरीका, कानाडा, और आस्ट्रेलिया ।

नयी दिल्ली की भंगी बस्ती के पीछे गन्दा क्षेत्र

†८८९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८८ के उत्तर के संबंध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नयी दिल्ली की भंगी बस्ती के पीछे के क्षेत्र को सुविधायें देने के काम में कहां तक प्रगति हुई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : नयी दिल्ली नगरपालिका की रिपोर्ट के अनुसार, वहां सब काम पूर्ण कर दिया गया है ।

औद्योगिक निकायों को विद्युत् सम्भरण

†८९०. श्री राम कृष्ण : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ से प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में विद्यत जन विद्युत निकायों द्वारा औद्योगिक निकायों को संभरित की गयी ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : १९५६ से जन विद्युत निकायों द्वारा औद्योगिक निकायों को संभरित की गयी विद्युत की मात्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा किलोवाट
१ ५६–५७	५,४७७,६०१
१९५७–५८	६,०७६,२०७

भाखड़ा की नहरें

†८९१. श्री राम कृष्ण : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६ से अब तक वर्षानुसार, भाखड़ा की नहरों से कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गई है ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी ?

†मल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क)

१९५६–५७	१३,१८,६३८ एकड़
१९५७–५८ . . .	१४,९२,४६३ एकड़
(ख) राजस्थान . . .	२,४०,००० एकड़
पंजाब . . .	जानकारी एकत्र की जा रही है और पंजाब सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

उत्तर रेलवे की माल और एक्सप्रेस गाड़ियों पर भोजन व्यवस्था करने वाले

†८९२. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की माल और एक्सप्रेस गाड़ियों पर भोजन व्यवस्था करने वालों की क्या संख्या है ; और

(ख) भोजन व्यवस्था करने वाले इन लोगों के विरूद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ३ ।

(ख) ३ (१९५८–५९ में ३१–१०–५८ तक) ।

उड़ीसा में वन

†८९३. श्री पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में वन विकास की कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) उड़ीसा सरकार ने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वन विकास की निम्नलिखित ७ योजनायें सम्मिलित की है जिन के लिये केन्द्र वित्तीय सहायता देगा :

१. संचार
२. नर्म लकड़ी के बागान
३. भूतपूर्व जमींदारी सम्बन्धी वनों का प्रबन्ध
४. राष्ट्रीय उद्यान और मृगशरणस्थान बनाना
५. वनों का सीमांकन
६. टीक तथा अन्य मूल्यवान इमारती लकड़ी के वन लगाना
७. सबािर घास और खैर बागान लगाना

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हां। चालू योजना काल में केन्द्र ने उड़ीसा सरकार की वन योजनाओं के लिए गत तीन वर्षों में उन्हें निम्नलिखित सहायता मंजूर की थी :

	केन्द्रीय सहायता	
	ऋण (रुपये)	अनुदान (रुपये)
१९५६–५७ . . .	२,३८,०००	४५,५००
१९५७–५८ . . .	४,०४,०००	७१,७००
१९५८–५९	*२,५०,२००	*८२,०००

*(मंजूरी के लिए अनुमोदित)

स्पिती क्षेत्र के लिए डाक व्यवस्था

†८९४. श्री हेम राज : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २७ सितम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर, चीनी, नामगिया, काजा और लोसाई की ओर से स्पिती तक नई डाक व्यवस्था आरम्भ करने के बारे में पंजाब सरकार से कोई प्रतिवेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) उत्तर सकारात्मक है।

(ख) पंजाब के पोस्टमास्टर जेनरल ने २० नवम्बर, १९५८ को रामपुर, बुशहर, चीनी, नामगिया, काजा और लोसाई की ओर से स्पिटी के क्षेत्र के लिए हरकारों द्वारा डाक व्यवस्था चालू करने का आदेश दिया है। इस क्षेत्र में अत्यधिक हिम पात होने के कारण आदेश का पालन नहीं हो सका क्योंकि हिमपात के कारण ओवरसियर वहां जा कर आवश्यक प्रबन्ध नहीं कर सका। तो भी पोस्टमास्टर जेनरल इस व्यवस्था को यथा संभव शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही कर रहा है।

लाहौल क्षेत्र में डाक व्यवस्था

†८९५. श्री हेम राज : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक लाने ले जाने के लिए टेंडर मांगे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निश्चय किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) इस मामले का पुनर्विलोकन करने पर यह पता लगा है कि वर्तमान पद्धति के स्थान पर संविदा पद्धति बनाने से कीलांग डाक घर के व्यय में और अधिक वृद्धि हो जायेगी जब कि वह पहले ही हानि

†मूल अंग्रेजी में

पर चल रहा है। अतः पंजाब सरकार से पूछ ताछ की जा रही है ताकि टेंडर मांगने से पूर्व यह पता लग जायगा कि क्या वह हानि वहन करने के लिए तैयार होंगे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पटसन का उत्पादन

†८९६. श्री अ० चं० गुह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिल के दरवाजे पर और पश्चिमी बंगाल के निचले भाग, उत्तर पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश के उत्पादकों के लिए पटसन का प्रति मन मूल्य क्या है;

(ख) १९५७, १९५६ और १९५५ में (मिल के दरवाजे और इन पांच स्थानीय बाजारों में) प्रचलित मूल्य की तुलना में इस वर्ष पटसन का मूल्य क्या है ; और

(ग) पश्चिमी बंगाल के निचले भाग, उत्तर पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश के स्थानीय बाजारों में धान के मूल्य की तुलना में इस वर्ष पटसन का मूल्य कैसा है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) तथा (ख). उत्पादक सामान्यतः अपना पटसन ऊपरी भाग के मुफासिल केन्द्रों में अपना पटसन बेचते हैं। एक विवरण जिसमें (१) चालू वर्ष (अक्तूबर १९५८) के थोक मूल्य और (२) पश्चिमी बंगाल के निचले भाग, उत्तर पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम और उत्तर प्रदेश के मुफसिल केन्द्रों और कलकत्ता में निम्न किस्म (बारम वेरायटी) के कच्चे पटसन का १९५७, १९५६, और १९५५ के उसी मास के प्रचलित थोक मूल्य, दिये गये हैं, संलग्न है--विवरण १ [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८] मिल के दरवाजे पर कच्चे पटसन के मूल्यों सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित नहीं हुए।

(ग) पश्चिमी बंगाल के निचले भाग, उत्तर पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्य बाजारों में निम्न किस्म (बारम वेरायटी) के पटसन के चालू (अक्तूबर १९५८) थोक मूल्य (मोटी किस्म के) चावल के थोक मूल्यों का एक विवरण संलग्न है--विवरण २ [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८]। धान के मूल्य नहीं दिये गये क्योंकि वे एकत्रित नहीं हुए।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिए आयात किया गया इस्पात

†८९७. श्री पांगरकर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५८-५९ में अब तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिए जापान और जर्मनी से कितना इस्पात आयात किया गया ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : जापान से कोई आयात नहीं किया गया। जर्मनी से २८,५०० रुपये का २५ टन।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सड़क विकास के लिए सहायता

†८९८. श्री पांगरकर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सड़क विकास कार्य के लिए वर्ष १९५८–५९ में अब तक बम्बई राज्य सरकार को कितनी धन राशि सहायतार्थ दी गई ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है :

विवरण

योजना का नाम	१९५८–५९ में कुल अनुमित सहायता	अब तक दी गई निधि
	(लाख रुपये)	(लाख रुपये)
(१) पश्चिमी तट की सड़क सहित राज्य की आर्थिक और अन्तर्राज्यिक महत्व की सड़कें . .	६३.००	११.१९
(२) केन्द्रीय सड़क निधि में से जिस सड़क निर्माण कार्य के लिए सहायता दी गई . .	७.००	०.८१

मीन क्षेत्र विस्तार सेवायें

†८९९. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीन क्षेत्र विस्तार सेवाओं ने अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) मीन विस्तार सेवाओं के कार्य को बढ़ाने के लिए आकाशवाणी का कोई लाभ उठाया गया है तो वह क्या है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) केन्द्रीय मीन क्षेत्र विस्तार सेवा विभागों ने देश में मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यों में पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर और दिल्ली की राज्य सरकारों को सहायता दी है :

(१) मछली के अंडे और खुश्क मछली के केन्द्र स्थापित करना।

(२) मछली के अभाव के राज्यों में मछली के अंडों के संभरण की व्यवस्था।

(३) मत्सय पालन के सुधरे हुए ढंगों का प्रदर्शन करना।

(४) मेजर कार्प्स किस्म की मछली के अंडे पैदा करने के ढंगों का प्रदर्शन करना।

(५) मछली पकड़ने के आधुनिक ढंग के कांटे के प्रयोग का प्रदर्शन और तालाबों तथा जलाशयों आदि में मछली पालन के आधुनिक सुधरे हुए साधनों का प्रदर्शन।

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) मछली रक्षण और मछली के उत्पादों के उपयोग के सुधरे हुए साधनों का प्रदर्शन।

(७) सामुदायक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में खंड विकास पदाधिकारियों और ग्रामसेवकों का प्रशिक्षण।

(८) भाषणों की व्यवस्था, सिनेमा प्रदर्शन, पत्रिकायें जारी करके और मेलों तथा प्रदर्शनियों में सम्मिलित हो कर अधिक मछली उत्पादन के आधुनिक सुधरे हुए ंगों को लोक प्रिय बनाना।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य के मीन क्षेत्र पदाधिकारियों द्वारा कभी कभी मछली पालन पर भाषणों के अतिरिक्त मीन क्षेत्र विस्तार सेवाओं को बढ़ाने के लिए आकाशवाणी का और कोई उपयोग नहीं उठाया गया।

केन्द्रीय मीन क्षेत्र प्रौद्योगिकी गवेषणा केन्द्र

†६००. **श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का एक केन्द्रीय मीन क्षेत्र प्रौद्योगिकी गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित केन्द्र कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) इस केन्द्र में मीन क्षेत्र के किस क्षेत्र के सम्बन्ध में गवेषणा की जायेगी ; और

(घ) परियोजना में कितनी पूंजी व्यय का विचार किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) केन्द्रीय मीन क्षेत्र प्रौद्योगिकी गवेषणा केन्द्र अगस्त १९५७ में स्थापित किया गया था।

(ख) यह केन्द्र कोचीन (केरल राज्य) में पहले ही काम कर रहा है।

(ग) यह केन्द्र मछली पालन प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित विभिन्न पहलुओं की खोज करता है :

(१) समुद्र तट और समुद्र तट से दूर के हमारे जलाशयों में जो जाल और ब्योरे उपयुक्त हो सकते हैं उन का अध्ययन और उनका रूप निर्माण ;

(२) जाल आदि बनाने के लिए सामग्री, जालों को रंगने और सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त सामग्री, और नौकाओं तथा पोतों को खराब होने से बचाने की सामग्री की खोज ; और

(३) नौका निर्माण में मछवाहों और अन्य लोगों को सुधरे हुए ढंग तथा साधन सिखाना। ४ सितम्बर, १९५८ से प्रौद्योगिकी केन्द्र के साथ एक माल तैयार करने वाला विभाग संलग्न कर दिया गया है और इस विभाग में निम्नलिखि गवेषणा कार्य किया जायेगा :

१. मछली के तैयार होने की प्रक्रिया की गवेषणा;

†मूल अंग्रेजी में

२. मछली के तेल, मछली के भोजन, मछली के खुरेश आदि मछली के उत्पादों के उपयोग और समुद्री संचार और समुद्र की अन्य वस्तुओं के उपयोगों की गवेषणा ; और

३. मछली के विभिन्न उत्पादों का स्तर और श्रेणी विभाजन तैयार करना और बाजार में बिक्री के लिए मछली और मछली उत्पादों की अच्छी किस्म तैयार करने के हेतु मछली निरीक्षण पद्धति का आधार तैयार करना।

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए २०.३० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

सारडीन मछली से तेल निकालना

†६०१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर उद्योग के आधार पर सारडीन मछली से तेल निकालने पर तेल के उत्पादन बढ़ाने और किस्म में सुधार के लिए क्या खोज की गई है ; और

(ख) मछली का जमा हुआ तेल निर्यात करने के लिए यदि कोई गुंजाइश है तो वह क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तेल निकालने के साधन में सुधार करने के लिए, ताकि अधिक अच्छा उत्पादन हो और तेल की किस्म में सुधार हो, केन्द्रीय समुद्री मीन क्षेत्र केन्द्र, मन्दायम, राज्य मीन क्षेत्र प्रौद्योगिकी गवेषणा प्रयोगशाला, कोजीकोडे और सरकारी तेल फैक्टरी, कोजीकोडे में खोज का कार्य हो रहा है।

(ख) यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में अत्याधिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण मछली के जमे हुए तेल के निर्यात की अधिक गुंजायश नहीं।

नल कूप

†६०२. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सहायता द्वारा अब तक राज्य सरकारों ने कितने नल कूप तैयार किये हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में प्रति नल कूप, औसत निर्माण लागत कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) केन्द्रीय सहायता द्वारा विभिन्न राज्यों में अब तक बनाये गये नल कूप निम्न लिखित हैं :

राज्य का नाम	नल कूपों की संख्या
१. उत्तर प्रदेश . . .	२७०७
२. बिहार . .	६८५
३. पंजाब . . .	१४३९
४. बम्बई	४२३

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी।

डाकखानों में चेक प्रणाली

९०३. **श्री सरजू पांडे** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन डाकखानों में चेक प्रणाली चालू की गई है।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : उत्तर प्रदेश के उन डाक घरों के नामों की एक सूची, जहां चेकों के जरिये रुपया निकालने की प्रणाली चालू की गई है, सभा-पटल पर रखी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९]**

उत्तर प्रदेश में बीज के खेत

९०४. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीज के खेतों (फार्म्स) की स्थापना के लिये वर्ष १९५८–५९ में उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गयी ; और

(ख) वे कौन कौन से खेत हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) ७०.९५ लाख रुपये।

(ख) सन् १९५८–५९ में बीज फार्मों को खोलने के लिये २५४ यूनिटों का लक्ष्य है, जिनमें १५४ मौजूदा फार्म जिनको सुधारा जायेगा और बीज फार्मों के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा और १०० नये फार्म शामिल हैं। मौजूदा फार्मों के नाम, जिनका सुधार किया जा रहा है, नीचे दिये गये हैं :—

फार्म का नाम	यूनिटों की संख्या	ज़िला
केन्द्रीय डेरी फार्म . . .	५	अलीगढ़
माधुरी कुंड . . .	२०	मेरठ
हस्तनापुर	३६	मेरठ
हेमपुर	३८	नैनीताल
भरारी . . .	१५	झांसी
सैंदपुर	७	झांसीं
अन्देशनगर	१३	एल० खेड़ी
धकौनी . . .	२०	हरदोई
	१३४	

नये फार्मों के लिये अभी तक स्थान निश्चय नहीं किये गये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास

९०५. **श्री सरजू पांडे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को कृषि के विकास के लिये वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक कुल कितनी धनराशि दी गयी है ; और

(ख) उक्त अवधि में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि मांगी थी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

९०६. **श्री सरजू पांडे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में उत्तर प्रदेश सरकार को 'अधिक अन्न उपजाओं' आन्दोलन के लिये कितनी धनराशि दी गयी ;

(ख) उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ; और

(ग) उससे 'अधिक अन्न उपजाओं' आन्दोलन कहां तक सफल हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) (क) 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत सन् १९५७-५८ में मंजूर की गई और सन् १९५८-५९ में मानी गई वित्त सहायता निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	ऋण	अनुदान	अल्पकालीन ऋण
१९५७-५८ .	२८८.७९ (नलकूपों के लिये शामिल करके)	८०.३९	२७०.००
१९५८-५९[1] .	३७६.८५ (नलकूपों को शामिल करके)	७०.८८	२००.००

(ख) और (ग). पूछी हुई जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी।

---

[1]मल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खरीदी गई गाड़ियां

९०७. श्री पद्म देव : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष १९५८ में कितनी गाड़ियां खरीदीं ;

(ख) ये गाड़ियां उसने किस एजेन्सी के जरिये खरीदीं ;

(ग) इन गाड़ियों की कितनी कीमत दी गयी ;

(घ) क्या इस काम के लिए कोई टेन्डर मांगे गये थे ; और

(ङ) इन गाड़ियों के ढांचे किस जगह बने थे ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २२ ।

(ख) हिमाचल प्रदेश में मैसर्ज प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई और मसर्ज टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर की एजेन्सियों के जरिए डी० जी० एस० डी० के ठेके की दरों के मुताबिक खरीदी गई।

(ग) ५,६९,२७०.७८ रुपये।

(घ) चूंकि मोटर गाड़ियां[१] ठेके की दरों पर खरीदी गई थीं इसलिए टण्डर मंगाने का सवाल नहीं पैदा हुआ।

(ङ) इन मोटर गाड़ियों के ढांचे अभी तक नहीं बनाए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग

९०८. श्री पद्म देव : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के पास कितनी सवारी गाड़ियां और कितनी माल ढोने वाली गाड़ियां हैं ;

(ख) उनमें से कितनी गाड़ियां चालू हैं ; और

(ग) काम में न आने वाली कितनी गाड़ियां हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १७१ मुसाफिर ले जाने वाली और १६३ माल ढोने वाली मोटर गाड़ियां।

(ख) २७८।

(ग) ५६।

रेलवे में पायदान पर यात्रा

†**९०९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में पायदान पर यात्रा करने में वृद्धि हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Chassis.

(ख) चालू वर्ष में अब तक पायदान पर यात्रा करने के कारण कितनी घातक घटनायें हुई ;

(ग) लोगों के इस अभ्यास को निरुत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) १९५८-५९ में (३०-९-१९५८ तक) २५ ।

(ग) पायदान पर यात्रा को निरुत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है।

(१) स्टेशनों पर विज्ञापनों का प्रदर्शन और गाड़ियों के डिब्बों में सूचनायें लगाना जिन में पायदान पर यात्रा के खतरे बताये गये हैं और यात्रियों से निवेदन किया गया है कि वे पटरी पर यात्रा न किया करें।

(२) जिन स्टेशनों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वहां उन के द्वारा उपरोक्त विषय की घोषणा।

(३) टिकटों का निरीक्षण करने वाले कर्मचारी सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की सहायता से ऐसे अपराधियों को पकड़ते हैं ; और

(४) डिब्बे, गाड़ी के लिए स्थान और लाइन की क्षमता यदि उपलब्ध हो तो वर्तमान गाड़ियों में डिब्बे बढ़ा कर और नई गाड़ियों को चला कर यात्रियों के लिए अधिक स्थान का प्रबन्ध किया जाता है।

दिल्ली में चूहे

†९१०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में सफाई करने और चूहों को मारने का कोई आंदोलन आरम्भ किया गया है, अथवा ऐसा करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) . दिल्ली के स्थानीय निकाय वर्ष भर नगर को साफ रखने और चूहों को मारने के लिये कार्य करते रहते हैं इस कार्य के फलस्वरूप नगर में प्लेग और महामारी आदि रोग गम्भीर रूप में नहीं फैलते।

दिल्ली में असैनिक हवाई अड्डा

†९११. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली में असैनिक हवाई अड्डा स्थापित करने की प्रस्थापना की इस समय क्या स्थिति है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : यह प्रश्न कि दिल्ली में पालम के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अलग अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक हवाई अड्डा बनाना चाहिये अथवा

†मूल अंग्रेजी में

नहीं, अभी विचाराधीन है किन्तु इस बीच जेट हवाई जहाजों के यातायात के लिए पालम हवाई अड्डे को विकसित करने के हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सिंचाई परियोजनायें

†९१२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में केन्द्रीय सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत सहकारी समितियों को बहुत कम काम दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) १९५१ से १९५६ और ३१ दिसम्बर, १९५७ तक ठेकेदारों और सहकारी समितियों को इन परियोजनाओं में १० लाख और उससे अधिक राशि के कुल कितने काम दिये गये ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) **हीराकुड बांध परियोजना** : इस क्षेत्र में सिवाय एक छोटी समिति के अन्य सहकारी समितियां ठेके लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

दामोदर घाटी निगम : टेण्डर की सूचनाओं को समाचारपत्रों और विज्ञापनों द्वारा प्रसारित किया गया था किन्तु अब तक किसी सहकारी समिति की ओर से उत्तर नहीं मिला।

(ग) **हीरा कुड बांध परियोजना** :

	ठेकेदारों को दिये गये	सहकारी समितियों को दिये गये	कुल ठेकों में प्रतिशतता
	रुपये	रुपये	
१९५१—५६ .	३,७३,५३,९४४	४८,०००	.१२८ (लगभग)
३१-१२-५७ तक .	शून्य		

दामोदर घाटी निगम

	रुपये	रुपये	
१९५१—५६ . . .	१,८२,७९,१५६	शून्य	शून्य
३१-१२-५७ . . .	१३,०३,९८७	शून्य	शून्य

उड़ीसा में नदियों द्वारा यातायात

†९१३. **श्री संगण्णा** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** उड़ीसा राज्य में नदियों द्वारा यातायात के बारे में १५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार से जल विद्युत सर्वेक्षण और इन्जीनियरिंग सर्वेक्षण करने के लिए जो प्रार्थना की गई थी, क्या उसका प्रतिवेदन उड़ीसा सरकार से मिल गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) नहीं, श्रीमान् अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्

†९१४. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९५८ में कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद् की भेड़ बकरी तथा ऊन समिति की जो बैठक हुई थी उसमें ट्वीड़ तथा अन्य ऊनी वस्त्रों और वर्स्टीड कपड़े के लिए बढ़िया ऊन तैयार करने के लिए प्रयत्न करने का निर्णय किया गया था ;

(ख) ऐसे परियोजनों के लिए बढ़िया ऊन तैयार करने के हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी ; और

(ग) ऐसे कार्यों पर कितनी धन राशि के व्यय होने की आशा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद् की बकरी भेड़ तथा ऊन समिति की जो बैठक सितम्बर १९५८ में हुई थी उसमें उसने ट्वीड़ अन्य ऊनी वस्त्रों और वर्स्टीड कपड़े के निर्माण के लिए बढ़िया ऊन तैयार करने के हेतु कोई कार्यवाही करने का निश्चय नहीं किया था। प्रत्युत इसमें टविर तथा अन्य ऊनी वस्त्रों के निर्माण के लिए बढ़ियां ऊन तैयार करने वाली भेडों की नस्ल तैयार करने के बारे में जिन योजनाओं के लिए परिषद सहायता देती है उन की जांच की थी।

(ख) तथा (ग). भेडों की ऐसी नस्लें पैदा करने के लिए जो उपरोक्त परियोजना के हेतु बढ़ियां ऊन तैयार करेंगी निम्नलिखित योजनाओं की मंजूरी दी गई।

योजना का नाम	मंजूर की गई राशि	योजना आरम्भ करने की तिथि
	रुपये	
१. उत्तर प्रदेश में भेड़ पालन गवेषणा पीपल कमेटी स्टेशन	१,४७,३४०	१-३-१९५२
२. जम्मू और काश्मीर में बनिहाल का भेड़ पालन स्टेशन	१,५०,१७०	१-४-१९५६
३. हिमाचल प्रदेश की तहसील रामपुर में सराहन का भेड़ पालन केन्द्र	१,६६,०००	१-१०-१९५५
४. राजस्थान में जयपुर का भेड़ पालन केन्द्र .	९५,३५०	२३-१२-५४

†मूल अंग्रेजी में

५. बम्बई में जोरिया (पाटन) का भेड़ पालन स्टेशन	५८,६२०	१-४-१९५३
६. भेड़ पालन गवेषणा स्टेशन, पूना, बम्बई	२,००,२३०	१-४-१९५२
७. भेड़ पालन केन्द्र नीलगिरी, मद्रास	१,२६,८३०	१-४-१९५३
८. भेड़ पालन स्टेशन कुरीकुप्पी, मैसूर	३०,३००	१-११-१९५६
९. भेड़ पालन गवेषणा केन्द्र, गया, बिहार	७७,८१०	१-१०-१९५३
१०. भेड़ पालन गवेषणा केन्द्र दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल	१९,०७५	३०-१२-१९५७
कुल रुपये	१०,७५,०२५	

हिमाचल प्रदेश में उर्वरकों का वितरण

९१५. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ में अब तक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कितनी कीमत का और कितना रासायनिक उर्वरक वितरित किया ;

(ख) कितना उर्वरक ऋण पर वितरित किया गया ; और

(ग) उर्वरकों पर सरकार ने कितनी सहायता प्रदान की ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) ३२५.५ टन उर्वरकों (सल्फेट आफ अमोनिया और सुपरफोस्फेट) का अभी तक वितरण किया गया है, जिसका मूल्य १,४८,१५९ रुपये है।

(ख) १६८ टन ऋण के रूप में बांटा गया।

(ग) ३५,८०० रुपये की रकम सहायता के रूप में दी गई।

हिमाचल प्रदेश में पशु-पालन व डेनमार्क जैसी दुग्धशाला योजना

९१६. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में पशु-पालन व डेनमार्क जैसी दुग्धशाला योजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस योजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) "डैनिश डेरी फार्म स्कीम" के नाम की कोई योजना हिमाचल प्रदेश में नहीं है। मंडी जिले में कटौला के स्थान पर एक कैटल ब्रीडिंग फार्म चालू कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न नं० ६३९ के उतर में दी गई जानकारी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) कैटल ब्रीडिंग फार्म, कटौला पर अभी तक २,३१,५१६ रुपये खर्च हुए हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

दक्षिण रेलवे पर भोजन-व्यवस्था

†६१७. **श्री वें० प० नायर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे का रेलवे भोजन-व्यवस्था विभाग सामिष भोजन पर निरामिष भोजन के बराबर समुचित ध्यान नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) दक्षिण रेलवे के रेलवे भोजन-व्यवस्था विभाग द्वारा चलाये जाने वाले निरामिष अल्पाहारगृहों और सामिष अल्पाहार गृहों की बिक्री कितनी-कितनी है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) दक्षिण रेलवे के भोजन व्यवस्था विभाग में सामिष भोजन पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) १९५७-५८ के बारे में यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३०]**

चित्तरंजन में प्रोत्साहन देने की योजनायें

†६१८. **श्री राम कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री १५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन में 'परिणामों के आधार पर भुगतान' करने की प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लागू की गयी योजनायें सफल सिद्ध हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम हुए हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) प्रशासन ने हाल के वर्षों में अपने उत्पादन लक्ष्यों से कहीं अधिक उत्पादन करने में सफलता प्राप्त कर ली है।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सिंचाई की योजनायें

†६१९. **श्री राम कृष्ण :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री उन बड़ी और मध्यम आकार की सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा बताने की कृपा करेंगे जिनके द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूरे हो जाने की आशा है?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३१]**

निजाम शूगर फैक्टरी

†६२०. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने निजाम शुगर फैक्टरी के विस्तार के लिये विदेशी मुद्रायें देने का अनुरोध किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम मांगी है ; और

(ग) क्या उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) २९.२२ लाख रुपये।

(ग) जी नहीं। उनका अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं था। राज्य सरकार को यह सलाह दी गयी है कि वह आवश्यक मशीनें भारत में ही बनवा लेने की संभावनाओं का पता लगायें।

पंजाब में भेड़-पालन और ऊन तैयार करने के काम का विकास

†९२१. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेड़ों और ऊन के विकास की योजना को क्रियान्वित करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को कुल कितना रुपया दिया है ; और

(ख) राज्य सरकार ने अब तक कितना रुपया खर्च कर दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

वर्ष	मंजूर की गयी राशि	व्यय की गयी राशि
	रुपये	रुपये
१९५६-५७ .	९६,०५०	५,३१३
१९५७-५८ . . .	१,४८,५००	७,३८९
१९५८-५९ .	७६,०००	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

सड़क विकास योजनाओं के लिये अनुदान

†९२२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७६५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों के खिलाफ़ कोई कार्यवाही की गयी है जिन्होंने सड़कों के विकास की योजना के लिये मंजूर किये गये अनुदानों का उपयोग नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). जी नहीं। अनुदानों का पूरा उपयोग न करने के कारण राज्य सरकारों से मांगे गये हैं

†मूल अंग्रेजी में

और आने पर उचित जाच के बाद विनियोग लेखे, १९५७–५८ में अनुदान संख्या १३०—सड़कों पर पूंजी व्यय (मुख्य शीर्ष "८८') के अधीन प्रकाशित कर दिये जायेंगे। उसके पश्चात् लोक-सभा की लोक लेखा समिति इन लेखों की परीक्षा करेगी और यदि उसने कुछ विचार प्रगट किये तो वह संबंधित राज्य सरकारों के पास भेज दिये जायें।

केरल को चावल का संभरण

†९२३. **श्री इ० ईयाचरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में केरल सरकार को कितना चावल दिया और पिछले वर्ष की तुलना में यह कैसा बैठता है ;

(ख) इस अवधि में खुदरा बाजारों में चावल के भावों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) इन तिमाहियों के प्रत्येक महीने में उचित मूल्यवाली दूकानों से कितने चावल की निकासी हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क)

(टनों में)

	१९५७	१९५८
तीसरी तिमाही . .	६७,२००	*२४,०००
चौथी तिमाही . . .	३३,२००	५,३००

(*इसमें बदले में दिया गया १२ हजार टन चावल भी शामिल है)

(ख) जुलाई और अक्टूबर, १९५८ के बीच थोक भावों में ५ प्रतिशत वृद्धि हुई है। खुदरा भावों में (जिनके बारे में मंत्रालय में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है) वृद्धि कुछ अधिक ही रही होगी।

(ग) जुलाई १९५८ . .	१५,४०० टन
अगस्त १९५८ .	१४,८०० टन
सितम्बर, १९५८ .	१,८०० टन
अक्तूबर १९५८ .	७,८०० टन (प्राक्कलित)
नवम्बर १९५८ .	जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है

रेल की पटरियों पर हथगोले रखने की घटना के बारे में पुलिस की छानबीन

†९२४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) उत्तर रेलवे के नरेन्द्रपुर और मनसा स्टेशनों के बीच रेल की पटरी पर जो नौ हथगोले पाये गये थे क्या उसके संबंध में पुलिस ने अपनी छानबीन पूरी करली ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). भटिंडा की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा छानबीन अब भी जारी है ।

तुगलकाबाद—साहिबाबाद लाइन का सर्वेक्षण प्रतिवेदन

†९२५. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुगलकाबाद—साहिबाबाद लाइन के सर्वेक्षण प्रतिवेदन को अब अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है और क्या प्राक्कलन तैयार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). स्थिति सर्वेक्षण प्रतिवेदन और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है और वह उत्तर रेलवे के वित्तीय परामर्श-दाता और मुख्य प्रशासन अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद विचार के लिये बोर्ड के पास आ जायेगा ।

मोकामा पुल

†९२६. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री २६ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोकामा के निकट गंगा के रेल-व-सड़क पुल पर कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) कुल मिलाकर प्रगति ७८ प्रतिशत रही । प्रगति काफी संतोषप्रद है क्योंकि १४ में से १२ मेहराब खड़े किये जा चुके हैं और १३ वां मेहराब खड़ा करने का लगभग १५ प्रतिशत कार्य भी पूरा हो गया है । पुल की ओर जाने वाले रास्तों पर मार्शलिंग और ट्रांशिपमेंट यार्डों के कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है ।

(ख) जी हां ।

कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न मेमने

†९२७. श्री राम कृष्ण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बहुत ही बढ़िया किस्म की ऊन तैयार करने के लिये यथा-शीघ्र कृत्रिम गर्भाधान द्वारा मेमने पैदा करने की योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना अब किस अवस्था में है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). सरकार ऐसी किसी भी योजना पर विचार नहीं कर रही है । भेड़ों को कृत्रिम गर्भाधान कराने के संबंध में इज्जतनगर के इंडियन वेटिरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्राथमिक प्रयोग किये गये हैं । यह इंस्टीट्यूट और आगे जांच जारी रखने के लिये गवेषणा योजना बना कर भारतीय कृषि अवेषणा परिषद् को देने वाला है ताकि वह उस पर विचार करे और उससे वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ते की अखिल भारतीय आरोग्य शास्त्र तथा लोक स्वास्थ्य संस्था

†६२८. **श्री सुबिमन घोष** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते की अखिल भारतीय आरोग्य-शास्त्र तथा लोक स्वास्थ्य संस्था के सिंगूर स्वास्थ्य केन्द्र के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से भारत सरकार को कुल कितनी राशि मिली है ;

(ख) छात्रावास के निर्माण की लागत कितनी है और उसके लिये ली गयी भूमि का क्षेत्र-फल कितना है ;

(ग) यह भूमि कब प्राप्त की गयी ;

(घ) क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों की भूमि ली गयी है उन्हें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है ;

(ङ) क्या यह सच है कि इस भुगतान के लिये पश्चिम बंगाल सरकार १९५४ से ही भारत सरकार से लिखा-पढ़ी करती रही है और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके अन्तिम प्राक्कलन १५ जुलाई, १९५८ को भारत सरकार को भेज दिये थे और उसका स्मरण-पत्र २५ अगस्त, १९५८ को भेजा था ; और

(च) इस प्रकार के भुगतानों में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) सिंगूर केन्द्र, कलकत्ते की अखिल भारतीय आरोग्य शास्त्र तथा लोक-स्वास्थ्य संस्था की एम० सी० एच० योजना का ही एक अंग है । लगभग ९० लाख रुपये लागत वाली एम० सी० एच० योजना भारत सरकार और विश्व/स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने ५०–५० प्रतिशत खर्च देने के आधार पर आरम्भ किया था । सिंगूर स्वास्थ्य केन्द्र के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन/संयुक्त राष्ट्र बाल-आपात निधि ने अलग से कुछ भी राशि नहीं दी है ।

(ख) छात्रावास की निर्माण लागत लगभग २,८६,६४१.०० रुपये है । इसके लिये अधिगृहीत की गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल लगभग ३.४७ एकड़ है ।

(ग) १९५४ में ।

(घ) मुआवजे के भुगतान के लिये आवश्यक मंजूरी दे दी गयी है ।

(ङ) यह सच नहीं है कि इस भुगतान के लिये पश्चिम बंगाल सरकार १९५४ से भारत सरकार से लिखा-पढ़ी करती रही है । प्रति एकड़ भूमि के मुआवजे की दर अन्तिम रूप से जनवरी, १९५७ में बताई गयी थी और मुआवज़े की प्राक्कलित राशि की सूचना अन्तिम रूप से १५ जुलाई, १९५८ को केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गयी थी । यह ठीक है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने २५ अगस्त, १९५८ को केन्द्रीय सरकार को मंजूरी में शीघ्रता करने के लिये लिखा था और मंजूरी दे दी गयी है ।

(च) जिस राशि की सिफारिश की गयी थी उसके ठीक होने न होने के विषय में संबंधित मंत्रालयों से पूछताछ करने के संबंध में जो प्रक्रिया संबंधी औपचारिक कार्य करने पड़े उन्हीं की वजह से यह देर हुई ।

†मूल अंग्रेजी में

शीघ्र बढ़ने वाले फलों के वृक्ष

†९२९. श्री उ० च० पटनायक : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों में शीघ्र बढ़ने वाले फलों के पेड़ लगाने के कार्य को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कुछ कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अधीन हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्रों में फल-उत्पादन के विकास की एक योजना मंजूर की गयी है । इस योजना में सभी प्रकार के फल आ जाते हैं—जिनमें शीघ्र बढ़ने वाले फल भी शामिल हैं ।

(ख) अब तक मंजूर की जा चुकी योजनाओं का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३२]

बदरपुर जंक्शन पर ऊपरी पुल

†९३०. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी सीमा रेलवे के पर्वतीय सेक्शन के बदरपुर जंक्शन पर ऊपरी पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ होने वाला है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां । पैदल चलने वालों के लिये एक ऊपरी पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

नाविकों में बेरोजगारी

†९३१. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नाविकों की बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): नाविकों की नौकरी बीच बीच में चलती-टूटती रहती है । इसका अर्थ है कि नौवहन कम्पनियां एक एक यात्रा के लिये नाविकों को नौकर रखती हैं । यह यात्रायें साधारणतया १२ से १८ महीने की होती हैं और इनके पूरे हो जाने पर वे अपने घरों को वापस लौट जाते हैं और उस समय तक अपने परिवार के साथ रहते हैं जब तक उनको पुनः नौकरी पर नहीं बुलाया जाता । नाविकों के काम दिलाऊ कार्यालयों में जो आंकड़े रखे जाते हैं उनसे पता चला है कि नाविकों को आमतौर पर नौकरी के लिये जितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है उसकी अवधि ६ महीने से अधिक नहीं होती । वास्तव में, यह बताया गया है कि अक्सर ही ऐसा होता है कि नौवहन कम्पनियों की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पातीं क्योंकि नाविक या तो उन्हें काम पर बुलाने के लिये भेजे गये पत्रों का उत्तर ही नहीं देते या चुनाव के लिये नियत दिन पर नहीं पहुंचते । इसलिये, यह कहा जा सकता है कि नाविकों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

डाकखानों से लापता राशि

†६३२. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) १ अप्रैल, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक की अवधि में आसाम के विभिन्न डाकखानों से कुल कितनी राशि लापता होने की खबर है ; और

(ख) इस प्रकार की हानि की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) ४८,४०६.६४ रुपये ।

(ख) पर्यवेक्षण को और भी सख्त कर दिया गया है ।

मलाबार होटल

†६३३. श्री कोडियान : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलिंग्डन द्वीप के मलाबार होटल के वर्तमान पट्टाधारी का पट्टा जून, १९५९ में समाप्त हो जायेगा;

(ख) क्या सरकार का होटल को पुनः पट्टे पर देने का इरादा है;

(ग) क्या होटल को सीधे अपने आप चलाना सरकार के लिये संभव नहीं है; और

(घ) वर्तमान कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये सरकार पट्टे के संविदे में क्या क्या गारंटियां शामिल करने वाली है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख), जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सरकार नये पट्टे की शर्तों में यह शर्त भी शामिल कर लेने के प्रश्न पर विचार करेगी कि ठेकेदार को यथासंभव होटल के वर्तमान सभी कर्मचारियों को काम पर रखना होगा ।

माल का तस्कर व्यापार

†६३४. श्री कोडियान : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के कुछ अधिकारियों के खिलाफ दुराचरण और सीमा-शुल्क विनियमों के विरुद्ध माल का तस्कर व्यापार करने के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है; और

(ग) संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) से (ग) जी हां। इस बारे में जो पूछताछ की गई है उस से पता चला है कि बम्बई में हाल ही में ऐसी दो घटनायें हुई हैं जिन में एयर इंडिया इंटरनेशनल के विदेशों में रहने वाले दो अधिकारियों की भारत पहुंचने पर की गयी सीमा-शुल्क सम्बन्धी घोषणाओं में अनियमिततायें पाई गयी थीं। ये दोनों मामले अभी सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पंचनिर्णयाधीन हैं। एयर इंडिया इंटरनेशनल के कुछ अधिकारियों के खिलाफ जिन आरोपों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है उन की सूचना जांच और समुचित कार्यवाही के लिये कारपोरेशन को दे दी गयी है।

जल-संभरण योजना

†९३५. श्री पहलेकर: क्या रेलवे मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने मनमाड की संयुक्त जल संभरण योजना के व्यय के अपने अंश के भुगतान की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अखिल भारतीय योग स्वास्थ्य विचार गोष्ठी

†९३६. डा० राम सुभग सिंह: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में एक अखिल भारतीय योग स्वास्थ्य विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस विचार गोष्ठी के लिये कुछ सहायता दी थी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) इस मंत्रालय को विचार गोष्ठी द्वारा की गयी सिफारिशों के बारे में कुछ नहीं मालूम।

(ग) जी नहीं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान में से भारत सेवक समाज (दिल्ली) को १९५६-५७ में फर्नीचर और उपकरण खरीदन के लिये १०,००० रुपये की जो राशि मंजूर की गई थी उस में से ७,५९६ रुपये बाकी बचे थे। समाज को इस राशि का उपयोग योग स्वास्थ्य विचार गोष्ठी से संबंधित खर्च पूरा करने में करने की अनुमति दे दी गई थी।

गैस संयंत्र

†९३७. श्री झूलन सिंह: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोबर का बेहतर उपयोग और संरक्षण करने की दृष्टि से पिछले पांच वर्षों में गैस-संयंत्रों के निर्माण और देश के कृषकों द्वारा उन के उपयोग म कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३३]

सामयिक श्रमिक

†९३८. { श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री पांगरकर:

क्या रेलवे मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) रेलवे में १९५० के बाद से प्रत्येक ज़ोन में कितने-कितने सामयिक श्रमिकों को रखा गया;

(ख) सामयिक श्रमिकों को क्रमशः नियमित श्रमिकों के रूप में रख लने के संबंध में कैसी प्रगति हुई है ; और

(ग) कितने मामले एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं !

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): पूरी और ठीक ठीक जानकारी अभिलेखों से उपलब्ध नहीं है ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये सेवा-निवृत्ति वेतन योजना

†९३९. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या रेलवे मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि ३० सितम्बर १९५८ तक कितने रेलवे कर्मचारियों (प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों) ने निवृत्ति वेतन के लिये स्वेच्छा प्रकट की थी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

रेलवे का नाम	३०–९–५८ तक निवृत्ति-वेतन के लिये स्वेच्छा प्रकट करने वाले कर्मचारियों की संख्या				
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	कुल
१	२	३	४	५	६
मध्य .	३७	२८	१,१२५	१,५८८	२,७७८
पूर्व	१७	३०	९७३	७४४	१,७६४
उत्तर . .	११	२४	८७६	१,७८६	२,६९७
उत्तर-पूर्व	१९	११	४६६	५८३	१,०७९
उत्तर-सीमान्त	८	८	१९९	१३४	३४९
दक्षिण .	४४	१९	२,२८९	१,४३०	३,७८२
दक्षिण-पूर्व .	२७	१८	६७१	७५८	१,४७४
पश्चिम . .	१७	१८	१,२९०	१,५६८	२,८९३
अन्य विविध कार्यालयों में	३०	१२	१९०	२७	२५९
कुल .	२१०	१६८	८,०७९	८,६२८	१७,०७५

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय नदी परिवहन समवाय लिमिटेड

†९४०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नदी परिवहन समवाय लिमिटेड ने, जो कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे के आरमेनियन घाट की आऊट एजेन्सी के ठेकेदार हैं, रेलवे प्राधिकारियों की इस प्रार्थना को कहां तक स्वीकार किया है कि पूर्व-वर्ती ठेकेदार के कर्मचारियों की सेवाओं को प्राप्त कर लिया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से बेरोजगार लोग विस्थापित व्यक्ति हैं ; और

(ग) क्या ठेकेदारों से इस आउट एजेन्सी को वापिस ले लेने की कोई परियोजना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) आरमेनियन घाट की आउट एजेंसी के पूर्ववर्ती ठेकेदार अर्थात् मैस्सर्ज पवन विश्वास मोटर सर्विस (प्राइवेट) लिमिटेड के ५६ कर्मचारियों में से ३० को वर्तमान ठेकेदार अर्थात् मैस्सर्ज इण्डियन रिवर ट्रांस्पोर्ट कम्पनी लिमिटेड ने काम पर लगा लिया है ।

(ख) यद्यपि पूर्ववर्ती ठेकेदार के उन कर्मचारियों ने, जिन्हें अभी तक काम पर नहीं लगाया गया है, यह अभ्यावेदन किया है कि वे विस्थापित व्यक्ति हैं, तथापि अभी तक इस बात की पड़ताल नहीं की गयी है ।

(ग) अब यह निर्णय कर लिया गया है कि ठेकेदारों से आउट एजेन्सी वापिस लेकर स्वयं विभाग द्वारा उसे शहर के बुकिंग आफिस के समान ही चलाया जायेगी।

इण्डिया शुगर एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड

†९४१. **श्री अगाड़ी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डिया शुगर एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड के मैनेजिंग एजेन्टों द्वारा १९५७-५८ में उन क्षेत्रों से जिनका पंजीयन नहीं किया गया है, कुल कितना गन्ना खरीदा गया था ;

(ख) क्या काश्तकारों को पूरी-पूरी राशि अदा कर दी गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) ६५,५२२ मन ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में बेदखली

†९४२. **श्री दशरथ देब** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में त्रिपुरा के उदयपुर के रक्षित जंगलों से कितने व्यक्तियों को बेदखल किया गया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार और बेदखल किया गया है ;

(ग) उनमें कुल कितने मुसलमान हैं ;

(घ) क्या इन लोगों में से कुछ एक के वहां पर पक्के मकान भी थे जहां से उन्हें निकाला गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्हें कोई प्रतिकर दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) किसी को भी बेदखल नहीं किया गया है, परन्तु ३८५ ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालयों में मामले दायर किये गये हैं जिन्होंने रक्षित वनों में अधिकार जमाने का प्रयत्न किया था।

(ख) ५४ गिरफ्तार किये गये हैं और ५० का निष्कासन किया गया है ।

(ग) वे सभी मुसलमान हैं ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते क्योंकि किसी का भी निष्कासन नहीं किया गया है ।

रास्ते में गुम हुई सम्पत्ति

†९४३. **श्री प० ला० बारुपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, १९५७ से अगस्त, १९५८ तक की अवधि में बीकानेर और अजमेर डिवीजनों में वस्तुओं के लाने और ले जाने के दौरान सम्पत्ति की होने वाली हानि के लिये कितने और कितनी कीमत के दावों के आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितनी कीमत के दावे स्वीकार कर लिये गये हैं ;

(ग) कितनी सीमा तक दावे अदा किये गये हैं ;

(घ) ऐसे दावों की कुल कितनी कीमत है जिनकी पुष्टि नहीं हुई है ; और

(ङ) उन सम्पत्तियों की हानि में कौन कौन सा अभिकरण जिम्मेवार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क)

	अजमेर डिवीजन	बीकानेर डिवीजन
दावों की संख्या	४,५८४	७,७८७
दावों की कीमत . . .	लगभग १० लाख रुपये	लगभग ७ लाख रुपये
(ख) और (ग) . .	१,११,२५१ रुपये	५,०२,१२३ रुपये
(घ)	लगभग २ लाख रुपयों के १७८ दावे	लगभग ६४,००० रुपयों के ७०२ दावे

(ङ) उनके मुख्य मुख्य कारण ये हैं : (१) चोरियां और मोटी छोटी चोरियां (२) सामान को गलत स्थानों पर पहुंचाना और स्थानों पर उलट देना और (३) गलत तरीके से निशान लगाने, लेबल लगाने तथा पैक करना ।

हिमाचल प्रदेश में उद्यान विज्ञान का विकास

†९४४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५८–५९ में अभी तक उद्यान विज्ञान के विकास के लिये कितनी राशि दी गयी है ; और

(ख) किन किन योजनाओं को मंजूरी दी गयी है और उन्हें कार्यान्वित किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) हिमाचल प्रदेश में १९५८–५९ को अभी तक उद्यान विज्ञान के विकास के लिये ६,१४,५०० पये मंजूर किये गये हैं ।

(ख) निम्नलिखित योजनाओं को मंजूर किया गया है :—

(१) फलोत्पादन का विकास ।

(२) उद्यान मालियों का प्रशिक्षण ।

(३) महत्वपूर्ण फलों के गवेषणा-कार्य को सघन बनाना ।

(४) रेजिन अंगूर के गवेश्गा कार्य को सघन बनाना ।

(५) नरसरी केन्द्रों की स्थापना ।

(६) फल विकास योजना ।

(७) फल गवेषणा योजना ।

ये सभी योजनायें इस समय चल रही हैं ।

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में कुकुटादि का पालन

†९४५. **श्री कुम्भार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिल्ली के लिये एक राजकीय सहायता प्राप्त वैज्ञानिक आदर्श कुकुटादि पालन योजना प्रारम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्योरे क्या हैं ;

(ग) इस योजना के अधीन मुर्गीखाने स्थापित करने के लिये अभी तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और कितनों को स्वीकृति दी गयी है ;

(घ) स्वीकृत आवेदनकर्ताओं में से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ; और

(ङ) प्रत्येक आवेदनकर्ता को राजकीय सहायता के रूप में कितनी राशि और सामान दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) 'वैज्ञानिक मुर्गीखानों को राजकीय सहायता प्रदान करना' नामक एक योजना प्रारम्भ की गयी है ।

(ख) इस योजना के अधीन यह प्रस्थापना है कि वैज्ञानिक रूप से स्थापित किये गये मुर्गीखानों को उन पर आने वाले कुल खर्च का ५० प्रतिशत अथवा २ रुपये प्रति पक्षी के हिसाब से सहायता दी जाये । वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रैस एण्ड एक्सटेंशन स्टाफ के द्वारा संभावित मुर्गीखाने स्थापित करने वालों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं ।

(ग) १०,१०० आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से १०,००० को स्वीकार कर लिया गया है ।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता कि क्या आवेदनकर्त्ता अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य हैं ।

(ङ) आवेदनकर्त्ताओं को अभी तक कुछ भी नहीं अदा किया गया है ।

भाखड़ा कैचमेन्ट क्षेत्र में भूमि संरक्षण

†९४६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा कैचमेन्ट क्षेत्र में भूमि संरक्षण सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). यह निर्णय किया गया है कि वर्तमान योजना के अन्तिम दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश में तीन और पंजाब में तीन प्रदर्शन केन्द्र

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थापित किये जायें और उन पर कुल २० लाख रुपयों की लागत आयेगी । वे योजनायें निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित की जायेंगी :—

पंजाब—(१) नंगल और किरातपुर के बीच नंगल हाइडल चेनल के ऊपर के क्षेत्र में ।

(२) जिला कांगडा की हम्मीर पुर तहसील में लुंखार खाद के कैचमेन्ट क्षेत्र में ।

(३) काडा घाट से नीचे गम्बर खाद के कैचमेन्ट क्षेत्र में ।

हिमाचल प्रदेश :

(१) नंगल हाइडल चैनल के कैचमेन्ट क्षेत्र में पंजाब प्रदर्शन परियोजना के ऊपर हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले क्षेत्र में ।

(२) पंजाब प्रदर्शन परियोजना के नीचे श्राक के आस पास गम्बोर खाद के क्षेत्र में ।

(३) सीर खाद के कैचमेन्ट क्षेत्र में राज्य सरकारों से स्वीकृति के लिये योजनायें भेजने के लिये कहा गया है ।

२.—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये तीन भूमि परिरक्षण योजनाओं—दो पंजाब के जिन पर ८·१६ लाख रुपये और एक हिमाचल प्रदेश में जिस पर ३.०० लाख रुपये खर्च आयेंगे—के लिये पहले ही मंजूरी दे दी गयी है ।

होम्योपेथिक कालेज

†९४७. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अभी तक उन राज्य सरकारों को कोई राशि प्रदान की गयी है जो कि होम्योपेथिक कालेज और गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके राज्यवार व्योरे क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर में फलों को डिब्बों में बन्द करने की फैक्टरी

†९४८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में फलों को डिब्बों में बन्द करने की एक फैक्टरी प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्थापना को अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). इम्फाल के निकट कृषि फार्म में प्रदर्शन के लिये एक फल प्रशिक्षक यूनिट प्रारम्भ करने की योजना अभी भी मनीपुर प्रशासन के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति

†६४६. **श्री वाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में नवम्बर, १६५८ में रामपुर में भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें किन किन विषयों पर चर्चा की गयी थी और उस द्वारा क्या क्या सिफारिश की गयी थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें मांगी गयी जानकारी निहित है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४**]

गोदी में उतारा गया परन्तु बाद में खोया गया सामान

†६५०. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १६५८ से ३१ अक्तूबर, १६५८ तक की अवधि में बम्बई की गोदियों में कितना सामान जहाजों से उतारा तो गया था, परन्तु बाद में खो गया था ; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५**]

मछली पकड़ना

†६५१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में केन्द्रीय मछली पकड़ने वाले स्टेशन द्वारा वाज किनारे पर मछली पकड़ने की संभावनायें खोजी जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी इतनी जल्दी परिणाम बताने कठिन हैं ।

सप्ताह में दो बार चलने वाली गलियारे वाली गाड़ियां[1]

†६५२. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हावडा और दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली वेस्टीबुल्ड गाड़ियों की आराम कुरसियों पर बैठ कर यात्रा करने वाले यात्रियों से अप्रैल से सितम्बर, १६५८ तक कितनी राशि प्राप्त हुई है और उन पर इसी अवधि में कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : हावड़ा और दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक्सप्रैस गाड़ियों की आराम कुर्सियों में यात्रा करने वाले यात्रियों से अप्रैल से सितम्बर, १६५८ के बीच ६.८ लाख रुपये प्राप्त हुए थे ।

किसी विशेष गाड़ी अथवा किसी विशेष श्रेणी द्वारा कमाई गयी राशि अथवा उन पर आने वाले खर्च का हिसाब लगाना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Vestibuled Trains

पर्यटन कार्यालय

†९५३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कुल कितने पर्यटन कार्यालय हैं ; और

(ख) इस समय उन कार्यालयों में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) भारत सरकार का शिमला में एक पर्यटन कार्यालय है। पंजाब सरकार ने पठानकोट, कुल्लू और मनाली में पर्यटन ब्यूरो स्थापित किये हैं। पंजाब अभी हाल ही में नंगल में भी एक पर्यटन ब्यूरो स्थापित करने की मंजूरी दी है, आशा है कि वह ब्यूरो शीघ्र काम प्रारम्भ कर देगा। पंजाब सरकार द्वारा स्थापित किये गये सभी ब्यूरों पर आने वाले खर्च में से आधा खर्च केन्द्रीय सरकार दे रही है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी पर्यटन केन्द्र नहीं है परन्तु हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने शिमला हेडक्वार्टर में एक स्वागत कर्ता और चम्बा, मण्डी और नाहन में पर्यटकों की सहायता के लिये एक गाइड नियुक्त किया गया है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]।

नये डाक व तार घर खोलना

९५४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ के बजट में नये डाक-घर, तार-घर, टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन-घर खोलने के लिये अलग-अलग कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ख) किस-किस परिमण्डल को किस-किस मद के लिये कितनी राशि दी गई ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). इस विषय में सूचना प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होते ही यह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे फैक्टरियों में विदेशी कर्मचारी

†९५५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे वर्कशापों में कितने विदेशी कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) क्या वे ठेके के आधार पर काम कर रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २३४.

(ख) ७ व्यक्ति ठेके पर।

उत्तर रेलवे की गाड़ियों का पटरी से उतर जाना

†९५६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में १ अप्रैल, १९५७ से ३० सितम्बर, १९५८ तक की अवधि में कितनी बार माल गाड़ियां पटरी से उतर गयी थीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उससे रेलवे को कितनी हानि हुई थी ; और

(ग) गाड़ियों के पटरी से उतर जाने के क्या-क्या कारण थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २६६।

(ख) लगभग ४ लाख रुपये ।

(ग) उनके कारण निम्नलिखित हैं :—

	मामलों में
(१) रेलवे कर्मचारियों की गलतियां	१८९
(२) रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की गलतियां	२
(३) पटड़ी की खराबी से	६
(४) मेकेनिकल उपकरणों की खराबियां	३८
(५) अन्य विविध कारण	२५
(६) अभी तक विचाराधीन	६
	२६६

रेलवे सम्पत्ति की चोरियां

†६५७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में उत्तर रेलवे में रेलवे सम्पत्तियों की चोरी के सम्बन्ध में क्या स्थिति रही है ; और

(ख) क्या चोरियां इससे पहले के दो वर्षों की अपेक्षा बढ़ गयी हैं या कि कम हो गयीं हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) गत दो वर्षों में उत्तर रेलवे में रेलवे सम्पत्तियों की चोरियों के निम्नलिखित मामले दर्ज किये गये हैं :—

१९५६–५७	७३६
१९५७–५८	११३८
कुल : . . .	१८७४

(ख) इससे पहले दो वर्षों में मामलों की संख्या २१५१ थी, अतः स्पष्ट है कि उसके बाद के दो वर्षों के मामलों की संख्या कम हो गयी है। फिर भी गत वर्ष मामलों की संख्या में होने वाली वृद्धि की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

अनधिकृत खेती

९५८. { श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में चकबन्दी के समय सार्वजनिक उपयोग के लिये छोड़ी गयी भूमि पर कितने व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से खेती करनी शुरू कर दी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : जानकारी मंगाई गई है और उपलब्ध होते ही सभा की टेबल पर रख दी जायेगी ।

इम्फाल के सिविल अस्पताल

†९५९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इम्फाल के सिविल अस्पताल के एक्स रे संयंत्र की मरम्मत कर दी गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जी, हां । इम्फाल के सिविल अस्पताल के एक्स रे सं की मरम्मत कर दी गयी है ।

उत्तर रेलवे की अकबरपुर—टांडा लाइन

†९६०. **श्री कालिका सिंह** : क्या रेलवे मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर अकबरपुर-टांडा की उखड़ी हुई रेलवे लाइन को पुनः बिछाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कुल अनुमानित लागत के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या इस कार्य को पुनः करने और उसके पूरा होने के लिये कोई समय निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) इस रेलवे लाइन को पुनः बिछाने की वित्तीय अन्तर्ग्रस्ततायें और उसके लागत के आवंटन पर अभी बोर्ड परीक्षण कर रहा है ।

(ग) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दक्षिण भारतीय रेलवे में डीजल कोच

†९६१. **श्री संबंदम्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर अच्छी अवस्था में चलने वाले डीजल चालित डिब्बे कितने हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या मांग को पूरी करने के लिये विदेशों से डीज़ल चालित डिब्बे मंगाये जाते हैं ; और

(ग) क्या ट्रंकबार और सेम्बनार कोइल की जनता द्वारा ट्रंकबार मायाडैयु लाइन पर डीजल चालित डिब्बे चलाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) १२ब्राड गेज और १४ मीटर गेज ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

ओड़िहार रेलवे स्टेशन पर ऊपर का पुल

†९९२. श्री सरजू पांडे : क्या रेलवे मंत्री १४ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ओड़िहार रेलवे स्टेशन पर ऊपर के पुल के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : इस्पात का ढांचा खड़ा करने का काम जल्द शुरु होने की आशा है ।

आशा है कि लगभग अप्रैल, १९५९ तक यह पुल तैयार हो जायेगा ।

भारत–तिब्बत सड़क

†९९३. श्री हेम राज : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान तिब्बत रोड पर १९४८ से अभी तक कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(ख) इस अवधि में कितने मील लम्बी सड़क बनाई गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मार्च १९५८ तक १.८८ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं । चालू वर्ष के लिये बजट में ३५.०० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

(ख) शिमला से आगे मोटर चलने योग्य सड़क . . . . ९४ मील ।

तत्पश्चात् जीप के योग्य सड़क . . . . १६ मील । . . . . . .

५३ मील का एक और टुकड़ा भी तैयार किया गया है ।

विमान निगमों में महिला कर्मचारी

†९९४. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें एयर इण्डिया इंटरनेशनल और इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन में आज कल काम करने वाली महिलाओं की संख्या, उनकी शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति की श्रेणी और कार्य का स्वरूप दिया गया हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली टेलीफोन ऐक्सचेंज

९९५. { श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज का नम्बर "९९" और "०" अधिकांशत: घिरा रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के अन्य नम्बर लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां, कभी-कभी व्यस्त-समय में ।

(ख) इसके लिये ऐसे और अधिक साधनों के मंजूर किये जाने का विचार है।

(ग) लगभग दो-तीन महीनों में ।

कांडला के निकट गांधीधाम का विकास

†९९७. श्री सोमजी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २८ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधीधाम में केन्द्रीय सरकार और सिन्धु पुनर्वास निगम द्वारा अलग-अलग कौन-कौन से क्षेत्रों का विकास किया गया है; और

(ख) विकास भूमि की बिक्री के लिये दोनों द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें और दाम क्या हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाकाल सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अंदमान और निकोबार द्वीप समूह मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं मोटर-गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अंदमान और निकोबार गजट में प्रकाशित, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह मोटर गाड़ी नियम, १९३९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या १२२/५८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १०७८/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन निकाले गये आदेश

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(१) पूर्व गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(२) पश्चिम गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) के टाडेपल्लीगुड्म के कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(३) पश्चिम गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) के थानुकू में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(४) पश्चिम गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) के निडादवोल में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(५) पश्चिम गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) के चेबरोल में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(६) पश्चिम गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) के एलूरु में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(७) पश्चिम गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) के भीमावरम् में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(८) गुंटूर जिले (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(९) श्रीगंगानगर जिले (राजस्थान) के कुछ व्यापारियों को दिये गये चने के अधिग्रहण के आदेश।

(१०) श्रीगंगानगर जिले (राजस्थान) के कुछ व्यापारियों को दिये गये चने का भण्डार बताने के आदेश।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १०७९/५८]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्री अ० म० थामस** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(१) जी० एस० आर० संख्या ८३३, दिनांक १९ सितम्बर, १९५८।

(२) मनीपुर खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ अक्तूबर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ८८९।

(३) कलकत्ता गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १५ अक्तूबर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ९७२।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) चावल (उत्तरी महाखण्ड) नियंत्रण यातायात आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १५ अक्तूबर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ९७३।

(५) बिहार खाद्यान्न (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १००९।

(६) जी० एस० आर० संख्या १०३०, दिनांक १ नवम्बर, १९५८।

(७) चावल और धान (पश्चिमी बंगाल) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २९ अक्तूबर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०४८।

(८) जी० एस० आर० संख्या १०४९, दिनांक १ नवम्बर, १९५८।

(९) दिनांक १ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या १०५०, जिसमें पश्चिमी बंगाल गेहूं (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८ दिया गया है।

(१०) दिनांक १ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०५१, जिसमें आयात किये हुए खाद्यान्न (अनधिकृत बिक्री पर रोक) आदेश, १९५८ दिया गया है।

(११) चावल (दक्षिणी महाखण्ड) यातायात नियंत्रण आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ४ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०५२।

(१२) दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०८५ जिसमें दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स (आटा नियंत्रण आदेश) आदेश, १९५८ दिया गया है।

(१३) दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०८६ जिसमें राजस्थान बाजरा (निर्यात पर रोक) आदेश, १९५८ दिया गया है।

(१४) चावल (दक्षिणी महाखण्ड) यातायात नियंत्रण आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०८७।

(१५) दिनांक १७ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०९० जिसमें चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १०८०/५८]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश मिले हैं :—

(१) कि लोक-सभा द्वारा १७ नवम्बर, १९५८ को पारित उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९५८ को राज्य सभा ने अपनी २ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सचिव]

(२) कि लोक-सभा द्वारा १९ नवम्बर, १९५८ को पारित विष (संशोधन) विधेयक, १९५८ को राज्य सभा ने अपनी २ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

†सचिव : मुझे सभा को यह भी बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा २७ नवम्बर, १९५८ की अपनी बैठक में पारित किये गये कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८ की एक प्रति संलग्न की है।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक--सभा पटल पर रखा गया

†सचिव : मैं कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८ को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली के बारे में याचिका

†श्री दशरथ देव (त्रिपुरा) : मैं त्रिपुरा के २६५३ विस्थापित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका, जो उनसे ऋण की वसूली के बारे में है, उपस्थापित करता हूं।

व्यापार की वर्तमान प्रवृति के बारे में प्रस्ताव--जारी

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा ३ दिसम्बर, १९५८ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

"कि भारत के निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति और कपड़ा उद्योग, जो इस व्यापार के मुख्य रूप से योग देता है, की स्थिति पर विचार किया जाये।"

श्री रामजी वर्मा अपना भाषण जारी करें।

†श्री तंगामणि (मदुरै) : इस प्रस्ताव के लिए ६ घण्टे का समय निर्धारित किया गया था। कल माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि समय बढ़ा दिया जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : इसके लिए ४ घण्टे शेष हैं। मैं एक घण्टा और बढ़ा दूंगा। आज ५ बजे तक हम इसी पर चर्चा करेंगे।

श्री रा० क० वर्मा (निमाड़) : श्रीमान, शासन की सहायता के लिए और सदन की जानकारी के लिए मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। उनकी कल मैं ने अपने भाषण में शुरूआत की थी।

आज हमारे सामने फारिन एक्सचेंज प्राप्त करने के लिए निर्यात करने का और निर्यात करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न है। हमको चाइना और जापान के मुकाबले में अपनी टैक्सटाइल इंडस्ट्री के निर्यात को दुनिया के दूसरे देशों में बराबर कायम रखना है। ऐसा करने के लिए दो बातें

---

† मूल अंग्रेजी में

बहुत जरूरी हैं। एक तो यह जरूरत है कि हमारा कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन कम हो और दूसरे इंडस्ट्री के अन्दर सेल्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। ये दो चीजें जरूरी हैं।

जहां तक कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन को कम करने का सवाल है उसके लिए हमारे यहां यह ट्रेंड चल रही है कि मजदूरों को कम किया जाये, टैक्स की छूट प्राप्त की जाये, बैंकों से सहायता दी जाये वगैरह वगैरह। यह चीज़ कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन में कमी करना नहीं होता बल्कि एक तरह से मिसमैनेजमेंट को प्रोत्साहन देना होता है ।

दूसरी तरफ सवाल आता है रेशनेलाइजेशन का, माडरनाइजेशन का, मशीनों के आधुनी-करण और नवीनीकरण का और इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर हमें सेल्समैन स्पिरिट को इंडस्ट्री में कायम करना है, अगर हमको जापान और चाइना के मुकाबले में दूसरे देशों में अपने माल की खपत करना है, तो उसके लिए रेशनेलाइजेशन और माडरनाइजेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना बहुत गड़बड़ हो रही है।

इस संबंध में आज हो क्या रहा है इसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। रेशनेलाइजे-शन, नवीनीकरण और आधुनीकरण के नाम पर आज मजदूरों की छटनी करते हैं, लेकिन जो मिल मालिकों के सगे सम्बन्धी होते हैं, साले बहनोई होते हैं, मामा फूफा होते हैं उन में से मिल के अन्दर किसी को सेल्समैन बना दिया जाता है, किसी को कैशियर बना दिया जाता है और उनको पांच पांच, चार चार और तीन तीन हजार रुपये महीना वेतन दिया जाता है, और ये लोग क्लबों में जाकर ब्रिज खेलते हैं या चौपाटी पर जाकर सैर करते हैं। पर इस तरह से कोई उद्योग नहीं चल सकता। मिस-मैनेजमेंट की भी कोई हद होती है। और इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। उन में से कुछ के उदाहरण में आपके सामने रखना चाहता हूं।

हम यह देखते हैं कि जो कैशियर होता है वह सेठ का सगा होता है। वह स्टेट बैंक से मजदूरों का वेतन लेने जाता है और गिन गिन कर दस दस, पांच पांच और एक एक रुपये के नोट थैली में रख कर लाता है। लेकिन जब वह वापस आकर कैश विभाग में खड़ा होता है और उस थैली को खोलता है तो नोटों के बजाये कागज के टुकड़े थैली में से निकलते हैं, और जब यह चीज सामने आती है तो उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता। स्टेट बैंक तो सरकारी बैंक है। वहां से नोट गिन कर लाये जाते हैं, उन नोटों के वहां पर नम्बर भी दर्ज होते हैं। लेकिन थैली में से कागज निकलते हैं और मजदूरों को वेतन नहीं मिल पाता। पर कैशियर के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता। उनको माफ कर दिया जाता है ।

इसी तरह से कोई चीज आती है और उसका आक्ट्राय ६ पाई चुकाया जाता है तो मिल से ५०० रुपये और ६ पाई लिया जाता है । पर कोई पूछ नहीं करता। जिस चीज़ पर ६ पाई आक्ट्राय दिया जायेगा वह तो इतनी छोटी होगी कि उसको जेब में लाया जा सकता है, लेकिन जिसका आक्ट्राय ५०० रुपया दिया जायेगा उसको तो ट्रकों में लाना होगा। इस पर मैनेजमेंट को विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ आई है जिसका ५०० रुपया आक्ट्राय देना पड़ा है। पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

इतना ही नहीं। एक्साइज ड्यूटी के रुपये गवर्नमेंट में जमा करने जाते हैं पर जमा करने के बजाये लाख डेढ़ लाख रुपया खा जाते हैं, और जब सवाल उठता है तो कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता बल्कि उस मिल के बजाये उनको दूसरे मिल में अधिक वेतन पर रख दिया जाता है । तो जो यह सारा का सारा इस उद्योग में ट्रेंड चल रहा है उस पर विचार करने की जरूरत है। इस मिसमैनेजमेंट पर बहुत सोचने की आवश्यकता है ।

[श्री रा० क० वर्मा]

कल मैं ने आप से कहा था कि एक मिल है और वह प्राफिट नहीं कर रही है। उसका डिप्रिसियेशन नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन वही मिल एक साल में जब २५ लाख का मुनाफा करती है तो वह दूसरी खराब मिल के २५ लाख के शेयर खरीद लेती है। यह दूसरी मिल भी नुकसान कर रही होती है। पर इसके शेयर खरीद लिये जाते हैं पर मिल का डिप्रिशियेशन नहीं निकाला जाता और पांच लाख व्याज का दिया जाता है। और जब वह मिल नुकसान देती है तो फिर गवर्नमेंट से सहायता मांगी जाती है। साथ ही जो मिल खरीदी है उस में बम्बई में काम करने के लिए इन्दौर की मिल के आदमी आते हैं और वहां पर चार चार छः छः महीने रहते हैं लेकिन उनकी हाजिरी इन्दौर में लिखी जाती है और उनका वेतन इन्दौर के मिल से दिया जाता है हालांकि वे काम बम्बई में करते होते हैं। यह चीज मेरी समझ में नहीं आती। इसके लिये हमने गवर्नमेंट को भी लिखा, कम्पनी की आथारिटीज को भी लिखा कि यह ४२० हो रहा है लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। उनका जवाब आता है कि ऐसी कोई बात नहीं है।

तो जो यह ट्रेंड चल रही है और जो हमारा कानून और विचारधारा है इसका कोई मतलब नहीं होता है और अन्त में हमारे सामने एक बात आती है और वह है क्लोजर जिससे मजदूरों की बेकारी बढ़ती है। मैं आपके सामने क्लोजर का एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। एक मिल ने नोटिस लगाया कि अमुक तारीख से इस मिल को बन्द किया जायेगा क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में ट्रेंड अच्छा नही है। लेकिन मैं आपके सामने यह चीज़ पेश करना चाहता हूं कि जिस मिल ने सरकार से टैक्स माफ कराने के लिए और सहूलियतें लेने के लिए क्लोज़र का नोटिस लगाया उसकी हालत क्या है। इस सम्बन्ध में मैं सदन के सामने उसकी जानकारी के लिए वह बैलेंसशीट रखना चाहता हूं जो कि उस मिल ने सन् १९५७ में निकाला है। इस मिल को खड़ा करने में मालिकों ने ३० लाख ९१ हजार रुपया लगाया। उस मिल में एक पाई अपने जेब से या बाहर से डाले बिना आज जो प्राफिट है उसके आधार पर उन्होंने अपना शेयर कैपीटल ३०,९१,००० के बजाये ४,३२,७४,२८० कर दिया। यानी उन्होंने तीस लाख से अपना शेयर कैपीटल बिना कुछ अपने पास से या बाहर से लगाये चार करोड़ कर लिया। इसके अलावा जो रिज़र्व है वह ३,१९,०३,३०८ है। इसके अलावा जो उन्होंने दूसरी इंडस्ट्रीज में इनवेस्टमेंट किया है वह ३,८५,००,००० है। इसके अतिरिक्त बैंकों में दो करोड़ डिपाजिट किया है। तो आप देखें कि तीस लाख से इतना सारा मुनाफा किया गया है। आप आगे देखें कि सन् १९५७ में उनका मुनाफ़ा है ९१,९०,००,१६५ और डिप्रिसियेशन जो निकाला है वह है २१,२०,३२९, गवर्नमेंट को टैक्स दिया है ३० लाख, डिवीडेंड बांटा है ३१,७२,७८९ और कमीशन के लिये है ६,८४,१९६, और दान में दिये हैं १२,१३,७५४, और जो सरप्लस उनके पास बचा है वह है १,२७,४८४। यह इस मिल का अन्तिम बैलेंसशीट है। और जिस रोज यह बैलेंसशीट निकलता है उसके दो महीने के बाद वह मिल यह नोटिस लगाता है कि दो महीने के बाद इस मिल को बन्द किया जायेगा क्योंकि आज जो ट्रेंड है इंडस्ट्री का वह नुकसान की तरफ है।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब ऐसी घटनायें हमारे सामने हो रही हैं तो गवर्नमेंट उन पर ऐक्शन क्यों नहीं लेती। और फिर सदन के अन्दर और बाहर यह सवाल आता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, राशनेलाइजेशन किया जाए। श्रीमान्, मैं पूछना चाहता हूं कि यह सब किस के लिए किया जाय? मैं मानता हूं कि देश के लिए फारेन एक्सचेंज प्राप्त करने के लिए, हमारी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, हमारे लोगों को काम देने के लिए या हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर कोई हुक्म दिया जाता है या कोई काम किया जाता है, तो हम सब उसका स्वागत करने के लिए

तैयार हैं। लेकिन जो ट्रेंड है वह दूसरी दिशा की ओर संकेत करता है। जैसा मैंने कल निवेदन किया था हमारे प्राडक्शन का क्या ट्रेंड है, जनता की रुचि किस ओर है तथा हमारी जरूरतें क्या हैं, इस ओर ध्यान न देकर हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की ओर होता है। हमारा ट्रेंड एक्सपोर्ट करने की ओर भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या क्या तरकीब हो सकती है, इस ओर ही हमारा ध्यान है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश नहीं है।

आजकल कहा जाता है कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री के अन्दर क्राइसिस है। श्रीमान्, मैं कहता हूं कि कोई क्राइसिस नहीं है। अगर कोई क्राइसिस है तो वह इंडस्ट्री के चलाने वालों ने, उसके संचालकों ने जानबूझ कर पैदा किया है। एक तरफ टैक्सटाइल वेज बोर्ड बैठा हुआ है, उसके काम में घपला डालने के लिए यह सब काम किया गया है। इसका कारण यह है कि अगर टैक्सटाइल वेज बोर्ड अपने काम में कामयाब नहीं होता है तो मिल मालिकों के चादर ओढ़ कर सोने के दिन आ जाते हैं और अगर वह कामयाब होता है और मजदूरों को कुछ मिल जाता है तो वह उनके मुनाफे में से, उनकी जेब में से मज़दूरों के पेट में जाता है, जिसे वे लोग बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। इस वास्ते वे टैक्सटाइल बोर्ड के काम में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसको यह बतलाने की फिक्र में हैं कि इस इंडस्ट्री में एक क्राइसिस सा है। साथ ही साथ वे गवर्नमेंट से ज्यादा से ज्यादा टैक्सों में छूट लेने की दृष्टि से, ज्यादा से ज्यादा सहायता लेने की दृष्टि से यह सब कुछ कर रहे हैं।

साथ ही साथ यह जो बतलाया जाता है कि ओवर-प्रोडक्शन है, यह बात बिल्कुल गलत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोर्स और मीडियम ज्यादा भरा पड़ा है और फाइन और सुपर-फाइन कम है। फैंट की जो किस्में हैं वे ज्यादा निकाली गई हैं। अगर एवरेज काउंट हमारा लिया जाता है तो ३० और ४० के बीच है। इसके हिसाब से आज जब जनता की मांग और जनता की रुचि को देखा जाता है तो यहां पर यह बताया गया है कि हमारी मिलों के अन्दर ५ अरब २१ करोड़ है वह ५ अरब २१ करोड़ से घट जाएगा क्योंकि हमारा कांउट बहुत कम है। कोर्स और मीडियम का कपड़ा डिमांड के बावजूद भी ज्यादा निकाला गया है। १९५५ के अन्दर जैसा कि टैक्सटाइल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है ९० लाख गज़ धोतियां कोर्स व मीडियम बुनी गई थीं और १९५७ को आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ९० लाख के बजाय १७२० लाख गज़ बुनी गई हैं। इसी तरह से १९५५ में साड़ियां २० लाख गज़ बुनी गई थीं लेकिन १९५७ में २००० लाख गज़ बुनी गई। श्रीमान् हमें देखना है कि आज डिमांड किस चीज़ की है। आज हम देखते हैं कि फैंट और फिनिश्ड माल के लिए लोग आतुर हैं। खादी भंडारों में हम देखते हैं वहां ताला लगा रहता है और लोग बाहर खड़े रहते हैं कि कब खुले। हमें रुचि को देखना चाहिए। फैंट के अगर आप परसेंटेज को देखें तो आपको पता चलेगा कि १९५५ में उसका परसेंटेज दो था, १९५७ के अन्दर वह साढ़े चार हो गया और १९५८ के अन्दर लगभग पांच होने वह जा रहा है।

इस वास्ते हमें विचार करना चाहिये कि हमारा ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। हमें देखना होगा कि हम एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ा सकते हैं। एक तरफ कास्ट आफ प्रोडक्शन कम करने की बात होती है, राशनालाइजेशन की बात होती है और दूसरी तरफ मजदूरों की बेकारी की बात होती है और साथ ही साथ यह बात होती है कि कपड़ा भर दो, ऐसा कपड़ा तैयार करो जिसे कि कोई छुए न या जिस को लेने में लोगों की रुचि न हो। इस वास्ते गवर्नमेंट तथा शासन के लिए सोचने की बात है कि इस टैक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में क्या करने की आवश्यकता है।

जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मज़दूरों ने चार लूम्स चलाना मंजूर कर लिया है, मैं इसका विरोध करता हूं। मज़दूरों ने हमेशा चार लूम्स चलाने का विरोध किया है और वे चार लूम्स चलाना

[श्री रा० क० वर्मा]

नहीं चाहते ह। चार लूम्स चलाने से आप यह न समझें कि कास्ट आफ प्रोडक्शन कम होगा बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि वह बढ़ेगा। चार लूम्स चला कर भले ही आप मज़दूरों में कमी करके कुछ बचा लें लेकिन आपका जो स्कोर परसेंटेज है वह बढ़ जाएगा, जो वेस्टेज है वह सारे का सारा बढ़ जाएगा। इस वास्ते अगर सब बातों पर आप विचार करें तो आपको पता चलेगा कि चार लूम्स चलाना हमारे देश के हित में नहीं है। अगर आप को देश के अन्दर टैक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत करना है और इस इंडस्ट्री को मज़दूरों की, संचालकों की और गवर्नमेंट की देख रेख में चलाना है तो मैं इसके लिए तैयार हूं कि अगर दरअसल इस इंडस्ट्री की हालत खराब है और अगर दरअसल में हम चाहते हैं कि चीन और जापान के मुकाबले हम बाज़ार में खड़े हों तो मिल्स के अन्दर भी आटोमेटिक मशीनरी लगी हुई है उसको वहीं ठहरा दिया जाए और यह भी ठहरा लिया जाए कि एक साल के लिये हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा फारेन एक्सचेंज कमाना है और उस साल के लिये नो कमिशन नो डिविडेंड, नो टैक्स, नो डिप्रिसिएशन होगा। अगर आज हम तय कर देते हैं कि बारह महीने के लिए कोई कमिशन नहीं दिया जाएगा, कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, तो मैं मज़दूरों की तरफ से यह कह सकता हूं कि वे भी बोनस की मांग एक साल के लिये नहीं करेंगे और इस तरह से जितनी भी रकमें इकट्ठी होगी उस रकम के आधार पर हम कास्ट आफ प्रोडक्शन को कम करके जितना भी अधिक से अधिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह से अगर किया गया तो बारह महीने के अन्दर हम काफी फारेन एक्सचेंज प्राप्त कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि मिल मालिक क्या इसके लिए तैयार हैं?

जब यहां पर कम्पनी एक्ट आया था और उस एक्ट के अन्दर जब कमिशन की लिमिट ठहराई गई थी उस वक्त सेठों के छोकरों को मिलों में शामिल कर लिया गया, उनके नाम उनमें दाखिल कर लिये गये और किसी के नाम दो हज़ार, किसी के नाम तीन हज़ार और किसी के नाम चार हज़ार कर दिया गया। इसके साथ ही साथ सैकड़ों मज़दूरों को निकाल बाहर कर दिया गया। यह जो तरीका है काम करने का यह अच्छा नहीं है। वह इस इंडस्ट्री को तरक्की देने का, इसको मज़बूत करने का या फारेन एक्सचेंज कमाने का तरीका नहीं है और यह तरीका हमारे देश को भारी पड़ रहा है। इस वास्ते हमें विचार करना होगा कि यह जो स्पिंडल्स बढ़ रही हैं, लूम्स बढ़ रही है, तथा दूसरी बातें जो नहीं बढ़नी चाहियें वे बढ़ रही हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। हम कहते हैं कि प्रोडक्शन इकट्ठा हो गया है और प्रोडक्शन को फ्रीज किया जाना चाहिये। यह जो हम करते हैं इसको करने से पहले हमें दूसरी बातों पर भी अच्छी तरह से विचार लेना चाहिये।

आज मज़दूर मांग कर रहे हैं कि साप्ताहिक छुट्टी आप रखिये, आप रैस्ट इंटरवल रखिये, पंद्रह अगस्त की छुट्टी इनको दें, गांधी जयन्ती की छुट्टी उनको दें, छब्बीस जनवरी की छुट्टी उनको दें लेकिन इनको माना नहीं जाता है। इसके विपरीत उनको ३६६ दिन —३६५ नहीं —तथा चौबीस घंटे और संडे वर्किंग डे रख करके नाजायज तौर पर दबाया जाता है और उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ काम लिया जाता है। साथ ही साथ कानून भंग किया जाता है और हमारी गवर्नमेंट है जो सारे कानून को शिथिल कर रही है, प्राविडेंट फंड की वसूली रोक रही है, स्टेट इंस्योरेंस में ढिलाई दिखा रही है, फैक्ट्री एक्ट का पालन नहीं करती, पेमेंट आफ वेजिस एक्ट का पालन नहीं करती, कोई श्रम न्यायालय नहीं है और न ही कोई न्याय देने वाला है। मज़दूर सड़कों पर भगवान के भरोसे खड़े हैं या वे इस सदन के भरोसे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर हमें बहुत ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिये और शासन को जिन को सहायता की आवश्यकता है उनको सहायता पहुंचानी चाहिये और आपको मैं मज़दूरों की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।

† **श्री श्रीं० अ० डांगे** (बम्बई नगर–मध्य) : मैं पहले इस समस्या के बजाये हमारी आर्थिक व्यवस्था की मुख्य समस्याओं का ही उल्लेख करूंगा।

हमें निर्यात में धक्का लगा है और अब हम इसको दूर करने का यत्न कर रहे हैं। हमें आशायें दिखने लगी हैं।

माननीय मंत्री ने कहा है कि हमारे निर्यात की कमी का मुख्य कारण यही है कि कतिपय औद्योगिक देशों में मन्दी की स्थिति आ गई थी ; और विशेषकर अमेरिका में मन्दी आ जाने के कारण हमारी स्थिति खराब हुई थी।

हमारी यह प्रवृति सी ही बन गई है कि हम सदैव अपनी आर्थिक व्यवस्था को अमेरिका से ही संलग्न करते हैं। वास्तव में यह बात हमारे निर्यात की कमी से प्रमाणित भी हो गई है।

अमेरिका एक पूंजीपति देश है। वहां की मंदी का प्रभाव यहां भी होता है। मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने यह तथ्य हमारे सामने रखा है कि जब हम अपना संबंध किसी पूंजीपति देश से लगाते हैं तो उस देश की मन्दी का प्रभाव भी हमारे ऊपर भो होता है। इस से स्पष्ट है कि हम पूंजीपति देशों की दया पर ही आधारित हैं। हमारे देश को यह शिक्षा लेनी चाहिये। माननीय मंत्री को यह भो स्पष्टतया कहना चाहियें कि हमें समाजवादी औद्योगिक देशों के सम्बन्धों से कभी हानि नहीं पहुंची।

इसके पश्चात् उन्होंने कहा कि औद्योगिक देशों में निर्यात कम हुआ अतः अविकसित देश भी अधिक आयात न कर सके। किन्तु हमें यह भी तो देखना चाहिये कि समाजवादी औद्योगिक देशों से सम्बन्ध स्थापित रखने से क्या परिणाम निकला ?

इसके पश्चात आप देखें कि हमें बताया गया है कि गत वर्ष रूस ने हमारे देश से अत्यधिक मिर्च खरीदी। पूर्वी यूरोप के देशों ने भी हमारा सामान खरीदा और सारी निर्यात का ४६ प्रतिशत भाग साम्यवादी देशों के कारण हुआ। अतः जब कि साम्यवादी देशों में निर्यात बढ़ी, डालर के देश में निर्यात घटी।

आप मेरी इस बात को "टाइम्स आफ इंडिया" के एक पत्रकार के लेख से प्रमाणित समझें जिसने लिखा है कि समाजवादी देशों से मांग अधिक होने के कारण हमारा निर्यात ठीक बना रहा।

हमें इन सब बातों से शिक्षा लेनी चाहिये। हमें यह बात जान लेनी चाहिये कि पूंजीवादी देश सदैव मन्दी ग्रस्त होते रहते हैं और साम्यवादी देशों में कभी मन्दी का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे देश में भी जो मंदी तेजी के उतार चढ़ाव होते रहते हैं; उससे यह स्पष्टतया यह पता चलता है कि हमारी व्यवस्था भी पूंजीवादी ही है और यह समाजवाद की ओर अग्रसर नहीं कर रही।

हमें स्वतः समाजवाद की ओर अग्रसर होकर समस्या का हल करना होगा। किन्तु मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि हमें तुरन्त ही सारा व्यापार समाजवादी देशों के ही साथ कर लेना चाहिये। यह निकट भविष्य में भी संभव नहीं है। उदाहरणार्थ हम अपनी चाय, चीन या रूस में नहीं बेच सकते। मेरा आशय केवल यही है कि हमें यह देखना चाहिये कि पूंजीवादी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों की क्या प्रतिक्रिया होती है।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री श्री० अ० डांगे]

यदि हम अमेरिका का साहित्य भी पढ़ें तो भी हमें ज्ञात होगा कि पूंजीवादी मन्दी का प्रभाव समाजवादी देशों पर नहीं पड़ा। वह पड़ भी नहीं सकता। पूंजीवादी व्यवस्था सदैव समृद्धि की ओर कभी नहीं जा सकती—वह गिर कर ही रहेगी। पूंजीवादी उत्पादन तथा खपत के अन्तर का उपचार ही नहीं कर सकते। निरन्तर समृद्धि असंभव है। जब भी यहां कभी हम मंदी के संकट से सरकार को अवगत कराते रहे हैं, श्री देसाई यही कहते हैं कि इस विकासोन्मुख देश में मन्दी का क्या काम ? किन्तु अब वही बात सामने है ?

जहां तक वस्त्रों के निर्यात का संबंध है, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने यह नहीं कहा कि चीन की प्रतियोगिता के कारण हमें हानि होती है। किन्तु यहां के एक श्री वाडिया यही प्रचार कर रहे हैं। वे चीन पर ही सारा दोष डालते हैं।

जनवरी-जुलाई, १९५७ में निर्यात होने वाला ४८५४.९ लाख गज वस्त्र कम होकर ३१९९.६ लाख गज ही रह गया। चीन ने तो केवल इंडोनेशिया में ही प्रतियोगिता की। उससे अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यह सारा प्रचार ही गलत है। श्री वाडिया का यह प्रचार आधारहीन है और केवल चीन से संबंध खराब करने के हेतु है।

हमें निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि अफ्रीकी देशों में हमारे निर्यात कम होने का कारण यह है कि यहां हमारे माल के साथ इंग्लैण्ड तथा पश्चिमी जर्मनी के माल की प्रतियोगिता है। इस कारण वस्त्रों के संबंध में चीन की प्रतियोगिता इतनी हानिकारक नहीं है। इंडोनेशिया चीन से इस कारण माल खरीदता है कि चीन वालों ने उन्हें ऋण दिया है। पूंजीवादी देश यह कार्यवाही नहीं कर सकते। चीन वाले इंडोनेशिया की सहायता करते हैं जो कि साम्राज्यवाद से टक्कर ले रहा है। चीन वाले वहां कारखाने लगा रहे हैं। क्या हम ईरान में कारखाने लगा सकते हैं। हम तो स्वतः लंकाशायर से मशीनों का आयात करते हैं। यहां मशीनों वालों को यह शिकायत है कि उनका माल नहीं बिकता।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जो वस्त्र उद्योग मशीनें भारत में बनती हैं उनका आयात नहीं होता।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : मैं तो यह कह रहा था कि आरम्भ में मशीन निर्माताओं की यही शिकायत थी कि पहले पहल उनकी मशीनें ही न बिकीं थीं।

हमें यह देखना चाहिये कि हमारे निर्यात को वास्तविक आघात कहां से पहुंच रहा है और क्यों। यदि हम पूंजीवादी भ्रान्तियों का अनुसरण करेंगे तो हमारी जनता पथभ्रष्ट हो जायेगी। हमारे लिये तो समाजवादी देश ही लाभदायक सिद्ध होंगे।

हमें तेल के प्रश्न पर पूरा विचार करना चाहिये क्योंकि यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

तीसरी बात यह है कि हमारी सरकार जो हल निकालती है वह भी देशहित के लिये उपयुक्त नहीं है। वे सभी कारखानेदारों की सुरक्षा के लिये ही हैं। मैं ऐसे हल कभी भी पसंद नहीं करता। सरकार ने मिल मालिकों को उत्पादन शुल्क में से भी रियायत दी। किन्तु ये लोग तो ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की रियायात नहीं दे सकते। रियायत लेने के बाद भी कपड़े के मूल्य वहां ही हैं जहां पहले थे। यह जानकारी सरकारी पुस्तिकाओं से ही उपलब्ध की गई है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सोमानी** (दौसा) : माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं। १९५५ की अपेक्षा मूल्य कम हैं। वह रियायत भी उपभोक्ताओं को दे दी गई है। माननीय सदस्य की जानकारी गलत है ।

†**श्री अ० श्री डांगे** : अब जो हल भी होता है वह सारा मिल मालिकों के ही पक्ष में। उन्होंने कहा कि जब तक स्वतः चालित करघे नहीं आते तब तक सफलता नहीं मिल सकती। सो वह भी हुआ। किन्तु यह कहना तो गलत है कि इसके अतिरिक्त त्रुटिहीन वस्त्र बन ही नहीं सकते। जो लोग इन बातों को जानते हैं उनके सामने ऐसी बात कहना व्यर्थ है।

†**श्री मनु भाई शाह** : मैं माननीय सदस्य के भाषण में बाधा उपस्थित करना नहीं चाहता था। यह एक तथ्य है। हमें प्रतियोगिता करने के लिये पर्याप्त वस्त्र बनाना है। और उसके लिये स्वचालित करघे ज्यादा अच्छे हैं। विश्व में प्रतियोगिता के लिये हमें उन्हें अपनाना ही होगा।

†**श्री अ० श्री डांगे** : मैं आधुनिकीकरण का विरोधी नहीं हूं किन्तु पूंजीपति आधुनिकीकरण का विरोधी हूं। समाजवादी आधुनिकीकरण का विरोधी नहीं हूं। मैं यह नहीं चाहता कि इसके कारण बेकारी बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ वाले भी इसकी आलोचना करते हैं किन्तु साथ वह भी सरकार का ही देते हैं। मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बुराई के विरूद्ध लड़ें। उन्हें श्रमिको के रक्षण की बात करनी चाहिये। यदि स्वतः चालित मशीनें भी लगें तो हमें 'ग्रे' वस्त्रों का उत्पादन उन से करना चाहिये।

अमेरिका आप के वस्त्र नहीं लेता किन्तु उधर मिस्र कपास देकर आपके वस्त्र लेने को तैयार है। इसी प्रकार से सूडान भी तत्पर है। किन्तु आपकी नीति देश के लिये हानिकारक है ।

हम निर्यात के जो भी करार करते हैं उन में नौवहन की शर्त नहीं रखते। जापान हमारे अयस्क को अपने जहाज़ों में ले जाता है। हमारे जहाज नहीं लेते। इस बात का भी तो ध्यान रखना चाहिये।

आप को चाहिये कि आप इन तीन हजार स्वतः चालित करघों को सरकारी क्षेत्र में ही लगायें इसी से सरकार की विदेशी मुद्रा की सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। किन्तु सरकार ऐसा तो कभी भी न करेगी क्योंकि लाभ तो पहुंचाना है कारखाने वालों को। अतः मेरी प्रार्थना है कि इन करघों को सरकारी क्षेत्र में ही लगाया जाये।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : यह सारी चर्चा ही व्यर्थ है। हमें चीन, जापान आदि से प्रतियोगिता ही क्यों करनी चाहिये? यह विचार ही गलत है। हमें निर्यात के बारे में सोचना ही नहीं चाहिये। हमें देश के गांव गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहिये। यह महात्मा गांधी ने भी कहा है अतः निर्यात की सारी बात गलत है।

†**श्री सोमानी** : श्रीमान्, साम्यवादी दल के नेता ने वस्त्रोद्योग के कुप्रबन्ध के बारे में पर्याप्त बातें कही हैं।

किसी भी उद्योग के कुछ त्रुटिपूर्ण पहलू चुन कर इधर उधर से उसकी आलोचना करना बड़ा आसान है किन्तु क्या यह तथ्य नहीं कि वह देश जो कभी कपड़े का आयात करता अब निर्यात करता है। आज हमारा देश इंग्लैण्ड से भी प्रतियोगिता कर रहा है। कारखाने वालों को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सोमानी]

शोषक, लुटेरे आदि कह देना तो आसान है किन्तु अनुभवी व्यक्ति उद्योग की सफलता की सराहना करेंगे।

श्री डांगे ने तो कहा है कि चीन की प्रतियोगिता साधारण है किन्तु वह जापान के वस्त्रोद्योग वालों की बातें संभवतया नहीं जानते। वे भी कहते हैं कि चीन की प्रतियोगिता से उन्हें पर्याप्त कठिनाईयां हो गई हैं। चीन वाले मूल्यों के आधार पर नहीं चलते। वे देशों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं। जिस पर २½ प्रतिशत का ब्याज लेते हैं। अतः उनकी प्रतियोगिता साधारण नहीं है।

जहां तक स्वचालित करघों का सम्बन्ध है यह तो सब कोई जानता है कि अब सरकारी क्षेत्र के हाथ भरे हैं। उनके पास अनेक काम हैं। अब भी देश में ४० कपड़े के कारखाने बन्द पड़े हैं। यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि उनका प्रबन्ध इतना सरल है तो उनको चला के देख लें।

†श्री श्री० अ० डांगे : क्या शोलापुर के कारखाने की बात माननीय सदस्य भूल गये हैं।

†श्री सोमानी : उस कारखाने का प्रबन्ध हमारे ही संगठन के आदमी चला रहे हैं उसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं। यह तो गैर-सरकारी क्षेत्र की ही सफलता है।

यह ठीक ही है कि कहीं कहीं इस क्षेत्र में त्रुटियां हैं किन्तु हमें सारी समस्या को निष्पक्ष ढंग से देखना चाहिये। हमें इसके अच्छे पहलू भी तो देखने चाहियें।

जो लोग देश के उत्पादन में सहयोग दे रहे हैं उन पर इस प्रकार का दोषारोपण उचित नहीं है। हमें निर्यात के इस प्रश्न को विवादास्पद रीति से कभी नहीं सोचना चाहिये। हमें विदेशी मुद्रा के प्रश्न पर विचार करना है। इस सारी समस्या पर हमें सहयोग के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

जहां तक स्वचालित करघों का सम्बन्ध है इस बारे में भी मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि सरकार पहले यह रुकावटें न लगाती तो आज तक कभी का यह समूचा कार्य क्रम क्रियान्वित हो गया होता। प्रतियोगिता करने के लिये यह आवश्यक है कि यह करघे कारखानों में लगे और लागत कम पड़े।

हमारे देश में जो निर्यात सम्वर्धन समितियां बनी हुई हैं उन पर हम केवल १५/२० लाख रुपया ही व्यय करते हैं। इसका अधिकांश भाग वस्त्रोद्योग परिषद पर व्यय होता है। परन्तु अकेले जापान वाले दो करोड़ रुपया इस कार्य पर व्यय करते हैं। अतः इन के सफलतापूर्वक संचालन के लिये अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझना है। १९५७ में अविकसित देशों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। यह भारी संघर्ष है जिस में सफलता के लिये बड़े परिश्रम की आवश्यकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

युरोपीय एकीकृत बाजार आदि की समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान देना होगा।

निर्यात सम्बंन्धी प्रेरणा देने की जो अन्तिम नीति सरकार ने उद्घोषित की थी वह कारखाने के मालिकों की दृष्टि में अपूर्ण है। वास्तव में कारखाना वालों को निर्यात किये जाने वाले वस्त्रों के

†मूल अंग्रेजी में

लिये शत-प्रतिशत कपास आयात करने के लिये कहना चाहिये। मैं समझता हूं कि वर्तमान रियायतें तो कम हैं।

इसके पश्चात प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों का प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि सरकार निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रस्तावित बातों को मानकर इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करायेगी क्योंकि इन्हीं में पर्याप्त समय व्यय हो जाता है।

सीमेंट के निर्यात के लिये भी सरकार बाहर से कागज के थैले नहीं मंगवा सकी ताकि उन में सीमेंट भरा जाये और निर्यात किया जाये। निर्यात में समय तो बहुत आवश्यक होता है। आयात करने वाले कब तक प्रतीक्षा करते रहें। ऐसी चीजों का प्रबन्ध पहले से ही हो जाना चाहिये।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसात) : हमें ज्ञात हुआ है कि प्रयास के बावजूद भी इस वर्ष सरकार वस्त्रों की निर्यात में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करा सकी। पहले नौ मास में हमारी निर्यात पिछले वर्ष की अपेक्षा ६० या ६५ करोड़ तक कम ही रहेगी। विदेशी मुद्रा के अभाव को देखते हुये यह स्थिति बड़ी गम्भीर है। हमने जो विदेशी मुद्रा के अनुमान लगाये थे वह इसी आधार पर लगाये थे कि हमारा निर्यात उतना ही रहेगा किन्तु जब निर्यात ही कम होता जायगा तब विदेशी मुद्रा का अभाव तथा आवश्यक विदेशी मुद्रा की राशि भी अधिक होती जायेगी। अब पता नहीं कि हमें कितनी कमी और पड़ जाये।

अब द्वितीय योजना की अवधि तक हमारे ऊपर ७०० करोड़ का ऋण होगा और हमें १६ करोड़ ब्याज देना पड़ेगा। इन बातों को देखते हुये भी यह अत्यावश्यक प्रतीत होता है कि हमारा निर्यात अधिक होना चाहिये।

मिलों का कपड़ा तो प्रति मास कम ही निर्यात हुआ और दूसरा वस्त्र ही अधिक निर्यात हुआ। केवल यही नहीं कि निर्यात की मात्रा में ही कमी हुई हो बल्कि उत्पादन में भी कमी हुई है। देश ही के औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है। यह सारे समाचार हमें रिजर्व बैंक के समाचार पत्रों से उपलब्ध हुये हैं।

वस्त्रोद्योग के साथ ही रोजगार की समस्या भी आबद्ध है। कल ही पता लगा कि कुछ कारखाने बन्द हो जाने के कारण ४०,००० मजदूर बेकार हो गये हैं। शनैः शनैः बेकारों की संख्या में वृद्धि होती जायेगी। वास्तव में वस्त्रोद्योग की कठिनाइयां १९५६ से आरम्भ हुईं जब उस पर उत्पादन शुल्क लगा। यह बात जांच समिति ने भी स्वीकार की है। पता नहीं किस कारण से सरकार ने यह पागलपन किया। इसे ठीक ढंग से तो लगाया ही नहीं गया। अतः मोटे तथा बीच के कपड़े पर उत्पादन शुल्क मूल्यानुसार होना चाहिये था—गजों के आधार पर नहीं। यह गलत नीति थी।

श्री डांगे ने सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की बातें कीं। किसी ने यह नहीं कहा कि चीन लागत से भी कम मूल्य पर कपड़ा देशों में भेज रहा है किन्तु हमें चीन की प्रतियोगिता को साधारण नहीं समझना चाहिये। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारा उद्योग चीन वालों से परास्त न हो। श्री डांगे ने कहा कि रूस ने हमारा अधिक कच्चा माल खरीदा। क्या हम कच्चे माल के निर्यातक ही बने रहें। हम इसी स्थिति में सदैव तो रहना नहीं चाहते। हमें तो निर्मित वस्तुओं का ही निर्यात करना है।

सरकार को यह देखना चाहिये कि इन देशों के साथ हमारा संतुलित व्यवहार रहे।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

इसी प्रकार से वैज्ञानिकन के प्रश्न पर भी हमें गम्भीर दृष्टि से विचार करना है लागत कम तभी हो सकती है। हम यह नहीं चाहते कि वैज्ञानिकन के परिणामस्वरूप लोग बेकार हो जायें। इसका ढंग यह है कि वस्त्रोद्योग वालों को लाभांश कम कर के अतिरिक्त श्रमिकों को स्थान देना चाहिये। इसी प्रकार से इस समस्या का हल हो सकता है। आजकल इस उद्योग में पर्याप्त लाभ है।

कच्चे माल में भी चीन हमारे से प्रतियोगिता करेगा। चीन की चाय हमारी चाय से मुकाबला करेगी और हमें हानि होगी। इस कारण हमें भी सतर्कता से कार्यरत रहना चाहिये। जो कारखाने अब बन्द पड़े हैं उनके बारे में भी हमें विचार करना है।

केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकारों को चेतावनी दे कि सूत इत्यादि पर कर लगा कर वस्त्रोद्योग पर पर्याप्त भार पड़ता है। इस से उद्योग को हानि उठानी पड़ती है इस कारण उन्हें उद्योग को प्रेरणा देनी चाहिये।

हमारे विक्रेता अभिकर्ताओं को विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों की रुचियां मालूम करनी चाहियें कि वे किस किस प्रकार के वस्त्र पसन्द करते हैं। हमें जो माल बाहर भेजना चाहिये वह अच्छी कोटि का ही भेजना चाहिये। उसकी मरम्मत इत्यादि की व्यवस्था भी करनी चाहिये। इस प्रकार की सहायता हम बाहर के लोगों से भी ले सकते हैं। हम ऋण देने के प्रश्न पर भी विचार कर सकते हैं।

सरकार को जहाजों के किराये के बारे में भी नौवहन समवायों से बातचीत करनी चाहिये।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : कल सरकार से वस्त्रोद्योग सम्बन्धी एक प्रश्न पूछा गया था। अभी हाल ही में एक ब्रिटिश मिशन भारत आया था और यह प्रश्न भी तत्संबंधी ही था। सरकार ने इस का भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और केवल कुछ गोल मोल बातें कह कर टालमटोल कर दी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार को यह पता न हो कि यहां के कारखानादारों ने उन से क्या बातचीत की है।

वास्तव में कामनवैल्थ आर्थिक सम्बन्ध सम्मेलन में भारत ने यह कहा था कि आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों को अविकसित देश से निर्यात की मात्रा पर कोई सीमा नहीं लगानी चाहिये क्योंकि अविकसित देश उन से पूंजीगत वस्तुयें लेते हैं। यह निर्णय हो गया किन्तु लंकाशायर वाले इस का विरोध करते रहे।

यह बात भी गलत है कि भारत के वस्त्र निर्यात से इंगलैंड के उद्योग को किसी प्रकार का खतरा था। वास्तव में यहां से "ग्रे" कपड़ा वहां जाता है और वहां इस पर थोड़ा काम होता है। और उसे फिर निर्यात कर दिया जाता है। इस से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण यह दुख की बात है कि भारत सरकार लंकाशायर वालों की बात मान गई।

सरकार ने उन के करार के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है। माननीय मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि करार के बारे में उन्हें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

यदि सरकार वास्तव में ही यह नहीं जानती कि वह करार किस प्रकार का है तो हमारा दुर्भाग्य है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हांगकांग जैसा छोटा सा उपनिवेश अब तक लंकाशायर वालों की बात स्वीकार नहीं कर रहा किन्तु हम हैं कि हर बात स्वीकार करते चले जा रहे हैं। वास्तव में अब कामनवैल्थ हमारे लिये एक दायित्व बन गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सन्धि के परिणामस्वरूप ब्रिटिश को हमारे वस्त्रों की निर्यात कम होगी ?

हमें मध्य पूर्व के देशों में अपने माल के निर्यात की व्याप्ति बनानी चाहिये क्योंकि वहां के लोगों के पास धन का अभाव नहीं है। वह अच्छी कोटि का माल चाहते हैं। इस कारण आज वहां रूस अपना माल खपा रहा है। हमें भी वहां माल भेजना चाहिये।

यदि स्वतः चालित करघों को हम गैर-सरकारी क्षेत्र में लगायेंगे तो निश्चय ही बेकारी का चक्र चलेगा और लाखों मजदूर बेकार हो जायेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन स्वतः चालित करघों के बारे में सरकार क्या नीति अपनायेगी ?

†**श्री रंगा** (तेनालि) : श्री डांगे के इस सिद्धान्त का उत्तर देना, कि हमें किन देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये और किन देशों के साथ नहीं, कठिन है। वास्तविक बात तो यह है कि हम स्वयं साम्यवादी देशों के साथ व्यापार करने को तैयार हैं। लेकिन अधिकांश साम्यवादी देशों की स्थिति वही है जो कि भारत की है। उन की अर्थव्यवस्था भी विकासशील है और इसी विकासशील अर्थव्यवस्था के कारण उन के यहां तेजी मंदी या उत्तार चढ़ाव पूंजीवादी देशों की तुलना में कम होते हैं।

वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में श्री डांगे ने यह सुझाव दिया है कि यदि स्वयं चालित करघे लगाना आवश्यक है तो क्यों न ये करघे सरकारी क्षेत्र में लगाये जायें। क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्रों में इन करघों को लगाने से, इस बात की कोई प्रतिभूति नहीं है कि इस का लाभ श्रमिकों और उपभोक्ताओं को मिलेगा। निस्संदेह यह सुझाव विचारणीय है।

वस्त्रों के उत्पादन शुल्क पर जो रियायत की गई है उस का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिला है क्योंकि कपड़े की कीमतों में मुद्रा अनुपात से कमी नहीं हुई है। आशा है माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे।

जहां तक निर्यात बढ़ाने का प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत पुराना है। १९४१–४२ में ब्रिटिश सरकार ने अमेरीका को भारतीय निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी। तत्पश्चात् भी इस सम्बन्ध में समय समय पर कार्य होता रहा। माननीय वाणिज्य मंत्री ने बड़ी स्पष्टता से यह समस्या हमारे सामने रखी है तथापि इस में कई अड़चनें हैं। ये रुकावटें, व्यक्तिगत प्रशासनिक, मंत्रालय व संगठन इत्यादि सम्बन्धी हैं। इस के लिये मैं अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र बिक्री समिति के अध्यक्ष का उदाहरण लूंगा। वे कुछ वित्तीय रियायतें प्राप्त करने के लिये ६ बार अपने व्यय से दिल्ली आये। वह यह आश्वासन दे रहे हैं कि अगले दो वर्षों में वह विदेशों में १ करोड़ रुपये के वस्त्रों की बिक्री करवा सकते हैं, तथापि सचिवालय में उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसी प्रकार तेल तथा तिलहनों पर उत्पादन शुल्क हटाने के लिये हम ने मंत्रालय से कई बार कहा तब कहीं वर्षों पश्चात् यह शुल्क हटाया गया है।

जहां तक राज्य व्यापार निगम का सम्बन्ध है, उस के सम्बध में विस्तृत चर्चा होनी आवश्यक है जिस से उक्त निगम के सुधार के लिये सभी आवश्यक सुझाव दे सकें। इस समय, मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निमम से यह आशा की गई थी कि वह बीच के दलाल या आढ़तियों को हटाने में

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

सहायक होगा लेकिन इस सम्बन्ध में वह कोई ठोस कार्य नहीं कर सका है जैसा कि लोह अयस्क से स्पष्ट है, बल्कि उन को प्रोत्साहन मिल रहा है ।

जहां तक वस्त्र उद्योगो में चीन की प्रतिद्वंदिता का सम्बन्ध में चीन हमारे देश का सब से प्रबल प्रतिद्वंदी है । चीन का वस्त्र निर्यात बढ़ता जा रहा है । हमें भी अपना वस्त्र निर्यात बढ़ाना चाहते हैं। जापान भी यही नीति अपना रहा है । अतः यह तीनों देश एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी हैं । अतः हमें चाहिये कि सरकार, मंत्रालय तथा वस्त्र उद्योग यथा शीघ्र इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर उचित कार्यवाही करें ।

अंत में मेरा सुझाव यह है कि ऐसे अविकसित देशों की, जिन का निर्यात कृषि वस्तुओं पर निर्भर है, एक सम्मेलन करने की संभावनाओं पर विचार किया जाये । इस सम्मेलन के सभी सदस्य देश अवशेष संसार पर इस बात के लिये दबाव डालें कि वह इन देशों के साथ व्यापार शर्तों में उचित परिवर्तन करें साथ ही इन देशों को भी परस्पर समायोजन तथा सहयोग से कार्य करने की संभावना पर विचार करना चाहिये ।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : यदि माननीय मंत्री मुख्य निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आंकड़े हमें देते तो यह चर्चा अधिक सहायक होती ।

यह ठीक है कि १९५६–५७ की तुलना में १९५७–५८ के निर्यात में कमी हुई है । अब सरकार संवर्धन कार्य भी कर रही है किन्तु तब भी निर्यात की मात्रा कम होती जा रही है ।

माननीय मंत्री ने बताया है कि मन्दी के कारण निर्यात की मात्रा में कमी हुई किन्तु रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन से पता चलता है कि इस के कारण और हैं । इस लिये हमें उन कारणों का भी पता लगाना चाहिये । प्रतिवेदन में तो वे कारण दिये नहीं गये । अतः हम जानना चाहते हैं कि वे कारण कौन से हैं ।

स्टर्लिंग क्षेत्र के साथ भी हमारे व्यापार में कमी हो रही है । स्टर्लिंग क्षेत्र के साथ हमारा भुगतान संतुलन भी ठीक नहीं है ।

श्रीमान्, साम्यवादी दल के नेता ने जो यह कहा कि पूंजीवादी देशों के साथ व्यापार करने से हमें हानि होती है यह बात भी व्यर्थ सी है । हमारा ९५ प्रतिशत व्यापार पूंजीवादी देशों के ही साथ है । सारा व्यापार साम्यवादी देशों से तो किया नहीं जा सकता । पूंजीवादी देशों में मंदे आते हैं तथा साम्यवादियों के यहां मंदी नहीं आती इस बात को मैं असंगत समझता हूं ।

इस से तो इन्कार ही नहीं किया जा सकता कि हमारे वैदेशिक व्यापार की स्थिति पूर्णतया खराब है । जब मांग की कमी हो जाती है तब कच्चा माल पैदा करने वाले देशों की स्थिति खराब हो जाती है । अब तो प्रगतिशील पूंजीवादी देश भी स्वरक्षात्मक कार्यवाही कर ही रहे हैं ।

इधर अफ्रीका के देश प्रशुल्क बढ़ा रहे हैं । उधर 'सामान्य बाजार' की स्थापना होने जा रही है इस से हमारे निर्यात पर और भी प्रभाव पड़ेगा । अभी तक हमारी प्रमुख निर्यात की वस्तुयें चाय तथा पटसन ही हैं । भारतीय चाय के निर्यात में भी कमी आ गई है । उधर वस्त्रों के निर्यात में जापान ने हम से अधिक प्रगति कर ली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय के निर्यात की स्थिति को हम तभी बनाये रख सकते हैं जबकि निर्यात करने वाले देशों से किसी प्रकार का समझौता न करें। पटसन की स्थिति तो इतनी बुरी नहीं है क्योंकि पटसन का हमारा उद्योग अत्यंत आधुनिक ढांचे पर बना है।

इस के पश्चात् वस्त्रोद्योग के वैज्ञानिकन का प्रश्न है। साम्यवादी दल के नेता ने कहा है कि वह वैज्ञानिकन के विरोधी नहीं किन्तु पूंजीपति वैज्ञानिकन के विरोधी हैं। इस का क्या तात्पर्य है। समिति भी इस पक्ष में है कि इस के लिये पहले उपयुक्त वातावरण बनाया जाये। इस सम्बंध में सरकार ने जो निर्णय करना हो उसे शीघ्र किया जाना चाहिये क्योंकि हमें अपनी विदेशी व्यापार स्थिति को भी ठीक करना है।

अब मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। सरकार को पहले तो यह निश्चय करना चाहिये कि वह क्या करना चाहती है। अब रेलभाड़ा भी अधिक है इस कारण भी व्यापारियों को बड़ा कष्ट होता है। भाड़े कम करने चाहियें। थोड़ा राजस्व कम हो जायेगा किन्तु निर्यात को तो प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुयें हमें स्वतः निर्यात करनी चाहियें। हमें कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिये। देश में कम खपत करके भी हमें अधिक चीज़ों को बाहर भेजना चाहिये। तभी हमारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। यदि हमें हानि भी उठानी पड़े तो भी उठा लेनी चाहिये। तभी हमारे निर्यात की स्थिति अच्छी हो सकती है।

आज व्यापार संवर्द्धन के निमित्त जो संगठन बने हुये हैं वह भी पर्याप्त नहीं हैं। न ही निर्यात कार्य के लिये कोई एक प्रभारी मंत्री है। जब तक इस विषय पर अविभक्त ध्यान नहीं दिया जाता तब तक यह काम पूरे ज़ोर से नहीं हो सकता।

इसके पश्चात् विभागों में पारस्परिक समन्वय स्थापित करने का भी प्रश्न है। जब रियायतों का प्रश्न होता है तो वित्त मंत्रालय आ टपकता है। जब भाड़ों में रियायत का प्रश्न उठे तो परिवहन मंत्रालय टांग अड़ा देता है। सरकार को यह अनुभव करना चाहिये कि बिना समन्वय तथा सहयोग के कोई भी कार्य पूरा न होगा।

†**श्री मनुभाई शाह :** उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्यों का वाद विवाद का इतना उच्च स्तर रखने के लिये तथा सरकार के सामने ठोस सुझाव प्रस्तुत करने के लिये बड़ा कृतज्ञ हूं। मेरे वरिष्ठ साथी के वक्तव्य का इस सभा में, प्रैस में तथा देश में जितना स्वागत हुआ है उसको देख कर मुझे बड़ा हर्ष आ है इससे यह प्रकट होता है कि यह सभा तथा सरकार तथा हमारे देशवासी इस समस्या की गम्भीरता में कितनी रुचि रखते हैं तथा इसे देश के आर्थिक विकास के लिय कितना महत्वपूर्ण समझते हैं।

सभा के सभी सदस्य भली भांति समझते हैं कि हमारे देश की आर्थिक समस्या के दो बड़े हल हैं। एक हम अपने कृषि उत्पादन को बढ़ायें और दूसरे हम देश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास करें। मैं आर्थिक उत्पादन के महत्व पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। सारा देश जानता है कि हमारे राष्ट्रीय विकास की धुरी इसी पर स्थित है। औद्योगिक विकास का नम्बर भी इसके बाद आता है। हमारा मंत्रालय इस देश के इस दिशा में विकास के लिये उत्तरदायी है।

संसार का कोई भी पिछड़ा हुआ देश विदेशी सहायता के बिना उद्योगों का विकास नहीं कर सकता। सभी स्रोतों को मिला कर सकल घरेलू राष्ट्रीय आय में औद्योगिक विकास तथा व्यापार का हिस्सा एक तिहाई के बराबर है। इसमें हमारा कृषि उत्पादन भी सम्मिलित किया जा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

सकता है जिस पर कि हमारा आयात तथा निर्यात व्यापार निर्भर करता है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस सभा को उचित महत्व देवें।

श्री डांगे ने निर्यात बढ़ाने की योजना के बारे में कुछ बातें कही हैं। इन बातों का उत्तर मेरे मित्र श्री रंगा तथा बिमल घोष ने दे दिया है। सरकार की नीति सदा निर्यात व्यापार को बढ़ाने की नीति रही है। हमने इस व्यापार को जहां भी सम्भव हो सका है बढ़ाने का प्रयत्न किया है। आज हमें इस नीति के प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। अभी हाल में हमारे विदेशी व्यापार के महानिदेशक विदेशों का भ्रमण करने गये हैं। इस दौरे से विभिन्न देशों के साथ जो व्यापारिक करार होंगे उनसे देश को बड़ा लाभ पहुंचने की आशा है। हमारा देश हर देश के साथ स्वतंत्रता तथा समानता के आधार पर व्यापार करने के लिये तैयार है जिससे कि दोनों देशों को परस्पर लाभ हो सकता हो।

अभी अभी मैंने बताया है कि विदेशी व्यापार में वृद्धि के बिना औद्योगिक अथवा आर्थिक विकास होना असम्भव है और खास कर भारत का। इस बात को ध्यान में रखते हुये मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने जो यह सूचना दी है कि अब हमारे निर्यात व्यापार की कमी रुक गई है यह बात बड़ी उत्साहवर्द्धक है। अब हम विश्व बाजार में आने वाली अस्थायी मन्दी से निकल कर पुनः वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।

किन्तु हमें इतने मात्र से सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था हमेशा ऐसी नहीं बनी रह सकती। हम यह चाहते हैं कि हम न केवल अपने निर्यात व्यापार को कम होने दें बल्कि हम प्रति वर्ष ५० करोड़ से १०० करोड़ रुपये तक इसकी वृद्धि करते रहें। यदि हमें द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं के विकास लक्ष्यों को पूरा करना है तब हमको निर्यात व्यापार इतना बढ़ाना आवश्यक है।

विकास के तीन पहलू हैं। सब से पहले भुगतान सन्तुलन का प्रश्न है। यह प्रश्न व्यापार की वृद्धि के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से हल नहीं हो सकता। भुगतान सन्तुलन की समस्या का मुकाबला करने के लिये व्यापार की वृद्धि, विदेशी सहायता तथा विदेशी पूंजी तीन बड़े हथियार हैं। इन सब में व्यापार की वृद्धि सब से महत्वपूर्ण कारक हैं। इसलिये हमने मान्ट्रियाल सम्मेलन, इकाफे सम्मेलन तथा जेनेवा सम्मेलन जहां कहीं भी हमारे देश का प्रतिनिधिमंडल गया है हमने परस्पर व्यापार बढ़ाने पर बहुत बल दिया है। हम यह चाहते हैं कि एशिया के अधिकतर पिछड़े देशों में परस्पर व्यापार की वृद्धि हो जिससे वह अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार अपने देश का आर्थिक विकास कर सकें। मैं समझता हूं सभी सदस्यों की इस नीति से पूर्ण सहमति होगी।

आज हमारे देश का प्रमुख निर्यात व्यापार कच्ची वस्तुओं के निर्यात तथा बाग़ान की फसलों पर निर्भर करता है और मैं समझता हूं अभी कई वर्षों तक हमारा निर्यात इन्हीं वस्तुओं पर निर्भर रहेगा। जब तक कि हम और वस्तुयें नहीं तैयार करने लगेंगे हमारे निर्यात व्यापार का ढांचा नहीं तबदील होगा। निर्यात की मुख्य मुख्य वर्तमान वस्तुओं से हमारी विदेशी मुद्रा में अधिक वृद्धि होने की आशा नहीं की जा सकती। हमें औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा कर अधिकाधिक आवश्यक पूंजी वस्तुओं के निर्यात करने का प्रयास करना चाहिये। हमारे उद्योग ने कभी निर्यात व्यापार की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि इनमें निर्यात व्यापार बढ़ाने की भावना बढ़े। बम्बई में भारत-जर्मन व्यापार संघ की बैठक में बोलते हुये मैंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि हमारे उद्योगपतियों को अधिकाधिक माल बाहर भेजने की कोशिश करनी चाहियें।

प्रत्येक छोटे, बड़े तथा मध्यम पैमाने के उद्योग का यह पहला कर्तव्य है कि वह कुछ न कुछ माल अवश्य बाहर भेजें। इससे हमारे कच्चे माल के आयात में कुछ कमी हो सकेगी और देश का औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ सकेगा। प्रत्येक औद्योगिक संस्था को इस कर्तव्य को सामाजिक कर्तव्य समझ कर निभाने का प्रयत्न करना चाहिये। संसार के सभी देशों में ऐसा हो रहा है। केवल विधि अथवा कार्यपालिका के आदेशों भर से देश का काम नहीं होता। लोगों में स्वतः सामाजिक हित का दृष्टिकोण होना चाहिये। उन्हें इस कार्य को नैतिक कर्तव्य समझ कर करना चाहिये।

अब मैं सूती कपड़ा उद्योग को लेता हूं। कई समितियों ने इस उद्योग की स्थिति का अध्ययन किया है। यह अध्ययन १९३१ से चालू है। प्रशुल्क बोर्ड ने भी इसका अध्ययन किया है। इन सब रिपोर्टों की छान बीन करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस उद्योग की वृद्धि तथा कमी के पांच या छः कारण हैं। पहला पुरानी मशीनरी, कई सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है। इस उद्योग में मशीनरी की बड़ी दुर्दशा है। कहीं कहीं तो १८५८ और १८९८ की पुरानी मशीनरी लगी हुई है। उसे देख कर बड़ी लज्जा आती है। हमारे मिल मालिकों को शेष संसार के औद्योगिक इतिहास से सबक सीखने की कोशिश करनी चाहिये। किसी भी उद्योग में २० वर्ष से पुरानी मशीनरी नहीं होनी चाहिये। आज के परिवर्तनशील जगत में तो १० वर्ष पुरानी मशीनरी भी प्रचलन से बाहर हो जाती है। इसलिये ६०, ७० वर्ष पुरानी मशीनों का सहन बड़ा कठिन हो जाता है। आधुनिकीकरण के प्रश्न को मैं थोड़ी देर बाद लूंगा।

†**एक माननीय सदस्य :** सरकार इसमें लोगों की सहायता क्यों नहीं करती ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम लोगों को राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के द्वारा ऋण इत्यादि देने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत का औद्योगिक वित्त निगम भी इस काम में सहायता दे रहा है। हम निर्यात व्यापार वृद्धि में प्रोत्साहन दे कर आधुनिकीकरण की प्रगति कर रहे हैं। अनेक मालिकों ने स्वयं अपने साधनों से भी नई मशीनें लगवा ली हैं। मैं इस वाद विवाद में उद्योगपतियों से फिर एक बार अपील करूंगा कि वे नई मशीनें लगाने के कार्य को बड़ी शीघ्रता से सम्पन्न करने का प्रयत्न करें ताकि हम अगले १० वर्ष में सब मशीनें बदल सकें।

अब मैं श्रम के प्रश्न को लेता हूं। श्रमिकों के कई एकक हैं। कुछ एकक ऐसे हैं जिनमें श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या है। वे बहुत शक्तिशाली एकक हैं। यहां तक कि कभी कभी उनकी शक्ति चिन्ता का विषय बन जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं कि हम श्रमिकों की समस्याओं को नहीं समझना चाहते या हमारी उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। हम भी यह चाहते हैं कि नवीकरण अथवा वैज्ञानीकरण के कारण कोई छटनी नहीं होनी चाहिये। पन्द्रहवें श्रमिक सम्मेलन में हमने नैनीताल में जो संहिता बनाई है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नवीकरण सर्वत्र 'विलायहीन' होना चाहिये। किन्तु इतनी प्रतिभूति देने के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उत्पादन की वृद्धि में मालिकों और मज़दूरों दोनों को सहयोग देना चाहिये। इस बात को हमारे सभी मित्र स्वीकार करते हैं। इसलिये श्रमिकों के नेताओं को सरकार और मालिकों के साथ मिल कर नवीकरण के लिये पूरा सहयोग देना चाहिये। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में उनको कुछ कड़वे घूंट भी चखने पड़ें। मगर उन्हें अस्थायी लोक प्रियता अथवा अप्रियता की चिन्ता न कर श्रमिकों को ठीक मार्ग बताना चाहिये और सरकार के उपायों को सहानुभूति से कार्यान्वित कराने में सहयोग देना चाहिये। एक खड्डी पर १५ या २० आदमियों का रखना कठिन है। इस चीज़ को सब आदमी भली भांति जानते हैं। इस प्रकार के अनावश्यक दबाव को कम करना बड़ा ज़रूरी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

इसके बाद प्रबन्ध की समस्या आती है। किसी भी उद्योग को दुनिया में मुकाबले का उद्योग बनाने के लिये तथा उसको पुनर्जीवित करने के लिये प्रबन्ध का सब से बड़ा महत्व होता है। इससे मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी देश से मुकाबला करने में कतराते हैं। हमारा कपड़ा उद्योग संसार के किसी भी देश के कपड़ा उद्योग से मुकाबला करने के लिये सर्वथा समर्थ है। श्री सोमानी ने कपड़े के उत्पादन-मूल्य के बारे में चर्चा की है। मैं उनके साथ इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि क्या कपड़े का उत्पादन-मूल्य १६५५ से कम या १६५६ से ज्यादा है। कुछ प्रकार के कपड़े के मूल्य कम हो सकते हैं किन्तु सब कपड़ों के मूल्य कम नहीं हैं। मैं अपने मित्रों को अपील करूंगा कि अभी हमें अपने उद्योग को ठीक बनाने की काफ़ी गुंजाइश है। कुछ एकक, जिनको कभी जंक, सीमान्त अथवा अनार्थिक कहा जाता है, इस प्रकार के एकक नहीं हैं कि इनकी दशा को सुधारा न जा सके। कल ही मैंने कुछ ऐसे मित्रों की हरकतों का जिक्र किया था जिन्होंने कि इस उद्योग का उचित ढंग से चलना दूभर बना रखा है। मैं ऐसे लोगों को राहु या केतु नहीं कह सकता। यह लोग एक बड़े भारी मिल के मालिक हैं जिसमें १ करोड़ ३० लाख सपिंडल चलती हैं। यह उद्योग जापान के कपड़ा उद्योग से ४० प्रतिशत बड़ा है और लंकाशायर के उद्योग से भी बड़ा है। कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिस पर रासायनिक, इंजीमियरी, चिकित्सा, पर्वतारोहण कपास तथा कृषि उत्पादक आदि अनेक व्यापारियों का काम निर्भर हैं। यह उद्योग भारतीय उद्योगों की मलिका है। इसलिये कपड़ा उद्योगपतियों को यह अपना प्रबन्ध सुधारने की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : श्री कानूनगो ने जिन आर्थिक एककों को मिलाने की सिफारिश की है उनका क्या होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सम्मिलन सम्भव नहीं है क्योंकि कोई उद्योग बम्बई में है और कोई भोपाल में। हम ऐसे अनार्थिक एककों को बढ़ा कर उनको आर्थिक एककों में बदल सकते हैं। हमने अभी यह सोचा है कि एक यूनिट में कम से कम १२,००० सपिंडल तथा ३०० खड्डियां हों तभी वह आर्थिक एकक बन सकता है। दूसरे देशों में न्यूनतम आर्थिक एकक का परिणाम २५००० सपिंडल तथा ६०० खड्डियां हैं। इस प्रकार का मिश्रण केवल आगरा, कानपुर, अहमदाबाद अथवा बम्बई में ही सम्भव है जहां पर कि ज्यादा मिलें हैं।

इसके बाद मैं उत्पादन कार्यक्रम को लेता हूं। इस समय कपड़े का उत्पादन ६ लाख गांठें हैं। इसमें से अधिकतर कपड़ा मोटा अथवा घटिया या मध्यम क्वालिटी का होता है। हमारे उद्योग अभी तक ऐसा कपड़ा नहीं तैयार कर पा रहे हैं जिसकी कि बाजार में सब से ज्यादा मांग है। क्यों ? ऐसा मालूम होता है इस दिशा में वैज्ञानिक रीति से काम नहीं हो रहा है। हमारे उत्पादक अभी तक बिकाऊ वृत्ति से नहीं काम कर रहे। थोड़ा उत्पादन शुल्क देने के लालच से वे मोटा कपड़ा तैयार करना पसन्द करते हैं हालांकि उसकी बिक्री बहुत कम है। पिछले वर्षों में औसतन ६ प्रतिशत मोटा कपड़ा बनता था किन्तु अब वह २२.५ प्रतिशत तक पहुंच गया है। उपभोक्ता लोग इस प्रकार के कपड़े को अपनाने के लिये कटिबद्ध नहीं हुये हैं। जोशी समिति की रिपोर्ट पर हमने जो संकल्प पास किया है उसमें हमने कपड़ा आयुक्त को यह कार्य सौंपा है कि वह कपड़े के उत्पादन के विनियमन की देख भाल करता रहे। किन्तु केवल विधान बना देने से कोई सुधार हो जाना कठिन है। इसके लिये उत्तम प्रबन्धकों तथा विक्रेताओं की आवश्यकता है। हमारे उत्पादकों को उपभोक्ताओं की प्रवृत्तियों का ध्यान रखना चाहिये। अमेरिका के बाजार में न्यूयार्क और मैक्सिको में मैंने विशेष रूप से यह देखा कि वे लोग अपना माल कैसे बेचते हैं। वे लोग यहां

†मूल अंग्रेजी में

तक ख्याल रखते हैं कि कौन से रंग की कारें ज्यादा बिकेंगी। सर्वत्र उपभोक्ताओं की रुचियों का वैज्ञानिक ढंगों से अध्ययन किया जा रहा है। हमें भी अपने यहां इस पद्धति से काम करना चाहिये। मैं चाहता हूं सरकार के हस्तक्षेप के बिना ही इस उद्योग का विनियमन हो सके। सरकार तभी हस्तक्षेप करना चाहती है जबकि बहुत आवश्यक हो।

इसके बाद मैं कपड़े की क्वालिटी और कीमतों को कम करने के प्रश्न को लेता हूं। मेरे कई मित्रों ने इस प्रश्न पर बड़ा बल दिया है। इस सम्बन्ध में मैं स्वचालित खड्डियों का उल्लेख विशेषकर करना चाहता हूं। मेरे मित्र श्री डांगे इन खड्डियों का जिक्र करते समय आर्थिक दर्शन की गुत्थियों में उलझ गये और वह यह नहीं समझ पाये कि ये पूंजीवाद, समाजवाद या साम्यवाद किस वाद की द्योतक हैं। मैं समझता हूं कि इन खड्डियों का राजनीति या किसी वाद से कोई ताल्लुक नहीं। आप अमेरिका, चीन या जापान कहीं भी जायें सभी देशों में इनका प्रयोग बढ़ रहा है। जापान में ६८ प्रतिशत स्वचालित खड्डियां हैं जब कि हमारे यहां केवल ६ प्रतिशत। चीन में भी सभी नई खड्डियां स्वचालित खड्डियां ही हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि यह राजनीति या ट्रेड यूनियनिज्म का विषय नहीं। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे देश का दुनिया की मंडियों में ऊंचा नाम हो और हम अपनी पुरानी परम्पराओं के अनुसार लोगों पर फिर से अपने माल की श्रेष्ठता की धाक जमा सकें तथा भारतवर्ष फिर से १००० वर्ष पूर्व के यश को पुनः प्राप्त कर सके तब हमें कपड़ा उद्योग में अधिकाधिक ऐसी खड्डियां लगाने का प्रयास करना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमें परस्पर या सरकार के साथ कोई मतभेद नहीं पैदा होने देना चाहिये।

हम १९५९, १९६० और १९६१ में प्रति वर्ष २५०० स्वचालित खड्डियां लगाना चाहते हैं। इस पर विचार करने के लिये तीनों श्रमिक संघों के उच्च नेताओं ने बातचीत करना भी स्वीकार कर लिया है। ये खड्डियां उन ३००० स्वचालित खड्डियों के इलावा होंगी जोकि निर्यात के लिये उत्पादन बढ़ाने के लिये लगाई जाने वाली हैं। ये खड्डियां इस प्रकार से लगाई जायेंगी कि इनके कारण किसी उद्योग में किसी प्रकार की छंटनी न हो। मुझे आशा है कहीं पर भी नई खड्डियों के कारण छंटनी नहीं होगी।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : क्या आप यह ३००० खड्डियां सरकारी उद्योगों में अथवा गैर-सरकारी उद्योगों में लगायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कपड़ा उद्योग में कोई भी कारखाना सरकारी क्षेत्र में नहीं है। इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

मैं तीनों श्रमिक नेताओं का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने स्वचालित खड्डियाँ लगाने के लिये योजना पर विचार विमर्श करने के लिये सहमति प्रकट की है। हमें कुल ७५०० खड्डियां लगानी हैं हालांकि हम में से कुछ लोग इतने उत्सुक थे कि हम प्रति वर्ष १०,००० स्वचालित खड्डियां लगाना चाहते थे। मगर अभी हम इस प्रयोग का प्रारम्भ ही कर रहे हैं। अनुभव प्राप्त होने पर हम आगे बढ़ने का कार्यक्रम बनायेंगे।

इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है कि स्वचालित खड्डियों का प्रति खड्डी पीछे अधिक उत्पादन है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार की खड्डियों से कपड़े का लागत व्यय भी कम हो जाता है। किन्तु मैं इन दोनों दृष्टियों से नहीं अपितु क्वालिटी की दृष्टि से यह खड्डियां लगवाने पर बल देना चाहता हूं। यदि हम श्रेष्ठ कपड़ा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

बनाना चाहते हैं और देश की भीतरी तथा विदेशी मार्किटों में दूसरे देशों का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें शीघ्रातिशीघ्र ये खड्डियां चालू करनी चाहियें। इससे श्रमिकों को बढ़े हुए उत्पादन का लाभ भी मिल सकेगा। हम यह खड्डियाँ श्रम व्यवहार संहिता में स्वीकार किये गये नियमों के अनुसार ही लगवाना चाहते हैं इससे हमें श्रमिकों के बेकार हो जाने का भय नहीं करना चाहिये। स्पिनिंग, कार्डिंग और ब्लो रुमों में अन्य प्रकार के सुधार करने के लिये भी हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं। स्पिनिंग तथा अन्य प्रारम्भिक कार्यों के लिये हमारे पास पहले से ही बहुत उत्तम तथा आधुनिक मशीनरी है।

अब मैं लागत व्यय में कमी करने के प्रश्न को लेता हूँ। यह प्रश्न उत्पादन वृद्धि के साथ अभिन्न रूप से सम्बद्ध है। मैं समझता हूं जब उत्पादन बढ़ेगा तब अपने आप व्यय कम हो जायेगा। इसलिये यदि हम उत्तम प्रकार की मशीनों, अच्छे प्रबन्ध, उचित नियंत्रित उत्पादन कार्यक्रम इत्यादि द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और इस कार्य में पूंजीपतियों, श्रमिकों तथा सरकार तीनों का सहयोग रहेगा तब हमारे सम्मुख कोई भी समस्या नहीं बचेगी। सरकार इस दिशा में मिल मालिकों द्वारा बनाई जाने वाली किसी भी योजना में पूर्ण सहयोग देने को तैयार है और उसके लिये प्रत्येक प्रकार की वित्तीय, वैधिक, नैतिक सामाजिक सहायता देने को तैयार है।

अंत में मैं रसायनिक तथा इंजीनियरिंग उद्योगों के बारे में भी चन्द शब्द कहना चाहूंगा। कपड़ा उद्योग के पश्चात्, अगर कोई और उद्योग विदेशी मुद्रा की खपत करता है तो वह इंजीनियरिंग तथा रसायनिक उद्योग हैं। इसमें इस्पात तथा अन्य अनेक प्रकार की अलोह धातुओं व रसायनिकों की बड़ी खपत होती है जो कि प्रायः विदेशों से निर्यात किये जाते हैं। मेरी यह इच्छा है कि इन उद्योगों को हम इतना समर्थवान बना दें कि ये उद्योग साइकल, मशीनें, पंखे, मीटर, औषधियां इत्यादि वस्तुओं का निर्यात करने लगें।

मैं इस सभा के सदस्यों का कृतज्ञ हूं और उन्हें आश्वासन देता हूं कि उन्होंने जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं सरकार उन पर उचित विचार करेगी। हम प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली देरी को यथासम्भव रोकने का प्रयत्न करेंगे किन्तु बड़े—बड़े कार्यों में प्रायः थोड़ा बहुत विलम्ब हो ही जाया करता है। हम जहां तक हो सकेगा निर्यात वृद्धि की समस्या को राष्ट्रीय आपतकालीन समस्या की भांति हल करने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री च० द० पांडे** (नैनीताल): बड़ी विचित्र सी बात है कि हमारी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में योजना के अनुसार विकास नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में, मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

असल में हमारे देश में कई विचारधाराओं की टक्करें चल रही हैं, एक किसी विचार-धारा के अनुसार नहीं चला जा रहा है। विरोधी दल के सदस्य, श्री डांगे और श्री बनर्जी सूती कपड़ा उद्योग में स्वयंचालित करघे लगाने और वैज्ञानिकन करने की बात को पूंजी—पतियों की मुनाफे बढ़ाने की चालें समझते हैं। उनका कहना है कि हम १९५१ में ११,००० लाख गज़ सूती कपड़े का निर्यात करते थे, जो अब सिर्फ ५,००० लाख गज ही रह गया है। इसका असल कारण यह है कि विश्वयुद्ध के बाद के काल में लंकाशायर के सूती कपड़े के कारखाने सूती कपड़े के उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे। तब जर्मनी, चीन और

†मूल अंग्रेजी में

जापान की प्रतियोगिता भी नहीं थी। इसीलिये १९५८, अब १९५१ से भिन्न है। अब स्थिति काफी गम्भीर है। हमें सोचना यह चाहिये कि निर्यात में आई इस गिरावट को दूर कैसे किया जाये। इतना ही नहीं, हमें अपनी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति करनी है।

वास्तव में हमारी योजना ही त्रुटिपूर्ण है। वह तो कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम भर है। तभी तो हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाते। कपड़े के उपभोग का हमारा लक्ष्य प्रति व्यक्ति २० गज था, लेकिन लगता है कि हम प्रति व्यक्ति १६ गज से आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

मेरा ख्याल है कि हमारी योजना एकांगी है। हमने अपना सारा ध्यान एक-दो मदों पर ही लगा दिया है। हमने इस्पात के तीन बड़े कारखानों और कुछ नदी घाटी परियोजनाओं को ही सब कुछ मान लिया है। उपभोग वस्तुओं के उद्योगों की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। इसीलिये हम पीछे हटते जा रहे हैं, हमारा कपड़े का उत्पादन ५५,००० लाख से घटकर ४८,००० लाख गज ही रह गया है। आन्तरिक उत्पादन में भी कमी आ गई है।

यह कमी केवल सूती कपड़ा उद्योग के उत्पादन में नहीं आई है। सिमेंट की उत्पादन क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। हमारा लक्ष्य १४० लाख टन सिमेंट का था, लेकिन हम अभी तक ७० लाख टन का ही उत्पादन कर पाये हैं। योजना के अनुसार हमारी प्रगति नहीं हो पा रही है। चीज यह है कि हमारे विभिन्न लक्ष्यों में कोई सह-योजना नहीं है। कभी हम इतना अधिक सिमेंट या कपड़ा भी पैदा कर सकते हैं कि उससे बाजार पट जाये, लेकिन दूसरी ओर दूसरी चीजों का अभाव ही बना रहे।

इसका हल दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो यह कि हमें कुछ तात्कालीन उपाय करने चाहियें। जहां तक दीर्घकालीन योजना या ऐसे उपायों का सम्बन्ध है, श्री शाह का सुझाव ही सर्वोत्तम है। श्रमिकों से सहयोग की अपील के साथ ही, देशीय उद्योग से निर्यात सम्बन्धी उत्पादन के लिये अपने मुनाफे कम से कम कर देने चाहियें।

श्री रंगा ने श्री डांगे से इस बात में सहमति प्रकट की है कि सभी मिलें और स्वयंचालित करघे सरकारी क्षेत्र में ही रहने चाहिये। लेकिन सभी जानते हैं कि सरकार अभी इसका दायित्व अपने ऊपर लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन विरोधी दल के सदस्यों को इस बात पर तो सरकार से सहमत हो ही जाना चाहिये कि राज्य व्यापार संगठन स्वयंचालित करघों का सारा उत्पादन अपने हाथ में ले ले और वही अपने नियंत्रण में सारा निर्यात करे और साथ ही उत्पादन-लागत के सम्बन्ध में गहरी छानबीन करता रहे। हमें उद्योग के मुनाफे को भी ५ या ३ प्रतिशत तक सीमित कर सकते हैं। इस प्रकार जब श्रमिकों की छंटनी किये बिना ही, स्वयंचालित करघे लगाये जा सकते हैं, और उद्योग का वैज्ञानिकन किया जा सकता है, तो उस पर विरोधी दल को क्या आपत्ति है?

श्री मनुभाई शाह ने जो दीर्घकालीन कार्यक्रम रखा है, उसे सफल बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें दो-तीन वर्ष लग जायेंगे। पहले हमने लगभग ५०,००० टन चीनी का निर्यात भी किया था। चीनी का निर्यात हमने विदेशी मुद्रा पाने के लिये किया था। लेकिन हमने चीनी के निर्यात से दो करोड़ रूपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा पाने के लिये उस पर डेढ़ करोड़ रुपये व्यय किये थे। यह कोई अधिक लाभदायक सौदा नहीं है।

[श्री च० द० पांडे]

हम ठीक समय पर चाय, जूट और सूती कपड़े के निर्यात से २० या ३० या ४० करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा पा सकते हैं और उस पर व्यय भी इससे कहीं कम होगा। इसलिये मेरा सुझाव तो यह है कि सरकार को निर्यात पर से सभी प्रतिबन्ध हटा लेने चाहियें। आज तो प्रत्येक वस्तु के निर्यात के लिये अनुमति लेनी पड़ती है। जो भी जिस वस्तु का निर्यात कर सकता है करे। उसके लिये अनुमति आवश्यक नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक निर्माता का निर्यातक बनने के प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

और जिन वस्तुओं पर उद्योगपतियों को मुनाफा नहीं लेने दिया जाता, उस वस्तु से होने वाली आय पर श्रमिकों को बोनस की मांग नहीं करनी चाहिये। राज्यों को भी राष्ट्रीय हित की दृष्टि से निर्यात की वस्तुओं पर, जैसे चाय, इत्यादि पर, सीमा-शुल्क नहीं लगाना चाहिये। तभी हम विदेशी बाज़ारों में प्रतियोगिता कर सकते हैं।

साथ ही चाय समवायों को भी अपने मुनाफे घटाने चाहियें।

निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने के लिये, राज्यों, उद्योगपतियों और श्रमिकों को ही नहीं, उपभोक्ताओं को भी कुछ त्याग करने पड़ेंगे। हमें सारा जोर चाय, जूट, और सूती कपड़े के उद्योग पर ही लगाना चाहियें। आशा है कि श्री मनुभाई शाह की अपील पर सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : यह बड़ी चिन्ता की बात है कि इस वर्ष हमारे विदेशी व्यापार में १०० करोड़ रुपये की कमी हो गई है। १९५१ में हमारा निर्यात व्यापार ७६१.६ करोड़ पये का था, जो १९५७ में ६००.१ करोड़ रुपये का ही रह गया है। १९५७ में हमने ९०० करोड़ रुपये का आयात किया है। यदि हमारे निर्यात और आयात में इतना अधिक अन्तर बना रहा, निर्यात में वृद्धि न हुई, तो हमारा देश बिलकुल निर्धन हो जायेगा। इंग्लैण्ड में जब ऐसी परिस्थिति आई थी तो श्रमिकों ने एक घंटा अतिरिक्त देना शुरू कर दिया था और मिल मालिकों ने अपने मुनाफे घटा दिये थे। हमें भी वही करना पड़ेगा। तभी हम विदेशी बाज़ारों में प्रतियोगिता कर सकेंगे।

सूती कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में दो विरोधी दृष्टिकोण रखे जा चुके हैं। मैं भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। १९३९ में सूती कपड़ा उद्योग के श्रमिकों की २६ दिन के लिये औसत मासिक तनखा साढ़े पैंतीस रुपये थी, जो १९५८ में ११८ रुपये १० आने हो गई है। १९४० में इस उद्योग में ४,९०,८१५ श्रमिक काम करते थे और कुल उत्पादन १२,७६० लाख पौण्ड सूत और ४०,९२० लाख गज सूती कपड़ा था। जबकि १९५६ में श्रमिकों की संख्या ८,०६,७०२ हो गई, लेकिन उत्पादन दोगुना नहीं हुआ, १६,७१० लाख पौण्ड सूत और ५३,०६० लाख गज कपड़ा ही रह गया। इससे स्पष्ट है कि श्रमिकों की आय और उनकी संख्या के अनुपात में उद्योग का उत्पादन नहीं बढ़ा है।

हम चाहते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़े और उत्पादन की लागत कम हो। इसके लिये ज़रुरी है कि श्रमिक पूरी मेहनत से काम करें। लेकिन हमारे देश के कार्मिक संघ तो श्रमिकों को कम से कम काम करना ही सिखाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी तरह सूती कपड़ा उद्योग के मिल मालिक भी देश के हितों की परवाह नहीं करते। उन्होंने १९५६ में ५३.५९ करोड़ रुपयों के मूल्य के विदेशी कपास का आयात किया था और ५७.३२ करोड़ रुपये के मूल्य के कपड़े का निर्यात। यदि विदेशी कपास का अधिक आयात करने पर भी मिल मालिक कपड़े का निर्यात नहीं बढ़ा सकते, तो हमें उन पर नियंत्रण करना चाहिये और निर्यात बढ़ाने की शर्त पर ही विदेशी कपास का आयात बढ़ाने देना चाहिये।

हम अधिकतर मोटे और मध्यम दर्जे के कपड़े का ही निर्यात करते हैं। तब फिर विदेशी कपास का आयात क्यों करने दिया जाये?

मिल मालिक मोटे कपड़े का निर्यात इसलिये अधिक करते हैं, कि उन्हें उसके लिये देशी कपास अधिक सस्ता मिल जाता है। इसलिये मिल मालिक देश के कृषकों और ग्राम जनता को मोटा और मध्यम दर्जे का कपड़ा नहीं मिलने देते, बल्कि उसका निर्यात कर देते हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

कल्याण के कपास उत्पादक क्षेत्र पर मिल मालिकों ने एकाधिकार कायम कर लिया है। सरकार वहां से निर्यात करने की अनुमति नहीं देती। नतीजा यह होता है कि हजारों गाठें कपास गोदामों में ही पड़ी रहती हैं। इससे देश की जनता को ही नुकसान होता है। सरकार को अपनी यह नीति बनानी चाहिये कि यदि शुरू में मिल मालिक कपास की गाठें न खरीदें, तो उनके निर्यात की अनुमति दे दी जाये। कपास उत्पादकों को मिल मालिकों की सुविधा के लिये कष्ट नहीं देना चाहिये। माननीय मंत्री ने कहा है कि सूती कपड़ा मिल फेडरेशन की सिफारिश पर ही सरकार ने विदेशी कपास के आयात के लिये सुविधायें जुटाई हैं। सरकार ने यह सुविधायें निर्यात संवर्धन के लिये ही जुटाई हैं। लेकिन मिल मालिक इसका फायदा उठा कर अपने देश के बाजार में ही महीन कपड़े को अधिक मूल्य पर बेचते हैं और बेशुमार मुनाफे कमाते हैं।

इसलिये सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिये। सरकार कहती है कि कृषीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया जा सकता है। यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निर्मित वस्तुओं के उत्पादन की हमारी क्षमता अभी सीमित ही है, और फिर इस क्षेत्र में हमें अन्य देशों से प्रतियोगिता भी करनी पड़ेगी। इसीलिये हमें अपने सारे प्रयास कृषीय उत्पादन बढ़ाने में ही लगाने चाहियें। लेकिन यह भाषणों से ही नहीं होगा। सरकार ने विश्व बैंक के विशेषज्ञों की सलाह के बाद भी कुछ नहीं सीखा है विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट बताया है हमारे यहां खाद्यान्नों का उत्पादन उनके मूल्य के उतार-चढ़ाव के साथ ही बढ़ता घटता रहता है। इसीलिये उन्होंने सरकार को सलाह दी थी कृषकों को निम्नतम निर्धारित मूल्य मिलने की गारंटी दी जानी चाहिये। सरकार जब तक यह नहीं करेगी, तब तक कृषीय उत्पादन में वृद्धि होना सम्भव नहीं होगा।

†**श्री श्रोझा** (झालावाड़) : देश के निर्यात-व्यापार में कमी होने से सभी को चिन्ता है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह आलोचना की है कि सरकार इस संबंध में उचित कार्यवाही नहीं कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ओझा]

माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि पिछले नौ महीनों का अनुभव बताता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिये, लेकिन फिर भी आत्म तुष्टि से भी नहीं बैठे रहना चाहिये ।

कम्युनिस्ट दल के नेता, श्री डांगे ने सरकार की प्रताड़ना इसलिये की है कि उसने देश की अर्थ-व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था वाले देशों के साथ जोड़ रखा है । इसका समुचित उत्तर दिया जा चुका है । हमारा देश कम-विकसित देश है, इसलिये हम सभी देशों से सहायता चाहते हैं । हम किसी एक गुट के देशों से गठजोड़ नहीं कर सकते ।

द्वितीय योजना में इस बात की ओर इशारा किया गया था कि विदेशी मुद्रा की आय और उसकी आवश्यकताओं के बारे में पांच साल के लिये पहले से ठीक ठीक अनुमान करना कठिन है । हम जानते थे कि योजना-काल में परिस्थिति कभी बिगड़ भी सकती है । इसलिये हमें इस बात से पस्तहिम्मत नहीं हो जाना चाहिये कि एक काल विशेष में हमारी निर्यात-आय में गिरावट आ गई थी । इसके लिये सरकार की आलोचना करना, और निर्यात-आय की वृद्धि के लिये सरकार को श्रेय न देना,—यह दृष्टिकोण गलत है ।

निर्यात-व्यापार की बात करते समय, हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि राज्य और निजी उपक्रमों दोनों ही को इसमें अपना अपना कुछ पार्ट अदा करना होता है । निर्यात की सभी वस्तुयें निजी क्षेत्र में तैयार होती हैं, और सरकार तो इतना ही कर सकती है कि निर्यात के लिये अधिक सुविधायें जुटाये । और, माननीय मंत्री ने अपने भाषण में बताया है कि सरकार ने पूरी-पूरी सुविधायें जुटाई हैं । सरकार ने निर्यात-संवर्धन के लिये ७–८ संस्थाओं की स्थापना भी की है ।

सरकार ने निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना की है । हम चाहते हैं कि सरकार हमें उसकी कार्यवाहियों का पूरा ब्यौरा भी बतायें ।

सभा में यह भी कहा गया है कि श्रमिक पूरी मेहनत के साथ काम नहीं करते, वे उत्पादन की लागत कम करने की आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं देते । लेकिन साथ ही यह भी सही है कि हमारे उद्योगों की मशीनें बड़ी पुरानी पड़ चुकी हैं । हमें उद्योगों के वैज्ञानिकन का काम बिना श्रमिकों की छंटनी के पूरा करना चाहिये । वैज्ञानिकन से होने वाला मुनाफा मिल मालिकों और श्रमिकों को बराबर का मिलना चाहिये । हमें प्रसन्नता है कि कार्मिक संघों, मिल मालिकों और सरकार के बीच आधुनिक मशीनें संस्थापित करने के बारे में समझौता हो चुका है ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

मुझे मूंगफली और उसके उत्पादों के निर्यात पर कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन इस संबंध में सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि ग़रीब जनता को केवल मूंगफली के तेल पर ही निर्भर रहना पड़ता है, इसलिये इसके निर्यात के कारण देश म इसका मूल्य नहीं बढ़ने देना चाहिये ।

हमें देश क विकास के लिये भारी मशीनों का आयात करना ही पड़ेगा, इसलिये निर्यात की आवश्यकता को सदैव ही ध्यान में रखना जरूरी है । इसमें हमें चीन और जापान इत्यादि के साथ प्रतियोगिता भी करनी पड़ेगी । चीन तो निर्यात बाजार में प्रवेश

पाने के लिये अपनी वस्तुओं को १० प्रतिशत कम मूल्य पर देने को तैयार है । हमें भी ऐसी ही नीति अपनानी पड़ेगी । लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसी नीति के परिणामस्वरूप देश में मुद्रा स्फीति न हो सके । साथ ही हमें इस नीति क परिणाम-स्वरूप उपिभोक्ताओं को भी रूष्ट नहीं करना चाहिये, वरना हमारी कई मिलें बन्द हो जायेंगी और बे ोज़गारी बढ़ जायेगी । इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही, हमें निर्यात संवर्धन करना चाहिये ।

माननीय उद्योग मंत्री ने देश के उद्योगपतियों से अपील की ँ कि वे राष्ट्रीय हित को, उद्योग के हित को ही सर्वोपरि समझें, मुनाफों को नहीं । श्रमिकों को भी इसी भावना से काम करना पड़ेगा । तभी हमारा निर्यात संवर्धन सफल होगा और ेश विकास कर सकेगा ।

हमें माननीय मंत्री को बधाई ेनी चाहिये कि उन्होंने सभा के सामने पूरी परिस्थिति रख दी है । मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमें निर्यात की इस परिस्थति को देखकर निराश होने या खीझने की कोई ुंजाइश नहीं है । हम अपने निर्यात व्यापार में सुधार कर सकते हैं ।

†**कुमारी मो० वेद कुमारी** (एलरु) : यह प्रश्न पूरी अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है । निर्यात और आयात के बीच भारी अन्तर रहने से, निर्यात बहुत कम रहने से अर्थ-व्यवस्था के विकास में बाधा पड़ती है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तमाम वादों की चर्चा छेड़ दी है । उनका कहना है कि हमें समाजवादी गुट के देशों को निर्यात करना चाहिये । कम्यूनिस्ट दल के नेता का यह तर्क मेरी समझ में नही आया कि हम १९५१ में जितना निर्यात करते थे, उतना अब क्यों नही करते । वह विश्व-बाज़ार की बदलती हुई परिस्थिति को क्यों नही देखते ?

हम तो सभी देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ।

हमने हाल में रूस के साथ एक पंचवर्षीय करार किया है । उस करार में सूती कपड़े का उल्लेख नहीं है । हमें रूस को सूती कपड़े का निर्यात करना चाहिये । रूस मिस्र तो सूती कपड़ा मंगाता ही है । अब विभिन्न वादों की चर्चा छेड़ना व्यर्थ है, क्योंकि हमारी जनता ने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को ही चुन लिया है । हमारी मुख्य समस्या तो यह है कि हमें अपने निर्यात-व्यापार को बढ़ाना है ।

हम किसी भी देश को किसी वस्तु विशेष का निर्यात तभी कर सकते हैं जब वहां उसकी मांग हो । इसमें विचारधाराओं या वादों का कोई प्रश्न ही नहीं हैं ।

हमें अपने देश के आन्तरिक व्यापार को भी देखना पड़ेगा । देश में उत्पादन की लागत बढ़ती जा रही है । हमा ी अपनी कई तरह की समस्यायें हैं । सरकार तो नि ति व्यापार के लिये सभी सुविधायें जुटा रही है ।

निर्यात की बात करते समय , हमें उत्पादन की लागत का प्रश्न अनदेखा नहीं करना चाहिये । आसाम में कुछ चाय बागान बन्द होते जा रहे हैं । सरकार को उन्हें चालू कराने का प्रयत्न करना चाहिये । हमें भी इस सम्बन्ध में रचनात्मक सुझाव ही रखने चाहियें ।

†मूल अंग्रेजी में

[कुमारी मो० वेद कुमारी]

यूरोपीय सामान्य बाजार स्थापित करने की बातें सुनने में आ रही हैं । हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । उसका हमारे निर्यात व्यापार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारा ५० प्रतिशत निर्यात यूरोपीय देशों को ही होता है । निर्यात संवर्धन समिति ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है ।

उस समिति ने वस्तुओं के मूल्य-स्तर के सम्बन्ध में भी गम्भीरता से विचार करने की सिफारिश की है । केवल उत्पादन शुल्क या रेल भाड़े में कमी कर देने से समस्या का हल नहीं होगा ।

देश के विकास के लिये हमें कुछ कच्चे माल का आयात करना ही पड़ेगा । इसलिये उत्पादन-लागत की समस्या पर विचार करना भी आवश्यक है ।

हमारे यहां जूट लगभग २५ रुपये मन बिक रहा है । तब इतने कम मूल्य पर, कृषक को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा कैसे मिल सकती है ? हमें जूट को परिष्कृत भी करना पड़ता है । इसलिये, निर्यात के सम्बन्ध में मूल समस्या उत्पादन लागत की ही है ।

निर्यात संवर्धन समिति ने सिफारिश की है कि आन्ध्र प्रदेश में सिगरेट बनाने का कारखाना संस्थापित किया जाये । सिगरेटों का निर्यात हो सकता है । सरकार को इस सिफारिश को कार्यान्वित करना चाहिये ।

हमें वस्तुओं के निर्यात को संवर्धित करने के लिये, सहकारी समितियों और विस्थापित व्यक्तियों को यह सुविधा देनी चाहिये कि वे सरकार द्वारा निर्धारित अपने निर्यात-अभ्यंशों को कमीशन के आधार पर बड़े बड़े नौवाहकों को दे सकें ।

साथ ही उत्पादकता की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा । श्रमिकों को अपनी उत्पादकता भी बढ़ानी पड़ेगी । तभी निर्यात संवर्धित हो सकेगा ।

मैं निजी क्षेत्र की हिमायत नहीं करती । निर्यात के प्रश्न पर विचार करते समय हमें सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र का विभेद नहीं करना चाहिये । इसीलिये मैं कहती हूँ कि बट्टे की दर को यदि बैंक की दर से कम रखा जाये, तो उससे निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा रक्खे गये प्रस्ताव पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ प्रस्तुत कर रहा हूं । इस प्रस्ताव में मैंने कहा है कि सरकार हमारे निर्यात व्यापार का समुचित ढंग से संचालन करने में पूर्णतः असफल रही है ; इस विषय की पूरी तरह से छानबीन करने के लिये दोनों सभाओं में से चुने गये सदस्यों की एक समिति बनाई जाये, जिसकी टेक्निकल विशेषज्ञों की भी सहायता प्राप्त हो, और यह समिति हमारे निर्यात व्यापार की स्थिति को ठीक करने के लिये उपाय सुझाये ।

कल से इस विषय पर जो वाद विवाद चल रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि निर्यात का जो काम है उसमें न सिर्फ सरकार की ही लापरवाही रही एक तरह से बल्कि उन हितों का भी बहुत स्वार्थ रहा जो हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि उनको लाभ होता रहे । मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस समस्या की तरफ

सदन का जितना ध्यान जाना चाहिये था, उतना ध्यान अभी नही जा रहा है । जो टेक्सटाइल के मालिक हैं, जो एक तरह से वस्त्र उद्योग के संचालक हैं, उनकी तरफ से वस्त्र के उद्योग पर कितना खर्च होता है, इस की तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं जा पाया है, न देश के लोग ही इस बात को जानते ह कि टेक्सटाइल उद्योग की तरफ से जितना मुनाफा दिखाया जा रहा है, उनको उतना ही मुनाफा होता है या उससे कहीं ज्यादा मुनाफा उनकी तरफ से कर लिया जाता है । एक माननीय मित्र ने सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि टेक्सटाइल उद्योग के जो संचालक हैं वह अपने नातेदारों और रिश्तेदारों को उन में रख कर उनको भारी भारी तन्ख्वाहें दिया करते हैं । यह सही है, लेकिन इससे भी आगे बढ़ कर एक बात है और वह यह है कि अभी तक सरकार को पूरी तस्वीर नहीं मालूम है कि किस तरह से इन मुनाफों में ब्लैकमेलिंग होती है । कुछ इस तरह के मुनाफे कर लिये जाते हैं जो कागज पर पूरी तरह से नहीं आते हैं, और उनका बहुत बड़ा हाथ एक्सपोर्ट ट्रेड के कम होने में रहता है । हमारा मुनाफा जिस तरह से बढ़ता है उस के हिसाब से जितना निर्यात बढ़ना चाहिये वह उतना नहीं बढ़ पाया है । इसलिये इधर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि किस प्रकार से वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग के संचालक कितना मुनाफ़ा कर रहे हैं, इसकी पूरी जांच पड़ताल हो । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वस्त्र उद्योग जांच समिति ने इस बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया है। इसको वेज बोर्ड पर छोड़ दिया गया कि वह इस को देख लेगा लेकिन मैं समझता हूं कि वेज बोर्ड भी इस बात की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाया है जितना कि जाना चाहिये था । इस बारे में पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिये कि वस्त्र उद्योग में किस तरह से मुनाफा किया जा रहा है, और क्या वह मुनाफा जायज है ? अगर वह जायज नहीं है तो उसको कम करने की कोशिश की जानी चाहिये।

हम आम तौर से इस उद्योग के निर्यात से ६५ करोड़ रुपया पैदा कर रहे हैं जो कि हमारी कुल निर्यात का करीब १२ परसेन्ट होता है । लेकिन कितने ही कदम उठाये जायें, यह विचारणीय विषय है कि क्या यह सम्भव है कि इस निर्यात को इस रेट पर हमेशा कायम रक्खा जा सके क्योंकि वस्त्र जो है वह हमारे कज्यूमर के उपयोग में आता है, उपभोक्ता सामान में आता है, और हर मुल्क जो पिछड़ा हुआ रहता है, चाहता है कि वह अपने यहां इस उद्योग को कायम करे । इसलिये निकट भविष्य में ही हमें इसके अतिरिक्त और भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । हो सकता है कि अभी बहुत ज्यादा कमी न हो, लेकिन दस बीस साल में इस तरह की बात हो सकती है कि कही इस तरह से एक्सपोर्ट हो ही न सके । तब क्या होगा ? इसलिये सबसे मुख्य समस्या यह है कि वस्त्र उद्योग की तरफ ध्यान दिया जाय, बल्कि पूरा ध्यान जाय कि हम अपने निर्यात को कैसे कायम रख सकते हैं । जो पुरानी चीजें चली आ रहीं हैं, जैसे वस्त्र है, चाय है, जूट है, उनकी तरफ पूरा ध्यान रक्खा जाय । लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं । जिनका निर्यात करके हम देश के लिये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, विदेशी विनिमय पैदा कर सकते हैं । लेकिन इधर भी सरकार का ध्यान नही जा रहा है । मैं यह नहीं कहता कि बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है, ध्यान जा रहा है और जाना भी चाहिये । लेकिन यह देखना चाहिये कि जितना निर्यात हमारा होता रहा है उतना कायम ही न रहे बल्कि उससे अधिक हो तो अच्छा है । लेकिन मेरा कहना यह है कि निकट भविष्य में जब यह निर्यात इस गति से कायम नहीं रह सकेगा तब क्या होगा । इस बारे में हमें सोचना चाहिये ।

[श्री ब्रजराज सिंह]

नई चीजों का निर्यात हुआ है लेकिन वह निर्यात भी जाना चाहिये पब्लिक सेक्टर में। वह न होकर उस प्राइ`ट सेक्टर को ` दिया जाता है। आगरा से जूते का बहुत निर्यात हुआ है। जनता यह सोच रही है कि जूते का निर्यात प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में दे दिया गया और प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा निर्यात होने की वजह से बहुत सा माल इस तरह का चला गया जो खराब था। उसके खराब होने की वजह से न सिर्फ हमारी बदनामी हुई बल्कि हमारी निर्यात की प्रतिष्ठा भी गिरी। कुछ और भी नये काम हैं जो यह `श आगे बढ़ा सकता है। एक चूड़ी का उद्योग है। इस देश के बाहर भी कुछ इस तरह के लोग हैं जिनके लिये हम इसका निर्यात कर सकते हैं। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं मानता हूं कि इससे शायद करोड़, दो करोड़ रुपये की ही विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा, लेकिन इससे आप अपने निर्यात में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। इन सब बातों को हमें ठीक से देखना पड़ेगा। हम सिर्फ एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल को ही न कायम कर दें और उस से काम चलाने की कोशिश करें, बल्कि इन सारी चीजों को ठीक से करके हम अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हैं।

टेक्स्टाइल इंडस्ट्री की तरफ अगर मैं ध्यान दिलाऊं तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस उद्योग में कितना घोटाला होता है। जब भी इस तरह की आवाज़ उद्योग की तरफ से आती है कि इसका कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका उत्पादन व्यय बढ़ रहा है, या किसी तरह से इतनी कीमत हो रही है कि उद्योग उसे बरदाश्त नहीं कर सकता तो सरकार की तरफ से रिबेट दिया जाता है, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाती है। अगर यह करना इतना आवश्यक हो कि उसके बिना काम न चल सकता हो तो वह निर्यात को कायम रखने के लिये जरूर किया जाय लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या इस की वास्तव में आवश्यकता भी है। जैसा आज सुबह इस सदन में कहा गया है हमें देखना चाहिये कि एक्साइज ड्यूटी कम करने से क्या उपभोक्ता तक उसका लाभ पहुंचता है। यह भी देखने की बात है। मैं समझता हूं कि चूंकि इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तभी यह स्थिति पैदा कर दी जाती है कि एक न एक मिल बन्द रहती है। ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है कि मिल बन्द हो, मज़दूर बेकार हों, उत्पादन घटे, निर्यात में कमी आये। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा करने वालों को मजबूर किया जाना चाहिये कि उनकी मिल बन्द न रहे। मैं चाहूंगा कि उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह ने जो अपने विचार व्यक्त किये, उनको वाकई में अमल में लाया जाय। जब कभी हमारे मिनिस्टर भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि वे अपोजीशन बेंचेज से बोल रहे हैं, लेकिन जब काम करने का सवाल आता है तो जो रेड टेप चला आ रहा है वह उसमें फंस जाते हैं, और साल दो साल तक उस की कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। मैं चाहूंगा कि जिस गति से और जिस प्रकार से यहां विचार व्यक्त किये जाते हैं मिनिस्टरों की तरफ से, उस पर तुरन्त ध्यान दिया जाय जिस-से यह अहम समस्या हल हो सके। जहां तक टेक्स्टाइल के एक्सपोर्ट का सवाल है इस समय बहुत सी टेक्स्टाइल मिल्स हैं जिनके लिये सुझाव रक्खा गया कि उनमें रैशनलाइ-जेशन किया जाय। यह सुझाव बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैनेजमेंट जो है, उस में कहीं घोटाला हुआ है और उस की तरफ एन्क्वायरी कमेटी का जितना ध्यान जाना चाहिये था उतना नहीं गया, और न सरकार का ही उस की तरफ ध्यान है। इस मैनेजमेंट के घोटाले की तरफ भी अच्छी तरह से ध्यान जाना चाहिये जिससे कि बहुत सा रुपया जो कि न शेअरहोल्डर के पास पहुंच पाता है और न सरकार के पास पहुंच पाता है और

मैनेजमेंट के नाम पर वह सारा रुपया इधर उधर हो जाता है उसको कम करने की कोशिश की जाय । इसलिये जहां तक रैशनलाइज़ेशन का सवाल है, नवीनीकरण का सवाल है, उससे कोई इनकार नहीं करता, रैशनलाइज़ेशन से अगर हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं तो उसे जरूर बढ़ाया जाना चाहिये, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखने की है कि रैशनलाइज़ेशन के नाम पर अगर रिट्रेंचमेंट होता है, छंटनी होती है मजदूरों की, तो उस से आप उस काम को कभी पूरा नहीं कर सकेंगे जो कि उस का उद्देश्य है ।

योजनाएं बनीं । बड़ी आशाएं दिलाई गईं कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो मुल्क के लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी और क्रय शक्ति बढ़ेगी लेकिन जो परिणाम निकल रहा है उसको देख कर आश्चर्य होता है । सन् १९४९-५० में जहां इस देश में प्रति व्यक्ति १५·७५ अर्थात् पौने सोलह गज़ कपड़ा खर्च होता था या उत्पादन होता था, इतना लोग लेते थे वहां सन् १९५७ में जाकर यह सिर्फ १६·८ हो पाया है यानी सिर्फ १ गज से यह कुछ ही ज्यादा बन पाया है । मैं नहीं समझ पाया कि इसका क्या कारण है जब कि हमारे यहां कपड़े का स्टाक भरा पड़ा है । मुझे लगता है कि हमारी इस पंचवर्षीय योजना में कुछ मूलभूत गलतियां हैं । आप यह कहते हैं कि उत्पादन बढ़ने से क्रय शक्ति भी बढ़ेगी लेकिन हम देख रहे हैं कि जनता की क्रय शक्ति घटी ही है उत्पादन भले ही आपका अधिक रहा हो । कपड़ा मिलों में कपड़े की गांठें पड़ी रहती हैं और उनको कोई उठाने वाला नहीं रहता है । १८ अगस्त १९५८ को ३३० मिलियन कपड़ा ऐसा था जो बिका हुआ था लेकिन मिलों से वह उठाया नहीं गया था और क्या इसके यह माने नहीं होते हैं कि मुल्क की जनता की क्रय शक्ति घट रही है और जब क्रय शक्ति जनता की घट रही है तो इस सारे मसले पर विचार करते समय हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर हमारी योजना में कुछ ऐसी मूलभूत गलतियां हैं जिनके कि कारण एक खास छोटे से तबके की तो आमदनी बढ़ रही है और अन्य तमाम लोगों की क्रय शक्ति घट रही है और उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह १६ गज़ कपड़ा भीख रीद सकें । इसलिए हमें जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिये योजना में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे जिससे कि यह योजना आम लोगों की योजना बन सके और आम लोगों की आमदनी बढ़ सके और आमदनी बढ़ा कर ही आज जो यह रिसेसेशन हो रहा है और कपड़े का स्टाक बिना बिका पड़ा हुआ है, वह उठ सकता है । इसलिए जहां हमें कपड़े का काफी मात्रा में निर्यात करने के लिए ध्यान देना चाहिए वहीं निर्यात करने के साथ साथ हमें अपने मुल्क में भी देखना चाहिए कि आज क्या हालत हो गई है कि १६ गज़ और साढ़े १६ गज़ प्रति व्यक्ति कपड़ा पहिनने की बात हो रही है । योजना में कहा गया है कि १८ गज़ एक व्यक्ति को मिल सकेगा और उतना उत्पादन हम कर सकेंगे और अब साढ़े १७ गज़ की बात कही जाय तो इस तरह तो हम और पीछे की ओर हट रहे हैं और पीछे की ओर इसलिए हट रहे हैं क्योंकि जनता की क्रय शक्ति निरन्तर घटती जा रही है । जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

टेक्सटाइल इनक्वायरी कमेटी की बात कही गई है कि गल्ले की कीमत बढ़ रही है । इसलिए लोगों की क्रय शक्ति घट रही है । क्रय शक्ति घटने से कपड़े की खरीद में कमी हो सकती है । गल्ला और कपड़ा दोनों ही चीजें आवश्यक हैं । अब जहां तक गल्ले का सवाल है तो हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे रहते हैं जो कि एक समय और आधा पेट ही भोजन

[श्री ब्रजराज सिंह]

करके रह जाते हैं । दरअसल योजना में कुछ ऐसी मूलभूत गलतियां हैं जिनकी कि वजह से आम जनता की आमदनी घट रही है अलबत्ता एक माइनारिटी १ या डेढ़ फीसदी ऐसी है जिसकी कि आमदनी ज़रूर बढ़ रही है । इस टेक्सटाइल उद्योग को यदि हमें अच्छे तरीके से चलाना है तो हमें पूरे मसले पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए और योजना में जो कुछ मूलभूत गलतियां रह गई हैं उनको सुधारना होगा ताकि लोगों की आमतौर पर आमदनी बढ़ सके और समाजीकरण हो सके और आज जो जनता की क्रय शक्ति घट रही है वह घटे नहीं ।

जहां तक लूम्स और करघों के रेशनलाइज़ेशन और आटोमेटाइज़ेशन का सवाल है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि आज के प्रगतिशील युग में नवीकरण या इस तरह की चीजों से इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन इन सब का भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि कहीं पर भी कोई आदमी जहां भी नवीकरण या रेशनलाइज़ेशन होता है, उसमें अगर हमारे यहां का कोई भी व्यक्ति बेकार होता है तो हमारी योजना का उद्देश्य पूरा नहीं होता है । जहां एक तरफ यह खयाल रक्खे कि नवीकरण भी हो आधुनिकीकरण भी हो वहां साथ ही साथ यह खयाल भी रहे कि कोई भी आदमी बेकार न हो । जब इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख कर हम आगे बढ़ेंगे तभी हम अपने उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे । हमें अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाना चाहिए और दोनों तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए ।

इसी तरह जूट और चाय उद्योग के बारे में भी आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह भी निर्यात के बहुत बड़े उद्योग हैं ।

यह जो डाइवरसिफिकेशन की बात कही जाती है तो उसके लिए मेरा कहना है कि यह डाइवरसिफिकेशन न सिर्फ मुल्कों में हो बल्कि कमोडिटीज़ में हो ताकि नई नई चीज़ें पैदा करके उनका बाहर निर्यात कर सकें और जाहिर है कि जब निर्यात हमारा बढ़ेगा तब विदेशी विनिमय हमें प्राप्त होगा । आज नहीं तो कल हमारा टेक्सटाइल मार्केट खत्म होगा । १०, १५ या २० साल में यह खत्म होगा । इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए कि हम अन्य नई नई चीज़ें अपने देश में तैयार कर सकें और उनको बाहर निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें और व्यवसायिक दृष्टि से हमारा देश अन्य देशों के मुकाबले पिछड़ा हुआ देश न रहे ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : मैंने अपने से पूर्व वक्ताओं के भाषणों को सुना और पाया कि वक्ताओं ने वह सभी कुछ कह दिया है जो मैं कहना चाहता था । परन्तु फिर भी मैं उद्योग मंत्री के विचारार्थ कुछ सुझाव प्रस्तुत करता हूं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने कपड़ा उद्योग तथा चाय उद्योग के विकास के बारे में कुछ कार्यवाहियां की हैं परन्तु फिर भी इनमें और सुधार करने के लिये कुछ कार्यवाहियां की जा सकती हैं ।

भाषण देते समय माननीय मंत्री महोदय ने हर महीने बढ़ते हुये श्रम व्यय के सम्बन्ध म कुछ नहीं कहा । पिछले साल महंगाई भत्ता ६८ रुपये था जो अब ८२ रुपये है । इस समय हमारा कपड़ा उद्योग इस बढ़ते हुये खर्च को सहन नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध में भी हमें कुछ करना चाहिये अन्यथा उद्योग पूर्णतया बन्द हो जायेगा और जो मज़दूर इसमें लगे हुये हैं वह बेरोज़गार हो जायेंगे । इसलिये मज़दूरों के बढ़ते हुये खर्च के बारे में कुछ किया जाना चाहिये ताकि मिल मालिकों को यह

मालूम हो जाये कि उन्हें मज़दूरों को क्या देना है और वे लाभ हानि के हिसाब में उसका ध्यान रख सकें ।

हर महीने बिजली से चलने वाले करघों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनका पंजीयन भी नहीं किया जा रहा है और दूसरी ओर हम स्वचालित करघे लगाने जा रहे हैं । इससे उद्योग को हानि हो रही है मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ ठीक व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे अनधिकृत बिजली के करघों का प्रयोग न किया जाय ।

आजकल हमारे यहां से इंग्लैंड को सादे कपड़े का निर्यात किया जाता है और निर्यात किये गये इस कपड़े को लंकाशायर अथवा मैन्चेस्टर में प्रिंट करके इसका पुनः निर्यात भारत तथा अन्य देशों को होता है । मेरा सुझाव है कि सरकार को वर्तमान कपड़ा मिलों में प्रिंट करने वाली मशीनें लगानी चाहियें जिससे हम खुद ही 'प्रिंटेड' कपड़ा बाहर भेज सकें और विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें ।

हमारा निर्यात व्यापार कम हो गया है । यह निर्यात-शुल्क अधिक बढ़ा दिये जाने के कारण हुआ है । १९५२-५३ में पटसन पर प्रति टन १,५०० पये शुल्क था । इसका प्रभाव यह हुआ कि ईरान, मिस्र, बर्मा, चीन आदि देशों में पटसन की मिलें बना ली गईं । यद्यपि अब हमने निर्यात शुल्क कम कर दिया है परन्तु उस बढ़े हुये शुल्क के कारण ही हम पर बुरा असर हुआ और कई मिलें हमें बन्द कर देनी पड़ीं । यद्यपि चाय पर निर्यात शुल्क कम किया गया है परन्तु फिर भी मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि निर्यात शुल्क पर पुनः विचार करें जिस से भारत के चाय बाग़ानों में और अधिक चाय उगाई जा सके । पूर्वी अफ्रीका, इंडोनेशिया, तथा लंका में चाय पर कोई शुल्क नहीं है । इसलिये अगर हमने भी शुल्क में कमी नहीं की तो हमें उनसे सख्त मुकाबला करना पड़ेगा । मेरा सुझाव है कि साधारण चाय पर से निर्यात शुल्क एकदम उठा लिया जाये ।

श्री डांगे ने पूंजीवादी देशों के बारे में कुछ कहा । मैं मानता हूं कि हमने ग़लतियां की हैं; आखिर ग़लतियां इन्सान से होती हैं । अभी इस्पात के कारखानों पर बहस हुई तो इस्पात मंत्री ने कुछ गलतियां कीं, अगर उन्हें ग़लतियां कहा जाये, ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली । हमारे यहां यदि पहले का मंत्री कोई ग़लती करता है तो नया आने वाला मंत्री उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है जब कि उनके द्वारा इंगित देशों में ग़लती करने वाले मंत्रियों को मार दिया जाता है अथवा उनके पीछे पुलिस लगा दी जाती है । परन्तु हमारे देश में ऐसा नहीं होता । ग़लतियों की ज़िम्मेदारी सभी पर होती है तथा इसीलिये ग़लतियों का पता लग जाने पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है जिससे अधिक हानि न उठानी पड़े । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से कुछ ग़लतियां हुई हैं लेकिन अब वह उन्हें ठीक कर रहा है, उदाहरण के लिये अगर चाय पर शुल्क लगाने के बारे म उचित कार्यवाही नहीं की गई होती तो कछार के कई बागान बन्द हो गये होते ।

संसद् सदस्यों को, जो विदेशों में रुचि रखते हों, या वहां के उद्योगों के बारे में जानना चाहते हों, विदेश भेजा जाना चाहिये जिससे वहां जा कर वह उन देशों के तरीक़ों का अध्ययन कर सकें ।

जब राजा महाराजा तथा अन्य व्यापारियों को विदेशों में जाने के लिये विदेशी मुद्रा मिल सकती है तो क्या संसद् सदस्यों को अध्ययन तथा प्रशिक्षण के लिये विदेशी मुद्रा नहीं दी जा सकती है । मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में भी वह कुछ कार्यवाही करें ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे निर्यात व्यापार में कुछ कमी हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि स्थिति इतनी निराशापूर्ण नहीं जितनी कि कुछ

[श्री अजि : सिंह सरहदी]

लोगों न बताने की कोशिश की है । निर्यात पर विचार कुछ बातों के आधार पर किया जाना चाहिये ; पहली चीज़ है उत्पादन बढ़ाना, दूसरी आन्तरिक खपत में कमी करना, तथा तीसरी निर्यात के लिये नये बाजारों को ढूंढना ।

उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में मेरे विचार से छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है । मोज़े, बनियानों के उद्योग को लीजिये, जो मुख्यतः पंजाब में केन्द्रीकृत हैं । १९५१ में २·१३ करोड़ रुपये के मोज़े, बनियान आदि का निर्यात किया गया । १९५३-५४ में यह कम हो कर १·६७ करोड़ रुपया रह गया । १९५७ में यह केवल ६० लाख रुपये का रह गया । यह केवल सरकार का समर्थन न मिलने के कारण हुआ । वैसे तो यह हमारे निर्यात व्यापार में एक छोटा सा मद है लेकिन हमें इन छोटे मदों को भी उचित महत्व देना चाहिये ।

सीने की मशीन बनाने के उद्योग का भी यही हाल है । पंजाब में कच्चे माल की कमी के कारण तथा प्रमापीकरण में सहायता न मिलने के कारण इस पर बुरा प्रभाव पड़ा है । साइकिल उद्योग के बारे में भी माननीय मंत्री जानते हैं । हमें इन उद्योगों के साथ और अधिक सहानुभूति दिखानी चाहिये ।

कपड़ा उद्योग को लीजिये । पंजाब में रुई का बहुत उत्पादन होता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि जब सरकार स्वचालित करघे लगाने के बारे में विचार ही कर रही है तो पंजाब में सहकारिता के आधार पर इन्हें लगाने का आरम्भ किया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे । जब पंजाब में रुई होती है तो फिर यहां कपड़ा उद्योग को सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहित करना चाहि ` और यहां के लोगों को सिर्फ़ खेती बाड़ी पर ही नहीं निर्भर रहने देना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासन हुए]

माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि कृषि उत्पाद जैसे रुई, तिलहन, तेल, खली मसाले, तम्बाकू तथा फलों का निर्यात इसलिये नहीं किया जा रहा है क्योंकि देश की आन्तरिक मांग बहुत अधिक है । मेरा यही कहना है कि इन वस्तुओं की आन्तरिक खपत पर नियंत्रण करना चाहिये जिससे विदेशी मुद्रा में वृद्धि हो । इसके अतिरिक्त ऐसे प्रयत्न करने चाहियें जिससे हमारे मज़दूर उत्पादन बढ़ा सकें । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी एक पुस्तिका में आंकड़े दे कर यह बताया है कि ब्रिटेन की तुलना में भारतीय मज़दूर बहुत कम उत्पादन करता है ।

मेरा एक और सुझाव है और वह यह कि निर्यात के लिये अन्य देशों को ढूंढने के बारे में सलाहकार संस्थायें बनाई जानी चाहियें जो इस सम्बन्ध में विदेशों का पर्यटन करें ।

†**श्री नंगामणि** : श्री रंगा के अतिरिक्त अन्य किसी सदस्य ने कपड़ा उद्योग के हथकरघा भाग के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है । मैं उसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इस समय देश में २५ लाख हथकरघे हैं जिसमें ७० लाख आदमी लगे हुये हैं । मिलों में हमें बताये गये आंकड़ों के अनुसार ८००,००० मज़दूर काम कर रहे हैं जो १६,००० लाख गज़ कपड़ा बनाते हैं । द्वितीय योजना में २०,००० लाख गज़ कपड़ा हथकरघे से उत्पादन करने का विचार था । भारत बहुत प्राचीन काल से हथकरघे के कपड़े का व्यापार करता रहा है और यह व्यापार यूरोप के देशों मिस्र सुदूर-पूर्व के देशों आदि से होता था । अब बीसवीं शताब्दी में हथकरघे के कपड़े का निर्यात मुख्यतः

†मल अंग्रेज़ी में

मध्य पूर्व, बर्मा, लंका, मलाया और नाइजीरिया को होता है। १९५६ में ९ करोड़ रुपये के कपड़े का निर्यात किया गया जो १९५७ में कम हो कर ५.५ करोड़ रुपये रह गया। बर्मा और लंका को विशेषतः निर्यात कम हो गया है क्योंकि उन देशों ने आयात पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं; हमारी सरकार को चाहिये कि वह इन देशों की सरकारों से बातचीत करके फ़ैसला करे। नाइजीरिया को दक्षिण भारत से लुंगी का निर्यात होता है परन्तु अब अन्य देशों की प्रतिद्वंदिता के कारण लुंगी के निर्यात पर भी नियंत्रण लग गया है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिये। अखिल भारतीय हथकरघा कपड़ा मार्केटिंग सहकारी समिति बम्बई ने जो इस प्रकार के कपड़े के निर्यात का काम करती है जिस पर कपड़े की खपत के नये बाज़ारों के बारे में एक योजना बनाई है हमें विचार करना चाहिये तथा इसके लिये प्रचार करना चाहिये। हमें नये बाज़ारों का पता लगाना चाहिये खास तौर पर जब कि अमरीका और यूरोप के अन्य देशों में इतनी मांग बढ़ती जा रही है। मेरा तो सुझाव है कि इसके लिये एक निर्यात निगम बनाया जाना चाहिये जो विदेशों को निर्यात के सम्बन्ध में एक एजेन्सी के रूप में काम करे। हमें अन्य देशों में भी "शो-रूम" स्थापित करने चाहियें।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा दिये गये संरक्षण के बिना हथकरघे के कपड़े का उद्योग प्रगति नहीं कर सकता। इस संरक्षण को जारी रखना चाहिये। पहले इस पर ९ नये पैसे की छूट दी जाती थी जिसको कम करके ६ नये पैसे कर दिया। एक बार फिर छूट १२ नये पैसे की गई और फिर उसको कम किया गया। मैं यही बताना चाहता हूं कि जैसा कपड़ा जांच समिति ने भी कहा है इस प्रकार बार बार छूट में घटा बढ़ी हमें नहीं करनी चाहिये :

मिल वाले हथकरघे के प्रति सहानुभूति का व्यवहार नहीं करते हैं। उदाहरणतः इस सभा ने एक विधान के द्वारा यह निश्चित किया कि मिलों में रंगीन साड़ियां तथा बोर्डर वाली धोतियां नहीं बनाई जायेंगी। इस पर मिल वालों ने बिना रंग तथा बिना बार्डर वाली धोतियां बनानी शुरू कर दीं जिनको बाद में रंगा जाने लगा और जिन पर बाद में बार्डर लगाया जाने लगा। इस प्रकार कानून से बचने के तरीके निकाल लिये गये हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी।

अब तक जो छूट अथवा रियायत दी गई है वह सहकारी हथकरघों को दी गई है। लेकिन कई सहकारी समितियों में ऐसा गड़बड़ घोटाला हो रहा है कि कुछ झूठमूठ के सौदे किये जाते हैं और सिर्फ छूट लेने के लिये उत्पादन दिखाया जाता है। वहां न तो कपड़ा ही बनता है और न सूत। वह किसी अन्य तरीके से इस छूट का लाभ उठाते हैं। ऐसा विशेष कर मद्रास के रामबाद ज़िले में हो रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस प्रकार की धोखाधड़ी की जांच करें।

इसके अतिरिक्त मिलें भी आधुनिक यंत्र आदि लगाने का बहाना लेकर इसकी मांग कर रही हैं। और उनको जब बम्बई के सिद्धान्त के अनुसार सहायता दी जाती है तो वह मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाते हैं। ऐसे सभी मामले उच्चतम न्यायालय से वापस लिये जाने चाहिएं।

मिलों द्वारा निर्यात किये गये कपड़े के आधार पर उन्हें रंग तथा रसायन आयात करने की अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं। अब नई योजना कृत्रिम रेशम के आयात के बारे में है। कुछ आन्दोलन होने के कारण इसमें संशोधन कर दिया गया है। यद्यपि इसको हथकरघा उद्योग पर भी लागू कर दिया गया है परन्तु कई प्रकार के नियंत्रण होने के कारण इससे उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी स्पीच में शिपिंग का भी जिक्र किया है। किसी भी चीज की एक्सपोर्ट के वास्ते एक तो सस्ता सामान होना चाहिये और दूसरे जो फ्रेट (भाड़ा) है वह भी कम होना चाहिये। अगर फ्रेट कम होगा तो स्वभावतः सामान भी सस्ता होगा। इस सदन में चार पांच बार यह सवाल उठा है कि शिपिंग का जो फ्रेट है उसमें साम्यता नहीं है और इसका नतीजा यह होता है कि भारत का जो सामान बाहर जाता है बहुत मंहगा पड़ता है। इसलिए अगर शिपिंग के फ्रेट में साम्यता होगी तो हमारा सामान बाहर के मुल्कों में सस्ता हो सकता है।

डांगे साहब ने आज वैस्टर्न और ईस्टर्न देशों का जिक्र किया। हमको यह विचार करना चाहिए कि जो हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, उसका क्या कारण है। मैं तो समझता हूं कि इसका कारण बाहर का संघर्ष भी है। संघर्ष किस प्रकार से है यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि पश्चिम के जो राष्ट्र युद्ध में ध्वस्त हो गये थे उनके यहां अब फैक्ट्रियां तैयार हो गई हैं तथा उन फैक्ट्रियों में तथा जापान में भी उत्पादन बहुत अधिक होने लगा है। साथ ही साथ वैस्टर्न कंट्रीस और जापान का जहां मार्किट था वह साउथ ईस्ट एशिया, हिन्दुस्तान और मिडिल ईस्ट में था। अब इन क्षेत्रों में हमारे मित्र देश पैदा हो गये हैं, वैस्ट की जो नेशंस हैं वे भी पैदा हो गई हैं और जो सोशलिस्ट नेशंस हैं जैसा कि डांगे जी ने कहा वे भी पैदा हो गई हैं। सोशलिस्टों को तो इस तरह से फायदा हो गया है कि साउथ ईस्ट एशिया की जो पापुलेशन है उसमें ३० परसेंट पापुलेशन चाइनीस है और उसको ड्यूअल सिटिजनशिप मिली हुई है, मेरा मतलब है कि वहां की और चाइना की सोशलिस्ट देशों में १/३ पापुलेशन चाइनीस है। मैं वहां पर स्वयं गया हूं और छः देशों में घूमा हूं। वहां पर मैंने हिन्दुस्तानियों से बात की है और उनसे पूछा है कि आखिरकार हिन्दुस्तान का जो व्यापार है वह क्यों कम हो रहा है। इसका उत्तर मुझे यह दिया गया कि जो चाइना की एम्बेसीस हैं उनका सम्बन्ध प्रत्येक चाइनीस सिटीजन से होता है। वह एम्बेसी देखती है कि उसके व्यापार की अभिवृद्धि कैसे हो सकती है और अपने लोगों को जितनी सहायता हो सकती है प्रदान करती है। इसके मुकाबले में हमारे हिन्दुस्तान की जो एम्बेसीज हैं उनमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि अगर कोई हिन्दुस्तानी चाहता है कि उसके सामने जो दिक्कत होती है उसको दूर करने में वह उसकी मदद करे, उसकी मदद नहीं होती। वह कहीं पर भी जा करके नहीं कह सकता है कि यह दिक्कत है और इसको दूर किया जाना चाहिये। यही नहीं मैं भी एक एम०पी० की हैसियत से अपनी एम्बेसीस में गया लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वे हम लोगों के साथ भी बात करना नहीं चाहते थे। जब ऐसी बात है तो किस तरह से हमारे व्यापार में वृद्धि हो सकती है।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि साउथ ईस्ट एशिया में अब भी हिन्दुस्तानियों की जो पापुलेशन है वह बहुत अधिक है। मलाया में हिन्दुस्तानियों की पापुलेशन १८ सैंकड़ा है बर्मा में करीब १२ सैंकड़ा है। इसी तरह से जितने भी ये देश हैं वहां हमारे लोगों की काफी पापुलेशन है। अब जो चीन वालों ने किया वह यह किया कि चीन वालों को उन्होंने अपने कानफिडेंस में लिया और उनकी सहायता करके अपने व्यापार को उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ाया। हम लोगों ने वहां रहने वाले हिन्दुस्तानियों को अपने कानफिडेंस में ले करके हिन्दुस्तान के व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं की है। इसका फल यह हुआ है कि हिन्दुस्तान का जो व्यापार है वह खत्म हो गया है और खुद हिन्दुस्तानी लोग,

हिन्दुस्तानी व्यापारी जापान से सामान लेते हैं, चीन वालों से सामान लेते हैं। इन हिन्दुस्तानियों को, इन हिन्दुस्तानी व्यापारियों को वहां पर चीन की एम्बेसी तक से सहूलियत मिलती है, जापान की एम्बेसी तक से सहूलियत प्राप्त होती है, अमेरिकन एम्बेसी से सहूलियत प्राप्त होती है, लेकिन अपने मुल्क की एम्बेसी से सहूलियत प्राप्त नहीं है। लिहाजा साउथ ईस्ट एशिया में कपड़े का जितना भी व्यापार था वह हिन्दुस्तान के हाथ से निकल गया। बर्मा में कपड़े का व्यापार, सिंगापुर में, मलाया में, थाईलैण्ड में, तथा दूसरे देशों में कपड़े का व्यापार हिन्दुस्तानियों के हाथ में आज नहीं है। वह आज चीन के हाथ में चला गया है और हिन्दुस्तानी लोग चीन वालों से, जापान वालों से समझौता करने को बाध्य हो गये और अब वे चीन तथा जापान वालों का सामान ले कर बेचते हैं। हमारा सामान लेकर वे हिन्दुस्तानी लोग अब नहीं बेचते हैं। यह तो आपके साउथ ईस्ट एशिया की बात हुई।

अब मैं अफ़ग़ानिस्तान ईरान इत्यादि मिडिल ईस्ट के कंट्रीस की तरफ आता हूं। इन देशों में ज्यादातर व्यापारी जो हैं वे सिख हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं। अफ़ग़ानिस्तान में आज भी जितना कपड़े का व्यापार है वह हिन्दुस्तानियों के हाथ में है। ईरान में थोड़ा व्यापार हिन्दुस्तानियों के हाथ में है। वहां भी सात आठ महीने हुए मैं गया था। मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या हालत है। उन्होंने कहा कि बाबा हम हिन्दुस्तान से सामान नहीं मंगायेंगे। मैंने उनसे कहा कि क्या बात है, क्यों नहीं मंगाओगे, आप तो हिन्दुस्तान में तीर्थ यात्रा करने आते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि आज से दो बरस पहले हिन्दुस्तान का हम लोग सामान मंगाते थे और हिन्दुस्तान का ही सामान बेचते थे, लेकिन अब वह सामान नहीं मंगायेंगे और इस सामान को न मंगाने के उन्होंने दो कारण दिये। एक तो यह था कि अगर हम मार्कीन के थान या मलमल के थान का आर्डर देते हैं तो उसमें जहां ४० धागा होना चाहियें, वहां पर ३६ धागा दे करके मिल वाले हमें माल भेज देते हैं। मतलब यह कि स्पेसिफिकेशन के अनुसार सामान नहीं भेजा जाता है। जब ऐसी बात है तो क्या कुत्ते ने हमें काटा है कि हम ज्यादा पैसा भी दें और सामान भी घटिया मंगायें? अब ईरान और अफगानिस्तान में व्यापार रूस के हाथ में नहीं गया, वहां का व्यापार जहां तक काटन क्लाथ है, जापान के हाथ में गया है, अमरीका के हाथ में गया है। इसका कारण यह है कि उनका माल स्पेसिफिकेशन के अनुसार आता है। साथ ही साथ वह सामान सस्ता भी होता है। दूसरा कारण यह भी है कि जो ग्राहक है वह उसी दुकान पर जाएगा जहां पर उसको अच्छा सामान प्राप्त होगा और उस दुकान पर नहीं जाएगा जहां उसको अच्छा सामान प्राप्त नहीं होगा। वे कहते थे कि चूंकि उनको ग्राहकों को अच्छा सामान देना होता है इसलिए वे वही माल खरीदते हैं जो अच्छा होता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि अफगानिस्तान और ईरान में भी कपड़े का व्यापार हमारे हाथ से बहुत कुछ निकल गया है। वहां पर जब मैंने एम्बेसेडर साहब से इस बारे में पूछा तो उनसे मुझे कोई तसल्लीबख्श उत्तर नहीं मिला। उनको मालूम ही नहीं था और न उनका कोई सम्पर्क इन लोगों के साथ था। वे यह समझते थे कि ये कोई आजाद आदमी हैं और कोई ताल्लुक इनका हिन्दुस्तान से नहीं है, अपना व्यापार करते हैं। ऐसी सूरत में जब तक आपकी सिम्पथी उनके साथ नहीं होगी, आपकी सहानुभूति उनके साथ नहीं होगी और जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि चूंकि वे हिन्दुस्तानी हैं और हम उनकी मदद करें और जो पालिसी चीन ने अपनाई है, उस पालिसी को हम अपनायें, तब तक हमारा व्यापार नहीं बढ़ सकता है।

अब मैं अपनी कांस्टिट्युएंसी की ओर आता हूं। मेरी कांस्टिट्युएंसी से आठ करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता है एक साल में। सन जिस को कि व्हाइट हैम्प कहते हैं, चार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट

[श्री रघुनाथ सिंह]

होता है और का ान, यानी वूलन कारपेट तीन करोड़ रुपये के होते हैं। साथ ही साथ बनारस सिल्क का जो सामान होता है वह भी करीब एक करोड़ रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता है। इस तरह से करीब करीब आठ करोड़ रुपये का सामान बनारस से एक्सपोर्ट होता है। अब हम भी डिफिकलटी फील कर रहे हैं। ूलन कारपेट आज तक हिन्दुस्तान का सब से सस्ता था लेकिन अब चीनी कारपेट सस्ता पड़ता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जिन देशों में हिन्दुस्तान का कारपेट जाता था आज उन देशों में चीन का कारपेट जाता है।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : डांगे साहब इसको नहीं मानते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो काश्मीर का कारपेट होता है वह पतला होता है। इन कारपेट्स का जो एक्सपोर्ट है वह बहुत ही कम हो गया है। इसका कारण यह है कि अगर हम कहते हैं कि हमको सस्ता वूल मिले, चाहे हिन्दुस्तान से चाहे बाहर से, तो गवर्नमेन्ट इस पालिसी का समर्थन नहीं करती है। वह नहीं चाहती है कि सस्ता रा-मैटीरियल बाहर से ले करके हिन्दुस्तान के व्यापारियों को दे। मैं चाहता हूं कि अपनी इस पालिसी को वह बदले। मैं समझता हूं कि अगर आप हमको सस्ता वूल ले कर के दें, तो कारपेट का जो रोजगार है वह आपको तीन करोड़ से लेकर छः करोड़ तक फारेन एक्सचेंज दे सकता है।

अब मैं सिल्क के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा करीब एक करोड़ रुपये का सिल्क एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इसमें से एक पैसे का सिल्क हमारे हिन्दुस्तान में नहीं बनता। हमको या चीन का और या जापान का सिल्क मिलता है लेकिन आपकी जो पालिसी है उसमें हमको सिल्क मिलने में दिक्कत होती है। मैं कहता हूं कि आप हमें रामैटीरियल दें, आप हमें फारेन सिल्क दें और हम आपको फारेन एक्सचेंज कमा करके दे सकते हैं। हमारा सिल्क अमरीका में जाता है और अमरीका वाले फाइन चीज़ चाहते हैं और जापानी और चाइनीस सिल्क के सामने वे हमारा सिल्क लेना नापसन्द करते हैं। इसलिये आप हमें जापानी और चाइनीस सिल्क दें और हम आपको इतना सामान देंगे कि रुपये से आपका घर भर जाये।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो दो तीन सुझाव मैंने दि े हैं उन पर मंत्री महोदय ध्यान दें और मैं आशा करता हूं कि जैसा कि शास्त्री जी ने शिपिंग में एक नया चैप्टर खोला है, उसी तरह से उद्योग के क्षेत्र में वह भी एक नया चैप्टर खोल देंगे और हमारे देश के व्यापार में काफी वृद्धि होगी।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने निर्यात समस्या के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

†उपाध्यक्ष महोदय : शेष आप कल कहें।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुरुवार, ४ दिसम्बर, १९५८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१४४१—६३
तारांकित प्रश्न संख्या	
५६० मुक्त व्यापार क्षेत्र	१४४१—४३
५६१ अमरीकी लिबर्टी पोत	१४४३
५६२ सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	१४४४–४५
५६३ पाकिस्तान पर बकाया राशि	१४४५–४६
५६५ खाद्यान्नों का आयात	१४४६—४९
५६६ ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल	१४४९–५०
५६७ उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजनायें	१४५०—५२
५६८ सहकारी चीनी कारखाने, आन्ध्र प्रदेश	१४५२—५५
५६९ पश्चिम जर्मनी का कृषि प्रतिनिधि मण्डल	१४५५–५६
५७० सूरत गढ़ यंत्रीकृत फार्म	१४५६—५८
५७१ क्षेत्रीय लघु सिंचाई सम्मेलन	१४५८–५९
५७२ सड़क विकास योजना	१४६०—६२
४७३ कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत के लिये गेहूं	१४६२–६३
५७४ रबी की फसल	१४६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	१४६४—१५०९
तारांकित प्रश्न संख्या	
५६४ हीराकुड बांध परियोजना	१४६४
५७५ आन्ध्र में धान की उपज	१४६४
५७६ ग्राम्य ऋण	१४६४–६५
५७७ टोकियो में खाद्य तथा कृषि संगठन का सम्मेलन	१४६५
५७८ हिण्डन से दिल्ली के लिये जल	१४६५
५७९ त्रिपुरा को रेल से मिलाना	१४६६
५८० पंजाब में चावल का समाहार	१४६६
५८१ मद्रास और केरल का अन्तर्राज्यिक जल विवाद	१४६६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

५८२	खण्ड विकास समितियां	१४६७
५८३	कचार रोड का निर्माण	१४६७
५८४	कोलाघाट के निकट रूपनारायण नदी पर पुल	१४६७
५८५	अमृतकौर पुरी दिल्ली में मकानों का निर्माण	१४६७–६८
५८६	रंगापुर के पास कृष्णा नदी पर पुल	१४६८
५८७	कुल्लू के भूतर पर हवाई पट्टी	१४६८
५८८	असघींय जहाजों का चार दिन का बहिष्कार	१४६८–६९
५८९	गेहूं गवेषणा संस्था	१४६९
५९०	परिवहन सहकारी संस्थायें	१४६९–७०
५९१	चितरंजन में इस्पात का ढलाई घर	१४७०
५९२	डीलक्स गाड़ियां	१४७०
५९३	भारत और भूटान को मिलाने वाली सड़कें	१४७०
५९४	मुकामा पुल से दरभंगा तक बड़ी लाइन	१४७१
५९५	दूध के चूर्ण का कारखाना	१४७१
५९६	अगरतला की रेलवे आउट एजेंसियां	१४७१
५९७	बीकानेर और लालगढ़ के बीच की रेल लाइनें	१४७२
५९८	खण्ड विकास समितियां	१४७२
५९९	मुरादाबाद के निकट राम गंगा नदीं पर पुल	१४७२
६००	पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण, समिति	१४७२–७३
६०१	सड़क परिवहन	१४७३
६०२	वायु परिवहन परिषद्	१४७३
६०३	तेल द्वारा समुद्र को गन्दा किया जाना	१४७३–७४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८८५	भारत में बच्चों के नेत्र रोग	१४७४
८८६.	रेलों में भीड़–भाड़	१४७४–७५
८८७	चितरंजन लोकोमोटिव	१४७५
८८८	गेहूं का स्टाक	१४७६
८८९	नई दिल्लीं की भंगी बस्ती के पीछे गन्दा क्षेत्र	१४७६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

८९०	औद्योगिक निकायों को विद्युत संभरण	१४७६
८९१	भाखड़ा की नहरें	१४७६–७७
८९२	उत्तर रेलवे की माल और एक्सप्रैस गाड़ियों पर भोजन व्यवस्था करने वाले	१४७७
८९३	उड़ीसा में बन	१४७७–७८
८९४	स्थिति क्षेत्र के लिए डाक व्यवस्था	१४७८
८९५	लाहौल क्षेत्र में डाक व्यवस्था	१४७८–७९
८९६	पटसन का उत्पादन	१४७९
८९७	हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिए आयात किया गया इस्पात	१४७९
८९८	सड़क विकास के लिए सहायता	१३८०
८९९	मीन क्षेत्र विस्तार सेवायें	१४८०–८१
९००	केन्द्रीय मीन क्षेत्र प्रौद्योगिकी गवेषणा केन्द्र	१४८१–८२
९०१	सारडीन मछली से तेल निकालना	१४८२
९०२	नल कूप	१४८२–८३
९०३	डाकखानों में चेक प्रणाली	१४८३
९०४	उत्तर प्रदेश में बीज के खेत	१४८३
९०५	उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास	१४८४
९०६	उत्तर प्रदेश में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन	१४८४
९०७	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खरीदी गई गाड़ियां	१४८५
९०८	हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग	१४८५
९०९	रेलवे में पायदान पर यात्रा	१४८५–८६
९१०	दिल्ली में चूहे	१४८६
९११	दिल्ली में असैनिक हवाई अड्डा	१४८६–८७
९१२	सिंचाई परियोजनायें	१४८७
९१३	उड़ीसा में नदियों द्वारा यातायात	१४८७–८८
९१४	कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद्	१४८८–८९
९१५	हिमाचल प्रदेश में उर्वरकों का वितरण	१४८९
९१६	हिमाचल प्रदेश में पशु-पालन व डेनमार्क जैसी दुग्धशाला योजना	१४८९
९१७	दक्षिण रेलवे पर भोजन-व्यवस्था	१४९०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

९१८ चित्तरंजन में प्रोत्साहन देने की योजनायें . १४९०

९१९ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की योजनायें . १४९०

९२० निजाम शुगर फैक्टरी १४९०–९१

९२१ पंजाब में भेड़-पालन और ऊन तैयार करने के काम का विकास १४९१

९२२ सड़क विकास योजनाओं के लिये अनुदान . . १४९१–९२

९२३ केरल को चावल का संभरण १४९२

९२४ रेल की पटरियां पर हथगोले रखने की घटना के बारे में पुलिस की छान बीन १४९२–९३

९२५ तुगलकाबाद—साहिबाबाद लाइन का सर्वेक्षण प्रतिवेदन १४९३

९२६ मोकामा पुल . . . १४९३

९२७ कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न मेमने . . . १४९३

९२८ कलकत्ते की अखिल भारतीय आरोग्यशास्त्र तथा लोक स्वास्थ्य संस्था १४९४

९२९ शीघ्र बढ़ने वाले फलों के वृक्ष . . १४९५

९३० बदरपुर जंकशन पर ऊपरी पुल . . १४९५

९३१ नाविकों में बेरोजगारी . १४९५

९३२ डाकाखानों से लापता राशि . . . १४९६

९३३ मलाबार होटल १४९६

९३४ माल का तस्कर व्यापार १४९६–९७

९३५ जल-संभरण योजना . . . १४९७

९३६ अखिल भारतीय योग स्वास्थ्य विचार गोष्ठी . १४९७

९३७ गैस-संयंत्र . . १४९७–९८

९३८ सामयिक श्रमिक १४९८

९३९ रेलवे कर्मचारियों के लिये सेवा निवृत्ति वेतन योजना १४९८

९४० भारतीय नदी परिवहन समवाय लिमिटेड . . १४९९

९४१ इण्डिया शुगर एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड १४९९

९४२ त्रिपुरा में बेदखली . . १५००

९४३ रास्ते में गुम हुई सम्पत्ति १५००–०१

९४४ हिमाचल प्रदेश में उद्यान विज्ञान का विकास . १५०१

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६४५	दिल्ली में कुक्कुटादि का पालन	१५०२
६४६	भाखड़ा कैचमेण्ट क्षेत्र में भूमि संरक्षण	१५०२-०३
६४७	होम्योपैथिक कालेज . .	१५०३
६४८	मनीपुर में फलों को डिब्बों में बन्द करने की फैक्टरी	१५०३
६४९	भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति . .	१५०४
६५०	गोदी में उतारा गया परन्तु बाद में खोया गया सामान	१५०४
६५१	मछली पकड़ना	१५०४
६५२	सप्ताह में दो बार चलने वाली गलियारे वाली गाड़ियां	१५०४
६५३	पर्यटन कार्यालय .	१५०५
६५४	नये डाक व तार घर खोलना .	१५०५
६५५	रेलवे फैक्टरियों में विदेशी कर्मचारी	१५०५
६५६	उत्तर रेलवे की गाड़ियों का पटरी से उतर जाना	१५०५-०६
६५७	रेलवे सम्पत्ति की चोरियां	१५०६
६५८	अनधिकृत खेती	१५०७
६५९	इम्फाल के सिविल अस्पताल	१५०७
६६०	उत्तर रेलवे की अकबरपुर—टांडा लाइन .	१५०७
६६१	दक्षिण भारतीय रेल में डीजल कोच .	१५०७-०८
६६२	ओड़िहार रेलवे स्टेशन पर ऊपर का पुल	१५०८
६६३	भारत-तिब्बत सड़क .	१५०८
६६४	विमान निगमों में महिला कर्मचारी	१५०८-०९
६६५	दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज . .	१५०९
६६७	कांडला के निकट गांधीधाम का विकास .	१५०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १५०९—११

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये —

(एक) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अंदमान और निकोबार गजट में प्रकाशित, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह मोटर गाड़ी नियम, १९३९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या १२२/५८ की एक प्रति ।

(दो) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(१) पूर्व गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(२) पश्चिम गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) के टाडेपल्लीगुड्म् के कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(३) पश्चिम गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) के थानुकू में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(४) पश्चिम गोदावरी जिल् (आन्ध्र प्रदेश) के निडादवोल में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(५) पश्चिम गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) के चेबरोल में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(६) पश्चिम गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) के एलुरू में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(७) पश्चिम गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) के भीमावरम् में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(८) गुटूर जिले (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के आदेश।

(९) श्री गंगानगर जिले (राजस्थान) के कुछ व्यापारियों को दिये गये चने के अधिग्रहण के आदेश।

(१०) श्री गंगानगर जिले (राजस्थान) के कुछ व्यापारियों को दिये गये चने का भण्डार बताने के आदेश।

(तीन) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(१) जी०एस०आर० संख्या ८३३, दिनांक १९ सितम्बर, १९५८।

(२) मनीपुर खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ अक्तूबर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ८८६।

(३) कलकत्ता गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १५ अक्तूबर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ९७२।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः)

(४) चावल (उत्तरी महाखण्ड) नियंत्रण यातायात आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १५ अक्तूबर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ९७३।

(५) बिहार खाद्यान्न (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १००९।

(६) जी० एस० आर० संख्या १०३०, दिनांक १ नवम्बर, १९५८।

(७) चावल और धान (पश्चिमी बंगाल) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २९ अक्तूबर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०४८।

(८) जी० एस० आर० संख्या १०४९, दिनांक १ नवम्बर, १९५८।

(९) दिनांक १ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या १०५०, जिसमें पश्चिमी बंगाल गेहूं (निर्यात नियंत्रण) आदेश १९५८ दिया गया है।

(१०) दिनांक १ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०५१, जिसमें आयात किये हुए खाद्यान्न (अनधिकृत बिक्री पर रोक) आदेश, १९५८ दिया गया है।

(११) चावल (दक्षिणी महाखण्ड) यातायात नियंत्रण आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०५२।

(१२) दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०८५ जिसमें दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स (आटा नियंत्रण आदेश), १९५८ दिया गया है।

(१३) दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०८६ जिसमें राजस्थान बाजरा (निर्यात पर रोक) आदेश, १९५८ दिया गया है।

(१४) चावल (दक्षिणी महाखण्ड) यातायात नियंत्रण आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १५ नवम्बर १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०८७।

(१५) दिनांक १७ नवम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या १०९० जिसमें चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया गया है।

राज्य-सभा से सन्देश १५११-१२

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित तीन संदेशों की सूचना दीः--

(एक) कि राज्य-सभा ने २ दिसम्बर, १९५८ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १७ नवम्बर, १९५८ को पारित किये गये

विषय पृष्ठ

राज्य-सभा से सन्देश—(क्रमशः)

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक १९५८ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(दो) कि राज्य-सभा ने २ दिसम्बर, १९५८ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १९ नवम्बर १९५८ को पारित किये गये विष (संशोधन) विधेयक १९५८ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(तीन) कि राज्य-सभा ने २७ नवम्बर, १९५८ की अपनी बैठक में कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पारित कर दिया है।

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया . १५१२

सचिव ने कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८, को राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा-पटल पर रखा।

याचिका का उपस्थापन १५१२

श्री दशरथ देब ने त्रिपुरा के २६५३ बिस्थापित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका जो, उनसे ऋणों की वसूली के बारे में थी, उपस्थापित की।

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव . . १५१२—४६

भारत के निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति संबंधी प्रस्ताव पर और आगे चर्चा।
निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उनका पारित किया जाना :—

(१) हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक, १९५८।

(२) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक।

श्री नौशीर भरूचा, के सैनिक व्यय के वर्तमान ढांचे की जांच आदि के बारे में तथा श्री पाणिग्रही के भूमि सुधार के मामले की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर भी चर्चा।